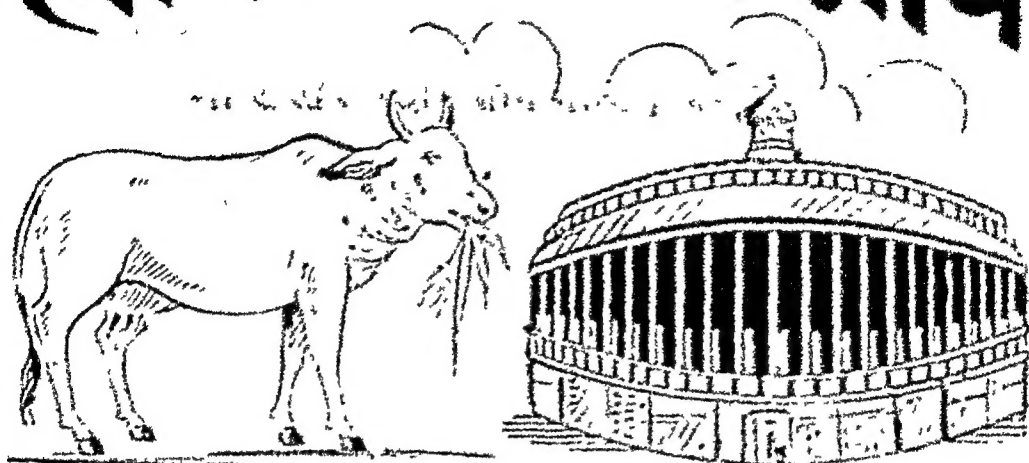


लोक सभा में गाय



श्री सरस्वतीजीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

दांतों तले तृण दबाकर हैं दीन गायें कह रही,
हम पशु तथा तुम मनुज, पर योग्य क्या तुम को यही ?
जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का,
तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का ।
जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पायेगी,
यह स्वर्ण भारत भूमि वस, मरघट मही बन जायेगी ।
(सैथिलीशरण गुप्त कांग्रेसी संसद सदस्य)

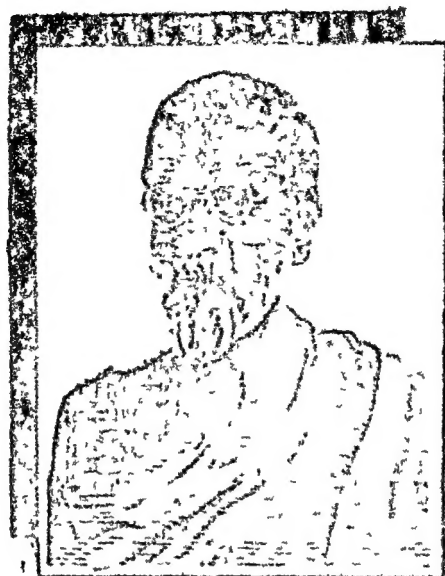
संग्रहकर्ता
हरदेव सहाय

प्रथम बार
२ हजार

जन्माष्टमी
१९५५

मूल्य
दस आना

मेठ गोविन्द दास जी के
 "भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक १९५२" पर
 सन्त विनोबा के विचार



श्री हरदेवसहाय,

विधेयक देखा, उसमें कैटल की व्याख्या में He and She-buffalo का समावेश किया है, वह गोरक्षण के आदेश के बाहर जाना है, मेरा ख्याल है अभी हम गाय, बैल और उनकी बच्छी और बच्छे तक सीमित रहें यह अच्छा है गो जाति के बारे में उपयोगी अनुपयोगी यह विभाग हमारी संस्कृति ने नहीं किया। यह बात भी हम पूरी अमल में नहीं ला रहे हैं, उतने में निरुपयोगी भैंसा भी बचाने की कोशिश कहां तक सफल होगी ? यह चिंतनीय विषय है। इतनी बात छोड़कर बिल के उद्देश्य के साथ मेरी सहानुभूति जाहिर है।

नैशनल हाल, पटना-३

विनोबा के प्रणाम.

६ दिसम्बर १९५३

सन्देश

भारतीय लोक-
सभा में नेट
मोविन्ददासजी के
गोरक्षा सम्बन्धी
विधेयक की चर्चा
नौ समाचार पत्रों
में चर्चत रही है।
समाचार पत्रों
को पढ़ते वाले
पाठकों को यह
भी विधि ही है
कि विधेयक की
आवश्यकता तथा
उस पर किसे
आशोपों का युक्ति-
युक्त उत्तर सुन
कर जब सरकार
की ओर ने कुछ



भी उत्तर नहीं बन पड़ा तब नियम विच्छेद, धर्म विच्छेद, सदानार विच्छेद
तथा परस्पर विच्छेद अनुमानन प्रचारित किया गया श्रीर नेहरूजी ने
अपना त्यागपत्र देने का अमोघ गाँधीय अस्त्र भी निकाला। उस दिन
नेहरूजी बोलना उठे और उनके वचन कितने असंख्य तथा परस्पर में
विच्छेद थे, इन सब बातों को पाठक इस पुस्तक में विस्तार सहित पढ़ेंगे।

समाचार पत्रों में न तो पूरे भाषण ही छपते हैं न विधेयक की पूरी जानकारी ही कराई जाती है। यह विधेयक और इसपर हुआ वाद-विवाद ऐतिहासिक है। पाठक इस विधेयक के इतिहास को और इसपर लोकसभा में हुए विवाद को पढ़ कर समझ सकेंगे कि किस प्रकार नेहरू जी ने आवश्यक विधेयक की, गौमाता की तथा धर्म, सदाचार तर्क प्राचीन परम्परा की हत्या की है। किस प्रकार अनुशासन करने पर भी कितने कांग्रेसियों ने उसकी अवहेलना की है और किन्होंने उसके विरुद्ध मत दिए थे। इस पुस्तक से कांग्रेसी सरकार की गौ सम्बन्धी नीति का नग्न-चित्र दिखायी पड़ेगा।

मेरी पाठक पाठकाओं से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक को पढ़ें और तब निश्चय करे कि हमें इस गोहत्या की पक्षपातिनी सरकार के प्रति क्या करना चाहिये। अन्त में परमपिता परमात्मा के पाद-पद्मों में मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि भारत में सर्वथा गोवध बन्द हो तथा सम्पूर्ण देश में दूध दही की नदियां बहें। भारत शीघ्र से शीघ्र गोहत्या के कलंक से मुक्त हो सके।

संकीर्तन भवन,
भूखी (प्रयाग)

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी
प्रधान,
अ० भा० गोहत्या निरोध समिति
३ सदर थाना रोड,
दिल्ली-६

भूमिका

स्वराज्य के बाद सर्वप्रथम पं० ठाकुरदास जी भार्गव ने केन्द्रीय एसेम्बली में केवल मात्र दिल्ली, अजमेर आदि 'क' भाग के राज्यों में उपयोगी पशुओं का बच बन्द करने का विधेयक उपस्थित किया, पर सरकार की कुटिल नीति के कारण यह विधेयक भी पास नहीं हो सका। सरकार ने आग्रामन दिया पर किसी भी प्रान्त में ठोस कानून नहीं बना। संसार के किसी भी देश में उपयोगी पशुओं की हत्या नहीं होती और न ही कसाईखानों के बाहर मन मानी गोहत्या की जा सकती है। पर भारत के बम्बई, बंगाल, मद्रास इत्यादि प्रायः प्रान्तों में कसाई को अधिक लाभ होने के कारण प्रायः करके उपयोगी पशु ही कत्तल किये जाते हैं। कसाईखानों से बाहर नित्य हजारों गाय बैल ही नहीं छोटे-छोटे बछड़े बछड़ियों को भी हत्या होती है। इससे यह सिद्ध है कि सरकार उपयोगी पशुओं को भी बचाना नहीं चाहती।

कांग्रेसी सरकार की तानाशाही

महा कोशल राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष तथा लोकसभा के कांग्रेसी सदस्य श्री सेठ गोविन्ददास जी ने १६ जुलाई १९५२ को लोकसभा में "भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक" उपस्थित किया। जिसका उद्देश्य सब गोवंश तथा भैंस वंश को कत्तल से बचाना रखना। १६ जुलाई १९५२ को उपस्थित करने के साधारण भाषण के बाद यह विधेयक २७ नवम्बर १९५३ को पुनः उपस्थित हुआ। सेठ गोविन्ददास जी ने इस दिन के भाषण में जो लोग गोरक्षा आन्दोलन को रूढ़ी-वादी और साम्प्रदायिक बतलाते हैं उनके आक्षेपों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया। ११ दिसम्बर १९५२ को सेठ जी ने महात्मा गांधीजी, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी तथा संत विनोबा भावे जी के भाषणों के उद्धरण, भारतीय विधान, सरकारी

विशेषज्ञों की सम्मति, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के आधार पर गो-हत्या निषेध के पक्ष को उपस्थित किया तथा सरकारी तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार बतलाया कि आज भारत में अंग्रेजी राज्य से अधिक गोहत्या होती है तथा प्रायः उपयोगी गोवंश ही कतल किया जाता है। श्री नेहरू जी ने २४ सितम्बर १९५३ को कृषि मंत्रियों के सम्मुख गोहत्या जारी रखने के पक्ष में जो भाषण दिया उसका उत्तर देते हुए सेठ गोविन्ददास जी ने कहा कि नेहरू जी गौ के मामले में कोई विशेषज्ञ नहीं। लोकसभा के अन्य कांग्रेसी सदस्यों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। खाद्य मंत्री स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई ने अपने पटने के भाषण में गोहत्या निरोध का जो समर्थन किया था उसे पुनः लोकसभा में दोहराया। २६ फरवरी १९५४ को यह विधेयक फिर लोकसभा में उपस्थित हुआ। सरकार के पास इस विधेयक के विरुद्ध कोई दलील नहीं थी। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जब यह अनुभव किया कि सम्भव है सम्मति लेने पर विधेयक पास हो जाय तब उन्होंने कांग्रेस पक्ष के लोकसभा के सदस्यों को गुप्त रूप से सदन छोड़ने का आदेश दिया। कितने ही कांग्रेसी सदस्य सदन छोड़ गये। कोरम पूरा नहीं रहा। विधेयक की कारवाई आगे नहीं बढ़ी और न ही मत लिए जा सके। संसार के किसी भी स्वतन्त्र देश में राज्य चलाने वाली पार्टी ने आज तक कोरम को समाप्त करने के लिए सदन को नहीं छोड़ा। लोकसभा के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये जनता द्वारा दिये गये टैक्स के रूपों में से अनुमान एक हजार रुपये मासिक मिलते हैं। अतः लोकसभा के सदस्यों के लिए कोरम समाप्त करने के लिये सदन को छोड़ना नैतिक दोष है। जो कांग्रेस के लिये लज्जा का विषय है। जब सरकार इस विधेयक के विरुद्ध कोई दलील न दे सकी तो १ मई १९५४ को एटर्नी जनरल से यह सम्मति दिलवाई गई कि गोरक्षा विषय पर लोकसभा में विचार नहीं हो सकता, यह तो राज्यों का कार्य है। यदि सरकार वास्तव में गोरक्षा के विषय को राज्यों के आधीन ही समझती थी तो उसे चाहिये था कि आरम्भ में १६

जुलाई को ही जिस दिन यह विधेयक सर्वप्रथम उपस्थित हुआ एटर्नी जनरल को बुलाकर सम्मति दिला देती २७ नवम्बर, ११ दिसम्बर १९५३, २६ फरवरी, १२ मार्च १९५४ चार दिनों का जो समय लगा, हजारों रुपए देश के बर्बाद हुए वे न लगते। एटर्नी जनरल का वक्तव्य सरकारी कार्यों के दिन दिया गया। कुछ सदस्यों ने इसे चुनौती दी। उचित था कि सरकार एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस नीयत करती। पर सरकार ने एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस को समय नहीं दिया। संसार के किसी भी जनतांत्रिक देश की लोकसभा में सरकार से विरुद्ध मत रखने वाले लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाता, जैसा कि एटर्नी जनरल का उत्तर देने के मामले में भारत सरकार ने किया।

२१ मई १९५४ को भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख ने एक अनुचित, असामयिक तथा नश्यहीन वक्तव्य जनता को भ्रम में डालने के लिए दिया। सरकारी पशु गणना के अनुसार देश में बृद्ध तथा अर्पण गोवंश की संख्या ३८ लाख है। पर कृषि मंत्री महोदय ने जनता में भय उत्पन्न करने के लिए यह संख्या टेढ़े-करोड़ में साढ़े चार करोड़ तक बतलाई।

कलकत्ता बम्बई की दूध सूखी गायों को बचाने के लिए सरकारी तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद जी की अध्यक्षता में बनी गोरोवा सच की कमेटी ने निर्णय दे दिये थे। फूका कानून, पशुओं के अंतर्प्रान्तीय निर्यात आदि के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विचार हो चुका था। इस कमेटी की कोई आवश्यकता न थी, पर जैसा कि इस कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सरकार ने पहले की तरह सरकारी गैर सरकारी लोगों की नहीं मनमानी रिपोर्ट कराने के लिए अपने नौकरों की कमेटी बनाई। इस कमेटी को गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करने या न करने तथा विधान की धारा ४८ का स्पष्टीकरण करने का अधिकार नहीं दिया था पर फिर भी इस कमेटी ने सरकार की नीति का समर्थन करने के लिए अनुचित तौर पर

विधान की धारा ४८ के अर्थ का अर्थ करते हुए सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करने की सम्मति देने की अनाधिकार चेष्टा की। केन्द्रीय सरकार की सरकारी स्तर पर बनी गोरक्षा उन्नति समिति १९४७-४८ तथा उत्तर प्रदेश सरकार की गोसम्बर्धन जांच कमेटी इन दोनों ने सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का समर्थन किया। कृषि मंत्री महोदय द्वारा बनाई समिति के अध्यक्ष श्री प्राणनाथ नन्दा जिन्होंने सन् १९४७-४८ की केन्द्रीय सरकार की कमेटी के सम्पूर्ण गोहत्या निषेध के सुभाव पर एक सदस्य की हैसियत से हस्ताक्षर किए थे। सरकार की कुदृष्टि के कारण उन्हें भी सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करना पड़ा।

सरकार ने एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस में समय नहीं दिया। २ अप्रैल सन् १९५५ को गैर सरकारी दिवस को पुनः यह विधेयक लोक सभा में उपस्थित हुआ। प्रसिद्ध कानूनी विरोधक पं० ठाकुरदास जी भार्गव तथा श्री एन० सी० चटर्जी ने विधान और कानून के आधार पर तथा अकाट्य तर्कों से यह सिद्ध किया कि गोहत्या निषेध का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है और न्याय को दृष्टि में रखते हुये लोकसभा ने ही इस विधेयक पर विचार होना चाहिये। पं० ठाकुरदास जी भार्गव ने तो यहां तक कहा कि "यह हमारा दुर्भाग्य होगा यदि सरकार लोक सभा के सदस्यों के सन्मुख वैधानिक प्रश्न को लेकर कहे कि यह सदन वास्तव में इस योग्य है या नहीं? यदि आप जनमत को नहीं मानते, जनता के विरुद्ध चलते हैं तो यही कहा जायेगा कि देश को सन्तुष्ट नहीं कर सके।"

२ अप्रैल १९५५ को लोकसभा में एटर्नी जनरल तथा कृषि मंत्री महोदय दोनों उपस्थित थे। उचित था कि कृषि मंत्री महोदय, सेठ गोविन्ददास जी ने अपने भाषण में गोहत्या निषेध के पक्ष में जो तथ्य वर्णन किये उनका उत्तर देते, तथा एटर्नी जनरल महोदय श्री भार्गव जी तथा श्री चटर्जी की कानूनी चुनौती को स्वीकार करते। पर दोनों के

पास कोई ठोस तर्क इस विधेयक के विरुद्ध नहीं था। लोकसभा के सदस्यों तथा जनता को संतुष्ट करने के लिए कृपि मन्त्री महोदय तथा एटर्नी जनरल महोदय न्याय पूर्ण उत्तर देने में असमर्थ थे। उनके पास कोई न्यायपूर्ण तर्क गोहत्या को जारी रखने या लोकसभा में विचार न करके राज्य ही निर्णय कर सकते हैं, इसके समर्थन में कोई औचित्य न था। अतः जनतन्त्र के नाम में चलने वाली सरकार ने न्याय तथा सत्य की हत्या तथा जनतांत्रिक सिद्धान्तों की अवहेलना करके इस विधेयक को असफल करने के लिये तानाशाही या अधिनायकवाद के मार्ग को अपनाया।

श्री नेहरू जी की धमकी

गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री सन्त विनोबा भावे ने सन् १९५१ के सर्वोदय पत्र में लिखा है कि गोहत्या निर्पेक्ष जनता का भेद या लोकाज्ज्ञा है। प्रधान मन्त्री महोदय को इसका पालन करना चाहिये। श्री विनोबा जी ने इस विधेयक का समर्थन भी किया है। उचित था सरकार गोहत्या को बन्द कर देती या इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करती। पर लोकसभा, कांग्रेस पक्ष के नेता पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी इस विधेयक पर विचार नहीं करवाया। कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया। फिर भी श्री नेहरू जी ने लोकसभा के सदस्यों को विचार करने का समय न देकर सचेतक जारी करा दिया कि कांग्रेसी सदस्य सेठ गोविन्ददास जी के विधेयक के विरुद्ध मत दें। पर श्री नेहरू जी को यह विश्वास नहीं रहा कि कांग्रेसी सदस्य भी उनके सचेतक का पालन करेंगे। लोकसभा से इस विधेयक पर उनका वक्तव्य देने का कार्यक्रम भी नहीं था। फिर भी इस विधेयक को असफल बनाने के लिए लोकसभा में पधारे। लोकसभा के सदस्यों के मत अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए इस विधेयक के विरुद्ध कोई ठोस दलील न देकर सदस्यों के मत विधेयक के विरुद्ध प्राप्त करने के लिए त्याग-पत्र देने की धमकी

दी। इस पर ११ सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में तथा ९५ ने विधेयक के विपक्ष में मत दिये। लोकसभा के सदस्यों की संख्या ४६६ है। २ अप्रैल को जिस दिन यह विधेयक उपस्थित हुआ ३१८ सदस्य उपस्थित थे। इनमें से कांग्रेस के पदा के २४६ तथा ७२ अन्य पदा के थे। जिन सदस्यों ने इस विधेयक के विपक्ष में मत नहीं दिये 'मौन रविकृति लक्षणम्' के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुये उन्होंने इस विधेयक का विरोध नहीं समर्थन ही किया। अर्थात् उपस्थित सदस्यों में से ६५ ने ही विधेयक के विरुद्ध मत दिए, शेष विरोधी नहीं थे। अतः आन्तरिक तथा तात्त्विक दृष्टि से यह विधेयक पास समझना चाहिये। २ अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष के २४६ सदस्य उपस्थित थे। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सैठ गोविन्द दास, पं० ठाकुर दास भागवत, श्री मुल्लन सिन्हा, श्री मूलचन्द जी दुवे, श्री उदयशंकर जी दुवे कांग्रेस पदा के इन सदस्यों ने तो श्री नेहरू के त्याग-पत्र देने की धमकी देने पर भी स्पष्ट तौर पर विधेयक के पक्ष में मत दिये। कांग्रेस पक्ष के १५३ उपस्थित सदस्य सचेतक तथा श्री नेहरू जी के त्याग-पत्र की धमकी देने पर भी मौन रहे। एक प्रकार से इन सदस्यों ने विधेयक का विरोध नहीं किया। अतः कांग्रेस पार्टी के भी १५६ सदस्य विधेयक के पक्ष में और ६५ विपक्ष में थे। उपस्थित लोक सभा के सब ३१८ सदस्यों में से ६५ विरुद्ध तथा शेष २२३ पक्ष में या मौन रहे। जिन सदस्यों ने नेहरू जी के त्याग-पत्र की धमकी देने पर मत दिये हैं उनमें कितने ही ऐसे हैं जो गोहत्या निषेध चाहते हैं पर केवलमात्र नेहरू जी के प्रभान में आकर गोहत्या जारी रखने के पक्ष में मत दिये। अतः इन मतों को स्वतन्त्र नहीं समझना चाहिये। जो सदस्य अपने क्षेत्र के मत दाताओं या अपनी आत्मा के अनुसार मत नहीं देते वे अपने तथा राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं। प्रसिद्ध गांधीवादी स्वर्गीय किशोरलाल जी मशरूवाला ने बनस्पति निषेध के विधेयक पर जब श्री नेहरू जी के भय से कांग्रेसी सदस्य मौन रहे तब जिन सदस्यों ने अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य किया तो जनवरी १९५१ के 'हरिजन' पत्र में

उनकी भत्सना की थी तथा श्री नेहरू जी के रवैये को खेद-जनक बतलाया । संसार के सर्वप्रथम विधान निर्माता भगवान मनु ने कहा है ।

“सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम् ।

अत्रु वन् वित्रु वन् वाऽपि नरो भवति क्लित्विपी ॥”

अध्याय ८, श्लोक १३

अर्थात् सभा में आओ नहीं, आओ तो उचित बात ही कहो । मौन रहने या विपरीत करने वाला पापी होता है ।

राज्य सरकारों के अधिकारों का बहाना क्यों ?

श्री चटर्जी तथा श्री भार्गव जी जैसे प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञों ने सर्व-पूर्ण कानूनी तथ्यों से सिद्ध कर दिया कि गोहत्या-निषेध का विषय केन्द्रीय सरकार तथा लोकसभा के अधिकार का है । यह स्पष्ट है कि भारत सरकार सर्वत्र से इस विषय को अपने आधीन मानते हुए अमल करती रही । भारत-सरकार ने १६ नवम्बर १९४७ को गोरक्षा के विषय पर सगति बनाई । २४ मार्च १९४९ को उस समय के वाय तथा कृषि मंत्री श्री जयरामदास दीलतगाम ने भारत सरकार की ओर से उन दिनों केन्द्रीय ऐसेम्बली में इस समिति के प्रायः नृभाषों को स्वीकार कर लिया तथा राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए आदेश जारी किये । २० दिसम्बर १९५० को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक गुप्त पत्र द्वारा गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द न करने की आज्ञा दी । पर चुनाव में जनता के मत प्राप्त करने के लिए १५ जीलाई सन् १९५१ को कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र पर विचार करते हुए श्री नेहरू जी ने कहा कि गोहत्या निषेध का विषय राज्य-सरकारों से सम्बन्ध रखता है वे जैसा उचित चाहे कर सकती हैं । चुनाव के बाद २४ सितम्बर १९५३ को श्री नेहरू जी ने राज्य कृषि मंत्रियों के समक्ष दिल्ली में सम्पूर्ण गोहत्या बन्द न करने की बात कही । गत जन्माष्टमी २१ अगस्त १९५४ को गोहत्या निरोध सत्याग्रह आरम्भ होने वाला था । राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को गोहत्या बन्द करने या न

करने का अधिकार नहीं। फिर भी श्री नेहरू जी ने वैधानिक आपत्ति से बचने के लिए २० अगस्त १९५४ को कांग्रेस प्रधान की हेतियत से राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को गोहत्या निषेध आन्दोलन को राजनैतिक तथा धर्म की आड़ में चलने वाला आन्दोलन बतला कर विरोध करने का सकेत किया। श्री नेहरू जी ने लोकसभा में प्रथम वाक्य में यह कहकर कि यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है, दूसरे वाक्य में कह दिया कि मेरा परामर्श राज्य सरकारों को भी यही होगा कि वे ऐसे विधेयक उपस्थित या पास न करें। श्री नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के विधेयक को गलत बतलाया तथा बम्बई सरकार के ऐसा कदम उठाने से इन्कार करने का समर्थन किया। श्री नेहरू जी विशेषज्ञों की गम्भीरता प्राप्त होने तथा विधान का नियम बनने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गोहत्या निषेध विधेयक बनाने को तैयार नहीं और न ही राज्य सरकारों को अजमेर, मथुरा, पंजाब आदि की तरह जब तक जनता उन्हें वाक्य नहीं करे आसानी से कानून बना देते हैं। एक प्रकार से श्री नेहरू जी अवैधानिक तौर पर गोहत्या को जारी रखना चाहते हैं। श्री नेहरू जी ने गोहत्या विधेयक के विरुद्ध जो तर्क दिये उनका सप्रमाण उत्तर परिशिष्ट में दिया गया है। श्री नेहरू जी ने श्री टंडन जी के पत्र के उत्तर में गोरक्षा के पक्ष में जो टालमटोल की बातें लिखीं वह केवल-मात्र जनता में भ्रम फैलाने के लिए ही हैं। वास्तव में श्री नेहरू जी और उनकी सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के गोवंश को नष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप अच्छी नसल के उपयोगी गोवंश को कतल द्वारा नष्ट किया ही जा रहा है, गोचर भूमियों को तोड़ना, बनस्पति घी, रासायनिक खाद को प्रोत्साहन देना भी गोवंश के लिए हानिकारक नहीं।

श्री नेहरू जी त्यागपत्र देने तक तैयार क्यों ?

जिस भारत के सम्राट् दिलीप एक गाय की रक्षा करने के लिये भी अपना शरीर देने तक तैयार हुये थे, जिस दिल्ली नरेश पृथ्वीराज ने गोरक्षा के लिये अपने राज्य तथा शरीर तक को त्याग दिया, जिस दिल्ली में गुरु तेग बहादुर ने गो ब्राह्मण रक्षार्थ अपना सीरा कटवाया, जिस दिल्ली में मुगल बादशाहों ने गोहत्या के हाथ कटवाने या गोली से मार देने की आज्ञा दी, जिस दिल्ली में सन् १८२१ की गोपाण्टमी को महात्मा गांधी जी पं० मोतीलाल जी नेहरू की उपस्थिति में उनकी आज्ञा ने गोहत्या जारी रखने के कारण अंग्रेजी सरकार ने अमहयोग करने के प्रस्ताव को पास किया, उन्ही दिल्ली में भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी सब परम्पराओं, करोड़ों लोगों की वार्षिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं, सरकारी विशेषज्ञों की सम्मति और अपने बनाये विधान को ठुकरा कर गोहत्या जारी रखने के लिये त्याग-पत्र तक देने को तैयार होते हैं। यह राष्ट्र के दुर्भाग्य का विषय है। श्री नेहरू ने २ अप्रैल १९५५ को इस विधेयक को असफल बनाने के लिये जो वक्तव्य दिया उसके पढ़ने से मालूम होगा कि श्री नेहरू जी वक्तव्य देते समय अपने आत्म-सन्तुलन को न रख सके तथा क्रोध और आवेग में जाकर भाषण दिया। उस भाषण में एक बार कहा एटर्नी जनरल के मतानुसार यह विषय राज्य सरकारों का है, दूसरे ही वाक्य में कह दिया कि राज्य सरकार भी कानून न बनावे। कुछ वाक्यों के बाद ही कहा कि मैं प्रधान-मन्त्री पद से त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। आवेग में आकर गोहत्या-निषेध आन्दोलन को जो इन दिनों जनसंघ, हिन्दू-महानभा, रामराज्य परिषद्, आर्य समाज तथा कितने ही मान्य कांग्रेसियों द्वारा चलाया जा रहा है उसे व्यर्थ, बुद्धिहीनता तथा हास्यास्पद बतलाया। भारत का प्रधान-मन्त्री अपना आत्म-सन्तुलन खो दे, आवेग में आकर दूसरों को अपमानित करने वाले सम्बोधन करे यह राष्ट्र और प्रधान मन्त्री दोनों के लिये शोभनीय नहीं,

लज्जास्पद है ।

श्री नेहरू जी के चुनाव क्षेत्र में १६ दिसम्बर १९५३ को गोहत्या निषेध विषय को लेकर मत संग्रह आरम्भ हुआ । एन्ही दिनों श्रीमती पूज्य बहिन इन्दिरा गांधी तथा कुमारी गुरुदा मारान्दा ने मदल बन इस क्षेत्र का दौरा करके गोहत्या नहीं होती कहकर जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की । यहां के मतदाता उनके भ्रम में नहीं पड़े । मौनी प्रभावस्था ३ फरवरी १९५४ को नेहरू जी के चुनाव क्षेत्र के दो लाख ४८ हजार ४२२ या बहु संख्यक मत दाताओं ने (श्री नेहरू जी को चुनाव में दो लाख तैतीस हजार मत प्राप्त हुये) यह घोषणा की थी कि हम आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हर प्रकार से गोहत्या पर रोक लगाना चाहते हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं आपसे हम संसद में इसके लिये प्रस्तुत विधेयक (बिल) का पूरा-पूरा समर्थन करने का लोकतन्त्रीय पद्धति के अनुसार आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रकार से गौ कटवाने का समर्थन करने वाला हमारा प्रतिनिधि नहीं बन सकता उचित था श्री नेहरू जी अपने मत दाताओं की भावना तथा आदेश का पालन करते हुये इस विधेयक का समर्थन करते या त्याग-पत्र दे देते ।

यह ठीक है कि भारत के विधान और कानून के अनुसार नेहरू जी के मतदाता त्यागपत्र देने के लिये उन्हें बाध्य नहीं कर सकते । पर नेहरू जी का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने मत दाताओं की सम्मति के अनुसार गोहत्या बन्द करे या त्याग-पत्र दे दें । धमकी देने की आवश्यकता नहीं थी । लोकसभा में त्यागपत्र की धमकी देना अपने मतदाताओं की अवहेलना करना है । यह केवल-मात्र लोकसभा के सदस्यों को विधेयक के विरुद्ध मत देने के लिये प्रभावित किया गया ।

श्री नेहरू जी गोहत्या के पक्षपाती क्यों ?

प्रश्न होता है कि श्री नेहरू जी गोहत्या को क्यों बन्द नहीं करना चाहते ?

१—गोहत्यारों और गोमांस आदि के व्यापारियों को आज भी गोहत्या से अनुमान १० करोड़ रुपये का लाभ पहुँचता है। श्री नेहरू जी राष्ट्र की अपेक्षा गोहत्यारों के लाभ को अधिक महत्व देते हैं।

२—कतल किये हुये भारतीय गोवंश की खाले, मांस, आन्ते, जिह्वा जिगर इत्यादि संसार भर में अच्छी समझी जाती हैं। और इन चीजों की संसार के प्रायः देशों में मांग है। श्री नेहरू अपनी अन्तर्गम्य स्थािति अधिक बढ़ाने के लिये इस निर्यात और कतल को बन्द करना नहीं चाहते।

३—गौ हिन्दू-धर्म की मान बिन्दू है श्री नेहरू जी हिन्दू-धर्म के मान बिन्दुओं को समाप्त करके हिन्दुओं के हृदय में धार्मिक भावना को समाप्त करके देश में हिन्दू-धर्म विरोधी साम्यवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। गोहत्या जारी रखना और हिन्दू कोड विन का पास करना दोनों ही इसके उदाहरण हैं।

जनता से

मैठ गोविन्ददास जी के विधेयक पर लोकसभा में जो कार्यवाही तथा भाषण आदि हुये तथा मत-संग्रह हुआ वे सब जनता की जानकारी के लिये उपस्थित किये जाते हैं। कोई भी निष्पक्ष महानुभाव इस पुस्तक के पढ़ने में इस निश्चय पर पहुँचेगा कि श्री नेहरू जी के पान गोहत्या जारी रखने के लिये कोई ठोस तर्क नहीं तथा वर्तमान सरकार विरोधों की सम्मति तथा विधान का नियम होने पर भी गोवंश को नष्ट करने पर तुली हुई है। यह भी सिद्ध है कि आज देश में जनतान्त्रिक नहीं जनतन्त्रता के नाम से तानाशाही सरकार चल रही है। जनतन्त्र तथा

तानाशाही दोनों ही परस्पर विरोधी हैं पर हमारे देश में जनता के दिखाने के लिये जनतन्त्र तथा सब कार्यों के निर्णाय और अमल के लिये तानाशाही राज्य है। यह जनतन्त्र और तानाशाही के अपवित्र गठबंधन का एक नमूना है जो राष्ट्र के लिये अनिष्ट और विनाशकारी पतन की ओर लेजाने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भारतीय राष्ट्र हितैषी सज्जन का कर्तव्य हो जाता है कि वह जनतन्त्र की सफलता तथा तानाशाही भावना की समाप्ति के लिये भी गोहत्या वन्द कराने के लिये सर्वात्मना यत्नशील हों।

दिल्ली

२५ जुलाई १९५५

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक

१६ जुलाई १९५२

Indian Cattle Preservation Bill

सेठ गोविन्ददास—(मंडला जयलपुर दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे अपने पशुवन रक्षा सम्बन्धी विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय ।

कानून मंत्री—(श्री विश्वास) मैं सदन का बतला देना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक को उपस्थित करने के विरोध में नहीं हूँ, परन्तु मैं इसे केवल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ... ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय—इस समय किसी प्रकार के भी भाषण की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है—कि देश के दूधार तथा भारवहन पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय ।”

श्री विश्वास—जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ और जो कुछ कि मैं

इससे पूर्व इस विधेयक के उपस्थित करने वाले से कह चुका हूँ वह यह है कि यह विधेयक विधान के विपरीत है और इसका सम्बन्ध ऐसे विषय से है जो कि राज्य सरकार के आधीन है। पशुओं के परिरक्षण का विषय ऐसा है जो राज्य सरकार के अधिकारों में है क्योंकि यह द्वितीय सूची की एक प्रविष्टि है। मैं यह बता चुका हूँ कि मैं इस विधेयक को उपस्थित होने का विरोध नहीं करता क्योंकि इस सम्बन्ध में स्थापित प्रथाओं को तोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। जब १९४७ में मेरे एक माननीय मित्र ने एक किसी और अवसर पर ऐसा ही विधेयक उपस्थित किया था उस समय जो आपने निर्णय दिया था उसको ध्यान में रखते हुये जब कि आपने कहा था कि आप इसे उपस्थित होने से नहीं रोकेंगे, मैं आपको इस विधेयक को केवल इस लिए कि यह अर्बन्धानिक है ममान्य कर देने का नियन्त्रण नहीं दे रहा हूँ। परन्तु मैं तो केवल उपस्थितकर्ता सज्जन को सूचित करना चाहता हूँ कि जब विधेयक विधान के लिए उपस्थित होगा तो सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह इस का विरोध करे। यह विरोध केवल इस कारण ही नहीं होगा कि यह विधान के विरुद्ध है बल्कि इसके औचित्य के आधार पर भी होगा।

Mr. Deputy Speaker: Rule 72 provides that if a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves from the Member who opposes the motion may, without further debate, put the question. I propose doing it.

धारा ७२ के अनुसार यदि किसी प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति का विरोध होता है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो बिना अधिक विवाद के प्रस्ताव करने वाले और उसका विरोध करने वाले से संक्षिप्त स्पष्टिकरण माग ले और यह घोषणा कर दे कि मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

प्रश्न यह है—कि देश के दुधार तथा भारवहन पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सेठ गोविन्द दास—मैं इस विधेयक को उपस्थित करता हूँ।

THE INDIAN CATTLE PRESERVATION BILL 1952

(As introduced in the House of the People)

A

B I L L

to preserve the milch and draught cattle of the country. Be it enacted by Parliament as follow:

I. SHORT TITLE EXTENT & COMMENCEMENT:

- (1) This Act may be called the Indian Cattle Preservation Act, 195
- (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force on the 1st day of 19

II. DEFINITIONS: In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

- (a) "Cattle" shall include cows, bullocks, their young calves, he and she-buffaloes and their young calves.
- (b) "Person" shall include any company or association or body of persons whether incorporated or not.

III. STOPPING OF CATTLE SLAUGHTER: No person shall wilfully kill or slaughter a cattle either for food or any other purpose either in a licenced slaughter-house or any public or private place.

VI. PENALTY AND PROCEDURE:

- (1) Any person who wilfully contravenes the provision of section 3 and kills or causes to be killed a cattle shall be punishable with fine for each such offence up to a maximum of rupees five hundred or with rigorous imprisonment for six months or with both. In addition to the above

sentence the convicting Magistrate, may, in his discretion, at the time of the passing of the sentence for the offence under section 3 above call upon the person convicted to execute a bond for a sum proportionate to his means with or without sureties for abstaining from commission of such offence during such period not exceeding two years as he thinks fit to fix.

(2) The Inspector of police or any officer specially authorised or appointed in this behalf by the local or Central Government shall take cognizance of the offence committed under this Act.

V. APPLICATION OF THE ACT BY THE STATE GOVERNMENT:

The provisions of this Act shall be made applicable by the State Governments to the territories governed by them within six months of the passing of this Act by a notification in the State Gazette.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

India is an agricultural country and needs draught animals. India is deficient in milk and also needs milch cattle. The cows and buffaloes and the bullocks provide these two pressing needs. It is, therefore, necessary to preserve and increase supply of draught animals and milch animals by stoppage of slaughter of cows, bulls, bullocks, he and she-buffaloes and calves of these animals.

GOVIND DAS

भारतीय गौवंश संरक्षण विधेयक, १९५२ (जोकि लोकसभा में उपस्थित किया गया)

एक विधेयक

देश के दुग्ध और भारवाहक पशुओं के परिरक्षण के लिये । सदन द्वारा इसको इस प्रकार पास किया जाये :-

१. संक्षिप्त शीर्षक, अधिकार क्षेत्र और आरम्भ

१. इस कानून को भारतीय पशु परिरक्षण कानून १९५२ का नाम दिया जाये ।

२. यह भारे भारत में लागू हो ।

३. यह १९५२ के प्रथम दिन में लागू होगा ।

२. व्याख्यायें

इस कानून में जब तक ।

[क] "पशु" में गाय, बैल, उनके बछड़े, बछड़ियाँ, भैंस और उनके बटड़े, कटड़ियाँ सम्मिलित होंगे ।

[ख] "व्यक्ति" में कोई कम्पनी, संस्था या कुछ लोगों का बना हुआ एक समूह चाहे वह संयुक्त हो या ना, सम्मिलित होगा ।

३. पशु हत्या पर रोक

कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर पशु को स्वाद्य या अन्य निम्नी कार्य के लिए ना ही अविद्युत वृत्तध्वनि और ना ही किसी सार्वजनिक या गुप्त स्थान पर बध करेगा ।

४. दण्ड और पद्धति

१. कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद ३ का जानबूझ कर उल्लंघन करे और पशु को मारे या मरवाये उसको अधिक से अधिक ऐसे अपराध के

लिए ५०० रुपये का अथ दंड या छः मास का कड़ा कारावास या दोनों दंड दिये जा सकने हैं। ऊपर वाले दण्ड के अतिरिक्त यदि दंड देने वाला मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि और इच्छानुसार ऊपर वाले अनुच्छेद ३ के अनुसार ऐसे अपराध के लिए दंड देते समय दंडित व्यक्ति ने उसके साधनों के प्रनुरूप जमानत सहित या, इसके बिना एक विशेष धन का आश्वासन पत्र इस बात के लिए भरवा सकता है कि वह व्यक्ति दो वर्षों के बीच में जितना समय मैजिस्ट्रेट द्वारा निश्चित किया गया हो, ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा।

२. पुलिस इन्स्पेक्टर या अन्य ऐसा कोई अधिकारी जिसे स्थानीय या केन्द्रीय सरकार इस कार्य पर नियुक्त करे या ऐसे अधिकार दे इस कानून के आधीन किये गये अपराध को पकड़ सकेगा।

५. कानून को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करना

इस कानून को राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने के छः मास के भीतर लागू करें।

उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी वक्तव्य

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसकी भारवाहक पशुओं की आवश्यकता है और इसी प्रकार दूध के अभाव के कारण दुधारु पशुओं की भी आवश्यकता है। गायें, भैंसें और बैल इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए भारवाहक तथा दुधारु पशुओं की उन्नति और परिरक्षण करना गायें, बैल, सांड, भैंस, भैंसों और इनके बछड़े, बछड़ियों के वध को समाप्त करके उनकी आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार से उन्नत करना अत्यावश्यक है।

गोविन्द दास

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक

२७ नवम्बर १९५३

सेठ गोविन्द दास: (मंडला-जबलपुर दक्षिण) — सभापतिजी, मेरे नाम पर जो विधेयक है उसे मैं विचारायें उपस्थित करता हूँ ।* जब मैं इस विधेयक को इस सभा में पेश करता हूँ उस समय मैं यह मानता हूँ.....

श्री गिडवाली (याना)—आप कृपा करके बोलिये तो सही कि किन बारी में है ।

सेठ गोविन्ददास—पशुरक्षा-विधेयक जिसे कि आपने आज की कार्गवाई में पढा होगा ।

जब मैं इसे पेश करता हूँ उस समय मैं यह मानता हूँ कि देश के नामने जितनी महत्त्वपूर्ण बातें हमें करनी है, उनमें से यह सबसे महत्त्वपूर्ण बातों में से है । जिस समय गोवध-निषेध पर चर्चा होती है,

उस समय हमारे सामने सबसे पहले आज जो अपने को सुधारक मानते हैं वे यह कहते हैं कि यह चर्चा रुढ़िवादी चर्चा है ।

श्री अध्यक्ष महोदय:—क्या मैं माननीय सदस्यों से सदन न छोड़ने की प्रार्थना कर सकता हूँ, अब केवल १५ मिनट रह गये हैं ? यदि एक-एक करके सभी सदस्य उठकर चले गये तो कोरम पूरा नहीं रहेगा । यह गैर-सरकारी दिवस है और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सदन में कोरम पूरा रहे ।

सेठ गोविन्द दास—तो सबसे पहले यह बात कही जाती है कि गोवध-निषेध के सम्बन्ध में जो आन्दोलन होता है, जो कुछ कहा जाता है, सब में, उसकी पृष्ठभूमि में, रुढ़िवाद है । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को हम रुढ़िवादी नहीं मान सकते । उन्होंने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा था कि गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्वपूर्ण नहीं है । राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी को हम रुढ़िवादी नहीं मान सकते । उन्होंने एक नहीं अनेक बार गोरक्षा के ऊपर अपने भाषण दिये हैं । सन्त बनोवा भावे को, जो इस समय देश में महात्मा गांधी के सबसे बड़े शिष्य हैं, हम रुढ़िवादी नहीं मान सकते । पुरानी बातों को जाने दीजिये । अभी हाल ही में बिहार में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि इस देश की जसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में गोवध बन्द होना नितान्त आवश्यक है । मैं अपने को भी रुढ़िवादी नहीं मानता । इतना ही नहीं, मैं अपने को साम्प्रदायवादी भी नहीं मानता । गत ३३ वर्षों से मैं केवल एक संस्था में रहा हूँ और वह कांग्रेस संस्था है, और जब से मैंने गत ३० वर्षों से इस केन्द्रीय धारा सभा में प्रवेश किया है, चाहे इस सभा में हो और चाहे कौंसिल आफ स्टेट में हो, मैंने सदा गोरक्षा के विषय में कुछ न कुछ करने का प्रयत्न किया है । आज तक इन ३३ वर्षों में मैं किसी भी साम्प्रदायिक संस्था का सदस्य नहीं रहा । इसलिये गोरक्षा के प्रश्न को रुढ़िवादी प्रश्न कहना, गोरक्षा के प्रश्न को साम्प्रदायवादी प्रश्न कहना,

इस प्रश्न के साथ और हम लोग जो इस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब के साथ, बड़े से बड़ा अन्याय है।

हमारा संविधान भी इस विषय में देखा जाये। हमारे संविधान में जो निर्देशात्मक अध्याय है, उसमें स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया है। महापतिजी, आपको याद होगा कि उस समय जबकि संविधान परिषद् में इस विषय की चर्चा हो रही थी तब वहां पर दो धारयाँ उपस्थित थीं। एक धारा में उपस्थित की थी जोकि करीब-करीब उसी तरह की थी जिस तरह का कि यह विधेयक है, और दूसरी धारा आपने उपस्थित की थी, जोकि स्वीकृत की गई। जहां तक संविधान की उस धारा का सम्बन्ध है, उस धारा में यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि इस देश में गोबध नहीं हो सकेगा। हम अपने संविधान के बड़े भारी समर्थक हैं, जिस संविधान का पालन करने की, उसके प्रति ईमानदार रहने की हमने शपथ ली है, उस संविधान के अनुसार भी इस देश में गोबध का कतई वन्द होना अनिवार्य हो जाता है। फिर हम प्रजातंत्र के पोषक हैं, हमने इस देश में प्रजातंत्र को चलाने का संकल्प किया है, हम यह कहते हैं कि इस देश में हमको प्रजातंत्र चलाना है, प्रजातंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि जो प्रजातंत्र शासन को चलाते हैं वे जनता क्या चाहती है, उनकी भावना के अनुसार काम न करें। मैं कहता हूँ कि इस देश में जनमत लिया जाय, इस देश में रिफरेन्डम लिया जाय, अगर ६० प्रतिशत मतों से गोबध-निषेध का प्रश्न जनता को स्वीकृत न हो और १० प्रतिशत ने अधिक व्यक्ति इसके विरोध में हों, तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय। मेरा इस बात पर बड़ा विश्वास है कि इस देश में एक-एक व्यक्ति इस बात का पक्षपाती है कि गाय का एक दूँद रक्त भी न गिरे। अब मैं यह कहता हूँ तो मैं कहना हूँ अपने अनुभव के आधार पर। मुझे स्वयं इस देश का कुछ अनुभव है, अपने प्रदेश के जिलों, जहरो, कस्बों और गांवों का अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं आप से कहता चाहता हूँ कि चाहे आप इस देश में हिमालय से लेकर

कन्या कुमारी तक जाये या अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जायें, आपको ६० प्रतिशत लोग इसके पक्ष में मिलेंगे कि गोवध-निषेध इस देश में हो, गोवध यहां पर न हो ।

फिर, सभापति जी, यह मानव केवल मस्तिष्क से ही शासित नहीं है, इस मानव के हृदय भी है, इस हृदय में जो भावनाएँ उठती हैं, उन भावनाओं से भी उसका जीवन चलता है ।

एक मानव का जिस प्रकार जीवन चलता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का जीवन चलता है । यदि आप भावनाओं से विहीन करके मानव को चलाना चाहे, राष्ट्र को चलाना चाहे, समाज को चलाना चाहें, तो वह राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता । इस संसार में जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, इस संसार के किसी देश के इतिहास को आप देख लें, उस देश में जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, वे सब भावनाओं से ही हुए हैं । जब समाज भावना-प्रधान रहता है तभी बड़े-बड़े काम हो सकते हैं । हमारे स्वराज्य के ही प्रश्न को आप लीजिये यदि महात्मा गांधी ने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इस देश के मानवों में भावनाएँ न भरी होतीं, स्वतंत्रता की भावनाएँ न भरी होतीं, तो क्या यह कभी संभव था कि हम इस देश में स्वराज्य की स्थापना कर पाते । इसलिये जहाँ एक ओर हमें मस्तिष्क से शासित होना है वहाँ दूसरी ओर हमें भावनाओं का भी ध्यान रखना है, और मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भावनाओं का सवाल है इस देश की भावनाएँ गोवध के प्रतिकूल हैं । वे नहीं चाहते कि एक भी गाय का यहाँ वध किया जाये ।

फिर गोवध को हम आर्थिक दृष्टि से भी देखे यह देश कृषि प्रधान देश है । इस देश की कृषि बिना बैलों के नहीं चल सकती । मैं ट्रैक्टरों के विरुद्ध नहीं हूँ । मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि हम को ट्रैक्टरों या और किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है । हम को ट्रैक्टरों की आवश्यकता है और हम को दूसरी मशीनों की भी आवश्यकता है ।

उसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल ट्रैक्टरों से इस देश की खेती नहीं हो सकती। भूमि का जिस प्रकार विभाजन इस देश में है उसको देखते हुए, इस देश के किसानों की जो आर्थिक अवस्था है उसको देखते हुए, यदि हम ट्रैक्टरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमारी खेती नहीं चल सकती। फिर यहाँ भूमिदान का आन्दोलन चल रहा है। उसमें लाखों एकड़ जमीन मिल रही है। वह लाखों एकड़ जमीन आगे चलकर बंटने वाली है। भूदान का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस देश में कोई भी भूमिहीन मजदूर न रहने पावे। जो लोग खेती से अपने गुजर-बसर करते हैं उनको कम से कम पाँच एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। करीब २४ लाख एकड़ जमीन विनोबाजी को प्राप्त हो चुकी है। मैं भी उसमें एक छोटासा कार्यकर्ता हूँ। मुझे विश्वास है कि सन् १९५७ तक ५ करोड़ भूमि विनोबाजी को मिलने वाली है। जब यह पाँच करोड़ भूमि भूमिहीन मजदूरों में बँट जायेगी, जो भूमि का बंटवारा इस वक्त है और भूदान के पश्चात् जो भूमि का बंटवारा होगा उस को देखते हुए, और आगे जो यह आन्दोलन यहाँ चलने वाला है कि एक खास तादाद के आगे किसी के पास जमीन न रहने पावे, इस सब को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्रैक्टरों ने उन परिवारों का काम कैसे चलेगा जिनके पास कि पाँच-पाँच एकड़ भूमि होगी? इसलिए हमको बैलों की नितान्त आवश्यकता है, और जहाँ तक बैलों का सम्बन्ध है वह गोंवध बन्द होने पर बहुत हद तक निर्भर है। फिर हमारे यहाँ पर जितने निरामिष भोजन करने वाले हैं, जो मांस नहीं खाते, उनकी जितनी बड़ी संख्या हमारे देश में है उतनी दुनिया के और किसी देश में नहीं है। उनको दूध चाहिए, उनको घी चाहिए। बिना दूध और घी के हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। इसलिए एक ओर हमें खेती के लिए बैल चाहिये; दूसरी ओर हमें दूध और घी के लिए गायें चाहियें। कहा जाता है कि बैकाम पशु रख कर हम क्या करेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह सब से बड़ी गलत फहमी इस

विषय में है। जो लोग यह कहते हैं कि इस देश में बेकाम पशु ही मारे जाते हैं वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने बम्बई, मद्रास और कर्नाटक के कसाईखानों को देखा है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो गायें मारी जाती हैं, जो बछड़े मारे जाते हैं वे बेकाम नहीं होते हैं। तब प्रश्न उठता है कि उनका यश क्यों होता है? उनका यश प्रधानतया इसलिए होता है कि इस देश में चमड़े का निर्यात होता है, इन देश में बाहर गोमांस जाता है। मेने कर्माश्कर जी के मागने कुछ आँखों पेस किये थे और उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि आप पता लगावे कि इस देश में कितना गोमांस बाहर भेजा जाता है, इन देश में कितना चमड़ा बाहर भेजा जाता है, यह जो गोवध यहाँ होता है वह गोवध इस गोमांस तथा चमड़े के निर्यात के लिए प्रधानतया होता है और गोमांस के निर्यात के लिये जो गोवध होता है। चमड़े के निर्यात के लिए जो गोवध होता है, वह बेकाम पशुओं का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेकाम पशुओं में मांस नहीं मिलता और न उनके चमड़े अच्छे हो सकते हैं। इसलिए चमड़े और गोमांस के लिए जो यह गोवध प्रधानतया होता है यह अच्छे से अच्छे जानवरों का होता है। इस विषय में जितने भी कानून बनाए गये हैं वे कभी कार्य रूप में परिणत नहीं किये जा सके हैं। उन कानूनों में यह व्याख्या है कि १४ वर्ष में नीचे की उम्र के पशु न मारे जाये। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, क्योंकि मैं इस आन्दोलन में गत ३० वर्षों से रहा हूँ, कि आठ वर्ष की ऊपर की उम्र के पशुओं के लिये कोई विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता है कि वह कितनी उम्र का है। आठ वर्ष की उम्र के ऊपर के जो पशु होते हैं वह बेकाम नहीं होते। हमने इस बात को देख लिया है कि प्रत्येक राज्यों में इस प्रकार का कानून है कि बेकाम पशु ही मारे जाये, लेकिन वे कानून कार्यरूप में परिणत नहीं हो रहे हैं। दूसरे देशों की मिसालें भी हमारे सामने हैं। दूसरे देशों में जहाँ कानून बनाए गए कि बेकाम पशु ही मारे जाये,

वहाँ कानून कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके। मैं आपको वर्मा का ही उदाहरण देता हूँ। वर्मा में पहले यह कानून बना था कि वहाँ अमुक अमुक अवस्था के ऊपर के पशु मारे जायें उसके नीचे के पशु न मारे जायें, लेकिन वह कानून रूप में परिणत नहीं हो सका और अन्त में वर्मा में बिल्कुल ही गोवध बन्द करना पड़ा तभी उपयोगी पशुओं की रक्षा हो सकी। फिर किसी पशु को बेकाम कर देना बड़ा आसान है। उनकी एक टाँग तोड़ दीजिए या और किसी प्रकार से अंग भंग कर दीजिए, वह बेकाम की संज्ञा में आ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बेकार पशु ही मारे जायें और अच्छे पशु न मारे जायें, उनका उद्देश्य, जब तक गोवध कतई बन्द न होगा तब तक निष्ठ नहीं हो सकता।

एक और दूसरी गलत फहमी है कि इन बेकाम पशुओं के लिए चारा कहाँ से आयेगा जबकि काम के पशुओं के लिए ही चारा नहीं। इसके लिए हमारे भागत गोमयक समाज ने गो मठनों की योजना रखी है। आप इस देश में रेल द्वारा मीनों चले जाइये आपको दोनों तरफ ऐसी बहुत भूमि मिलेगी जिनमें हरों घास मौजूद है। वह घास जाड़ों में या तो ठंड के कारण जलम हो जाती है या गर्मियों में लू के कारण जल जाती है। यदि उन स्थानों पर गोमठनों की स्थापना हो जाये तो वहाँ पर वह बेकाम पशु रक्ते जा सकते हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि इन बेकाम पशुओं की संतति बढ़ाई जाय। हमने स्पष्ट कहा है कि वहाँ सांड न रख कर वहाँ पर बेकाम पशु रक्ते जायें। और उनको वहाँ पर रख कर गोमठन नलाए जायें। इस काम में जो वर्तमान गोशालायें हैं, वे भी बहुत बड़ी सहायता दे सकती हैं। हमारी एक यह योजना भी है कि इन गोशालाओं के दो दो विभाग कर दिए जायें, एक विभाग डेवरी और नस्ल सुधार का होना चाहिए और दूसरा विभाग बेकाम पशुओं की रक्षा का होना चाहिए। हमारे यहाँ कई गोशालायें ऐसी हैं जिनमें यह दोनों

विभाग चल सकते हैं। उनके पास जमीन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भी गोसदन स्थापित करे और इन गोनान्त्रियों को भी सहयता दे।

अध्यक्ष महोदय:—क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेना चाहते हैं ?

सेठ गोविन्ददास—जी हाँ, अभी मुझे बहुत समय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय:—वह सदन सोमवार के डेढ़ बजे तक स्थगित रहेगा।

— — —

३

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

११ दिसम्बर १९५३

अध्यक्ष महोदय—अब सदन में सेठ गोविन्ददास के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार होगा ।

कि देश के दुधारु तथा भार वहन पशुओं के परिदक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये ।”

सेठ गोविन्द दास—(मंडला-जवलपुर दक्षिण) सभापति जी, २७ नवम्बर को जब मैंने अपना यह विधेयक विचार करने के लिए उपस्थित किया उस समय मैंने आरम्भ में कहा था कि जो लोग यह समझते हैं कि हम रुढ़िवादी हैं, हम सम्प्रदायवादी हैं, वे हमारे साथ

अभ्यास करते हैं। अपने इस कथन के प्रमाण स्वरूप में आप के सामने इस देश के कुछ महापुरुषों के दायन उपस्थित करता हूँ। राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने यह कहा था।

“भारतवर्ष में गौरवा का प्रथम मान्यता में किसी प्रकार यम नहीं। कई बातों में तो मैं उसे खराब में भी मिला मानता हूँ। जबकि हम गाय को बचाने का उपाय तो नहीं निभाते तबतक खराब अर्थहीन कहा जायगा। देश की गुरु-मूर्तियों और उसकी सन्मान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।”

हमारे जो आज राष्ट्रपति हैं, जाकर राजेन्द्रप्रसाद जी, उन्होंने कहा था—

“हिन्दुस्तान में गायों के लिए हम कद की मानता है कि उनको मारना लोग पसन्द नहीं करते। वरु जो ब्रह्मदुरी की मान्यता को जानती है कि जितने खराब जानवर हैं उन को मार कर दिया जाय, मैं समझता हूँ इसमें ब्रह्मदुरी ज्यादा है दुष्टिमानी नहीं। यदि हम उस काम को करना चाहेंगे तो अपने खिलाफ एक बड़ी जगावत पैदा कर देंगे।”

३ मार्च १९५१

इस समय महात्मा गांधी जी के सद से बड़े निष्ठा रखत विनोद भावे हैं, उन्होंने हाल ही में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसके अ उद्धरण आपके सामने उपस्थित करता हूँ।

१. ‘इस देश में गोहत्या नहीं चल सकती। गाय दैज हमारे सनातन में दाखिल हो गये हैं। सीधा प्रश्न यह है कि आप को देश का रक्षण करना है या नहीं। यदि करना है तो गोवध भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं आता। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गोहत्या जारी रही तो देश में बगावत होगी। गोहत्या बन्दी भारतीय जनता का मेडेट, लोक आज्ञा है, और प्रधान मन्त्री महोदय को इसे मानना चाहिए।”

“सर्वोदय” १२ नवम्बर १९५१

२. "हिन्दुस्तान में गोरक्षा होनी चाहिए। अगर गोरक्षा नहीं होती तो कहना होगा कि हमने अपनी आजादी खोई और इस की सुगन्ध गँवाई। मैंने कुरान और बाइबिल का गहराई और अत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है। मैं मुसलमान और ईसाइयों की ओर से उनका प्रतिनिधि बन कर कहता हूँ कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय का बलिदान हो। मैं कहता हूँ कि हमारी संव्युलर स्टेट में गोरक्षा होनी चाहिये।"

("हरिजन-सेवक" २२ अगस्त १९२३)

अब सभापति जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी को, सन्त विनोबा भावे को, कोई भी रुढ़िवादी, या साम्प्रदायवादी नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में जब हमें ऐसे विशेषणों से विभूषित किया जाता है तो हम लोगों के साथ और हम लोगों के साथ ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ, सन्त विनोबा जी के साथ और स्वर्गीय महात्मा गांधी के साथ भी अन्याय किया जाता है।

डा० एन. बी. खरे—(स्वालयर) यह अन्याय कौन करता है ? जरा मुझे बता दीजिये, मालूम नहीं है।

सैठ गोविन्द दास—अब प्रश्न यह है कि गोवध सर्वथा बन्द क्यों हो ?

श्री खारदेकर (सतारा)—आपत्ति—इस बात से नियमपूर्वक रोक दिया गया है कि राष्ट्रपति का नाम किसी भी वाद-विवाद में न लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय—क्या माननीय सदस्य को यह आपत्ति है कि यदि राष्ट्रपति ने कोई भाषण या वक्तव्य दिया है तो उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता ?

श्री खारदेकर—मेरा वही प्वाइन्ट था।

अध्यक्ष महोदय—मैं ऐसा अनुभव नहीं करता कि किसी उद्धरण को उपस्थित करने की आज्ञा न दूँ। आपत्ति नहीं है।

सेठ गोविन्द दास—अब, सभापति जी, हम गोवध सर्वथा बन्द क्यों कराना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में आपके सामने कुछ बातें उपस्थित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सन्मुख अपने सविधान की धारा ४८ उपस्थित करता हूँ। यह धारा अनेक बार पढ़ी गयी है, लेकिन जब तक इस देश में गोवध जारी है तब तक यह धारा सदा पढ़ी जायगी। इस धारा में य. कहा गया है—

48—"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

४८, राज्य कृषि और गोपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा संगठित करने का प्रयत्न करेगा, तथा विशेषतया नसलों के परिरक्षण और गोसम्बर्धन तथा गायों, बछड़ों व अन्य दूधार एवं भारवाहक (यानी, हल, गाड़ी आदि में चलने वाले) पशुओं की हत्या का निषेध करेगा।

इस धारा का बहुत बार ऐसा अर्थ लगाया जाता है जो यथार्थ में इसका अर्थ नहीं है। मैं यद्यपि आजकल यहाँ पर अपनी राष्ट्रभाषा और राज्य-भाषा हिन्दी में बोलता हूँ, पर गये तीस वर्षों से मैं इस सभा का सदस्य रहा हूँ। और पहले अंग्रेजी में ही बोलता था। मेरी अंग्रेजी कभी बुरी नहीं मानी गई। अंग्रेजी मैं जानता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धारा के जो अन्तिम विशेषण हैं 'अदर मिन्च एण्ड ड्राट कैटल' अन्य (दुधारने और भारवाहक पशु) इन विशेषणों को 'काऊज और

कावज' गाय बछड़े बछड़ी के साथ नहीं लगाया जा सकता । क्यों नहीं लगाया जा सकता वह मैं आपको बताता चाहता हूँ । पहले तो आप कावज बछड़े बछड़ी गध के लीजिये । अब कावज बछड़े बछड़ी न तो मिल्च दुधार ही होती हैं और न ट्राफ्ट भारवाहक ही होते हैं । कावज बछड़े बछड़ी गध के पहले काऊज (गाय) गध आया है यानी "काऊज एण्ड कावज एण्ड अदर मिन्च एण्ड ट्राफ्ट कैटल" गाय तथा बछड़े बछड़ी अन्य दुधार और भारवाहक पशु, आप यह देखिये कि 'अदर मिन्च एण्ड ट्राफ्ट कैटल अन्य दुधार तथा भारवाहक विशेषण कावज (बछड़े बछड़ी) के साथ कैसे लग सकते हैं ? अगर इस संविधान का अभिप्राय केवल मिल्च (दुधार) और अदर ट्राफ्ट कैटल (अन्य भारवाहक पशुओं) को ही बचाने का होता तो काऊज एंड कावज (गाय बछड़ी-बछड़े) इन दोनों गधों को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी । उस वक़्त तो इसमें यह लिखा जाता ।

"नमलों के परिश्रम और योगस्वयं के साधन जुटायेगा और दुधार एवं भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध करेगा ।"

इतने ही में, मिल्च एंड ट्राफ्ट कैटल (दुधार और भारवाहक पशुओं) में ही गाये भी आ जाती, बैल भी आ जाते, भैंस भी आ जाती और भैंस भी आ जाते । लेकिन इसमें काऊज एंड कावज गाय बछड़ी-बछड़े पहले लिये गये और उसके बाद अदर मिन्च एंड ट्राफ्ट कैटल अन्य दुधार और भारवाहक लिखा गया है । जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, उनके सामने इस संविधान को रखा जाय और उनमें पूछा जाय कि इस संविधान की धारा का अर्थ क्या होता है, मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई विशेषज्ञ अपना निष्पक्ष निर्णय देगे तो स्पष्ट रूप से यह निर्णय देगे कि गायों और बछड़ों का तो वय तुरन्त बन्द होना चाहिये और उसके बाद जो दूसरे जानवर हैं, भैंसे हैं और भैंसे हैं जो मिल्च एंड ट्राफ्ट कैटल दुधार और भारवाहक पशु में आता है उनका वय नहीं किया जाना चाहिये जो

हमारे दूध के या खेती के काम में आते हैं उन दूसरे जानवरों का वध नहीं किया जाना चाहिये। गायों और बछड़ों में यह विशेषण नहीं लगाए जा सकते। इस तरह का अर्थ लगाना, खीचातानी करनी, हमारे संविधान के अर्थ का अनर्थ करना है।

फिर यह संविधान की धारा क्यों बनी। इस सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा। हमारी सरकार और सत्तार की सभी सरकारें विशेषज्ञों की राय के अनुसार चलती हैं। विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में पहले एक कमेटी मुकर्रर हुई। उसका नाम है कैंटल प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, गोवंश रक्षा तथा उन्नति कमेटी १६ नवम्बर १९४७ को यह कमेटी नियुक्त हुई, हमारे कृषि मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार। वह प्रस्ताव भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रस्ताव यह है—

भारत सरकार को पता चला है कि इस देश में मांस के लिये हर वर्ष बहुत अधिक संख्या में गोवश का वध होता है, अन्यवस्थित रूप में हर प्रकार के और हर आयु के पशुओं की हत्या की जाती है। पशुवध के कारण दूध और उपयोगी बैलों का अभाव हो रहा है। देश के गोधन का ह्रास और विनाश हो रहा है। इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों, सार्वजनिक सभाओं और विधानसभाओं में जोरदार आंदोलन होता रहा है। और सरकार पर यह दबाव डाला जाता रहा है कि पशुवध को रोकने के लिए अति शीघ्र कानून द्वारा इसपर प्रतिबन्ध लगाया जाए। यह एक बड़ा जटिल तथा सामाजिक और धार्मिक प्रश्न है। बहुत सोच-विचार के पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बना दी जाये। वह समिति इस प्रश्न पर हर दृष्टिकोण से पूर्णतया विचार करे और एक पूर्ण रिपोर्ट उपस्थित करे, जिसके द्वारा देश के गोधन की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए उचित साधन अति शीघ्र ही अपनाये जा सकें।”

इस प्रस्ताव पर यह कमेटी बनी। इस कमेटी ने क्या सिफारिश की वह भी मैं आप को बताना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य—कमेटी के मेम्बरान कौन थे ?

सेठ गोविन्ददास—मेम्बरान के नाम हैं ।

सरदार बहादुर दातारसिंह, रायबहादुर पी. एन. नन्दा

श्री एच. वी. जाही, डा० ज्ञान आर. कोटेवाला

लाला हरबंश महाय, राय बहादुर जे. एन. मान्कर

सरदार हरबंशसिंह, गुन महाराज प्रतापसिंह

बाबू धर्मदालसिंह, श्री सतीशचन्द्र दान गुप्त

श्री महावीरप्रसाद पोटवार, श्री लाला सुनापति गरवान

सेठ गोविन्ददास

अब उन्होंने ६ नवम्बर १९४८ को सिफारिश इस सम्बन्ध में की वह मैं आपके नामने रखता हूँ—

इस कमेटी का यह मत है कि भारत में किसी भी परिस्थिति में गोवंश का वध उचित नहीं और इसको कानून द्वारा बन्द किया जाये । भारत की समृद्धि बहुत कुछ गोवंश पर निर्भर है और देश की आत्मा को तभी सन्तोष होगा, जबकि गोवंश के वध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाये और आज गोधन की जो दुर्दशा है उसको उन्नत किया जाये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमेटी निम्नलिखित गुणाव उपस्थित करती है, जिनकी कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ।

फिर आगे चलकर उसने इस सम्बन्ध में और कहा—

१. सर्वप्रथम निम्नलिखित पशुओं के अतिरिक्त सभी उपयोगी पशुओं के वध पर जीव्र प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

(क) १४ वर्ष से अधिक आयु के और अनुपयोगी पशु ।

(ख) ऐसे सभी पशु जो आयु, चोट आदि के कारण सेवा के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं ।

२. बिना लायसेंस और आज्ञा के पशुवध पर जीव्र प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और ऐसा कानून बनाया जाये जिसके द्वारा पशुवध अपराध माना जाये ।

३. शीघ्र अति शीघ्र ऐसा कानून लागू किया जाये जिसके द्वारा गोवंशवध पूर्णतया बन्द हो जाये और कानून के लागू होने के दो वर्ष तक अनुपयोगी पशुओं की सेवा और रक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायें ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह संविधान की ४८ वीं धारा कुछ आप-मे-आप आस्मान से नहीं टपकी । इस ४८ वीं धारा के निर्माण के पहले एक विपक्षी की कमेटी नियुक्त की गयी, उस कमेटी में कौन-कौन थे, यह मैंने आपको पढ़ कर सुनाया । उस कमेटी की क्या सिफारिशें थी, यह मैंने आपको बतलाया और उस कमेटी की राय के अनुसार संविधान की ४८ वीं धारा बनायी गयी । फिर हमका सिफारिशों के कुछ अंश को, (पूरी को तो नहीं) सरकार ने स्वीकार भी किया और यह २४ मार्च सन् १९४९ को उस समय कृषि मन्त्री श्री जयरामदास दौलतराम थे, उन्होंने यहाँ पर इस सम्बन्ध में क्या कहा था यह मैं आपके सामने रखता हूँ, वह कहते हैं ।

श्री जयरामदास दौलतराम-खाद्य और कृषि मन्त्री १६ मार्च १९४६ को जो खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी मांगों पर वाद-विवाद हुआ तो सेठ गोविन्ददास ने पशुओं की उन्नति और सुधार और पशु-हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्य करने का प्रश्न उठाया था । मैंने उत्तर देते हुये इस विषय पर कहा था और पशुरक्षा तथा उन्नति कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के अस्थायी निर्णय की भी घोषणा की थी; परन्तु क्योंकि उस दिन वाद-विवाद ५ बजे समाप्त करना था, मेरा वक्तव्य बड़ा संक्षेप में था और मेरा विचार है कि यह बड़ा सहायक सिद्ध होता यदि सरकार का निर्णय और स्पष्ट होता ।

उसके बाद उन्होंने कैंटल प्रिजर्वेशन (पशुरक्षा) कमेटी की जो सिफारिशें थी, जिन्हें मैंने अभी पढ़ा था, वे पढ़ी और उसके बाद उन्होंने यह

कहा कि बाँझ वष की उम्र के नीचे के पशु न मारे जायें और उपयोगी पशु भी न मारे जायें, इस विषय में वह यह कहते हैं।

प्रायः तो बहुत से सन प्राप्त हुये वे प्रायः कमेटी द्वारा उपस्थित किये गये पहले दो सुझावों में जो कार्य बनाया गया है उसके पक्ष में हैं। इनलिग मन्त्रालय ने उन सुझावों को स्वीकार करके उनको क्रियान्वित करने के लिये नीचे दी उचित कार्य करने का निर्णय कर लिया है।

यह आश्वासन हमको २४ मार्च सन् १९४६ को मिला। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की जो पहली यादृति है, उनमें भी इस विषय पर प्रजाप उल्लास गया और यह कहा कहते हैं, वह में आपको बतनाता है।

“इस समस्या पर क्याकिस पशुवध से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और जहाँ अनुपयोगी पशुओं का वध करना कार्यान्वित होना वाला सुझाव नहीं, इसलिग इस स्थिति को संभालने के लिए किसी तीसरे दो सुझाव या मार्ग की आवश्यकता है। इसमें एक मार्ग यह है कि जहाँ चारा आवश्यकता से अधिक होता है वहाँ मदन खाले जायें। पिंजराघालों द्वारा इन सदन में बृद्ध और अनुपयोगी पशुओं को भेजा जायें और उस प्रकार जो आज चारों का अभाव प्रतीत होता है, उस की समस्या ठीक हो जायेगी। वहाँ पर जीवित पशुओं के गोबर से खाद और मर जाने के पश्चात् खाले आदि प्राप्त करने का उचित प्रवन्ध किया जा सकता है।”

अच्छे पशुओं के परिन्धाल की दृष्टि से गहरो की दूध-सूखी गायों की समस्या भी महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि अच्छी दुधार गायें बम्बई और कनकना जैन बड़े नगरों में लाई जाती हैं और दूध सूख जाने पर बूचढ़ालों को भेज दी जाती हैं।”

यह निष्कर्ष है पंचवर्षीय योजना की और अब इतनी दूर हम क्यों जायें, अभी हाल में हमारे जो कृषि मन्त्री श्री किदवाई हैं, उन्होंने सन

१९५२ में २३ दिसम्बर को पटना में जो कहा यह भी मुन लीजिये:—

आज यहाँ श्री रफी अहमद किदवई, खाद्य मन्त्री भारत सरकार ने कहा कि अब देश में गोहत्या को बन्द करने के पक्ष में इतना अधिक जनमत है तो इसका आदर होना चाहिए क्योंकि जनतन्त्र तभी सफलतापूर्वक चल सकता है ।

डा० एन, वी, खरे—इस सब के खिलाफ कौन है यह तो बतलाइये ।

सेठ गोविन्ददास—यह जो कृषि मन्त्री जी का हाल का कहना है, वह मैंने आपको बतलाया, फिर सरकार ने १६० गोसदनो के स्थापना की योजना बनायी । अगर सरकार पूरा गोवध इस देश में बन्द नहीं करना चाहती तो गोसदनो की योजना न बना कर कसाईखानो की योजना बनानी चाहिए । हम लोग कही न कहीं किसी स्थान पर तो जायेगे, या इसी प्रकार सारे मामले टटोलते रहेगे । इसके लिये दो ही रास्ते हो सकते हैं । या तो जिस तरह से हमारी कैटल प्रीजर्वेशन (पशु-रक्षा) कमेटी ने कहा और उसके आधार पर हमारे सविधान की धारा बनी, उसके अनुसार हम अमल करे और हमारी पंचवर्षीय योजना में गोसदनो की बात कही गयी और श्री रफी अहमद किदवई साहब ने इस बात को कहा कि अगर हमें इस देश में प्रजातन्त्र चलाना है, तो हमें लोगो के मत का ध्यान रखना होगा, इसके अनुसार काम करे । वहाँ-दुरी की बात चाहे जितनी कह लीजिये कि हम बेकाम पशुओं को मार डाले, लेकिन यह बात इस देश में नहीं हो सकती, अगर हम सबको मजूर करते हैं, और गोसदनो की योजना बनाते हैं, तो हमको गोसदनो की योजना बनाकर इस गोवध को कतई बन्द करना होगा, या फिर हम गोवध की बात और आगे बढ़ावे, कसाईखानो की स्थापना करें और जितनी गाये यहाँ पर हैं उनको काटने को तैयार हो जाये । दो में से एक रास्ता हमें चुनना होगा, इनके अलावा और किसी दूसरे रास्ते पर हम चल नहीं सकते ।

एक ब्रान और बार-बार कही जाती है कि आर्थिक दृष्टि से इन गायों को रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यह दूसरी गलतफहमी है। आर्थिक दृष्टि से यह जो पशु प्रकाम कहे जा रहे हैं, यह यथार्थ में बेकार है या नहीं, इस पर हमें विचार करना होगा और इस विषय पर आपके सामने विहार सरकार की इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट है—

प्रथम-धर्मपालमिह, मन्थी, बिहार राज्य गौबाला पिजरापाल संघ पटना का वृक्ष के देशों का दौरा।

इनका गोमन्दर्शन अंक है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य का और तीसरी यह पंचवर्षीय योजना है रखना चाहता हैं। इन सब में इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। अगर मैं उन सब को यहाँ पर पढ़ने लूँ, तो शायद दो घंटे मुझे उस सब के पढ़ने में लग जायेंगे। इसलिए मैं उसका एक संक्षिप्त तौट जो मैंने बताया है उसे मैं गदन के सामने पढ़ देना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अंक दिये गये हैं और उन अंकों को सीखिक पढ़ना सम्भव नहीं है। अब आप देखिये कि इन सब प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर एक पशु पर कितना व्यय होता है।

“सरकारी गोमन्दर्शन कौन्सिल के अनुमान के अनुसार एक पशु को गोमदन में रखने का आरम्भिक व्यय १५ रुपये और प्रतिवर्ष १० रुपये निगनती इत्यादि पर व्यय आता है। यदि एक बृद्ध और अपग पशु अधिक से अधिक ५ वर्ष जीवित रहे तो उस पर औसत खर्च १५ रुपये प्रतिवर्ष होगा। इस पशु के मरने पर बमड़े हड्डी इत्यादि में यदि कम से कम ५ रुपये आय हो तो १० रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष व्यय हुआ।

भारत सरकार की वैज्ञानिक पत्रिका ‘वैटनरी साइन्स एण्ड ऐनिमल-हैल्थिन्डरी’ के मार्च १९४१ के प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि औसत गाय को स्वस्थ रखने के लिये ५ सेर नित्य या वर्ष में ३६ मन मूँडा चारा चाहिये जिसका मूल्य अधिक से अधिक ३ रुपये प्रति मन के हिसाब से १०५ रुपये वार्षिक आता है। इस हिसाब से वह चारा

जो पशु वर्षा के दिनों में गोचर भूमियों में चरता है वह कम नहीं किया गया। सब खर्च लगा लिया गया है। तो अधिक से अधिक १०८ रुपये के चारे पर एक पशु जीवित रहता है।

जैसे कि आय के हिसाब में बतलाया गया है एक पशु से १२५ रुपये वार्षिक आय होती है। वह आगे में आपको बतलाऊंगा और गोसदन में रखने से १५ रुपये तथा घर में रखने से १०८ रुपये वार्षिक व्यय पड़ता है। इस हिसाब से [गोसदन में रखा जाने वाला ११० रुपया वार्षिक और घर में रखा जाने वाला १८) वार्षिक लाभ देता है। यदि सरकार और जनता दोनों गोबर और गोमूत्र को ठीक-ठीक उपयोग में लावे और मरे हुए पशु के चमड़े और हड्डी का ठीक-ठीक उपयोग हो तो एक वृद्ध, अपंग, अनुपयोगी कहलाने वाला पशु भी हानिकारक नहीं लाभदायक है।”

यह तो व्यय के हिसाब से हुआ,

अब आय के हिसाब से देखिए।

पंचवर्षीय योजना के १८ वे अध्याय के ‘कृषि उन्नति की कुछ समस्याएँ’ के २३ वे पैराग्राफ में लिखा है कि १९५१ की पशुगणना के हिसाब से ८०० मिलियन टन या अनुमानतः २२ अरब ५० करोड़ मन गोबर वार्षिक होता है। इसमें से आधा या सवा ग्यारह अरब मन खाद के काम और आधे के करीब जलाने के काम आता है। सिंदरी के कारखाने के ऐमोनियम सल्फेट का भाव जिसमें अनुमान २० प्रतिशत नाइट्रोजन होता है उसका मूल्य २८० रुपये टन है या १० रुपये प्रति मन है। गोबर का खाद ऐमोनियम सल्फेट से निस्सन्देह अच्छी चीज है पर उसमें नाइट्रोजन कम से कम २ प्रतिशत है, इस हिसाब से नाइट्रोजन के अनुपात को देखते हुए गोबर १ रुपया मन पड़ता है अर्थात् पंचवर्षीय योजना के लेखकों के अनुसार जो गोबर खाद के काम आता है उसका मूल्य १२ अरब रुपये होता है। ईंधन के काम आने वाले गोबर का

मूल्य खाद के काम आने वाले गोबर के बराबर नहीं पर कम से कम एक चौथाई के बराबर ३ अरब रुपये अवश्य है। इस हिमाव में दोनों खाद और जलाने वाले, प्रकार के गोबर का मूल्य १५ अरब रुपये में कम नहीं।

सभापति महोदय, यह आप के पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं।

“इसी परे २२ में लिखा है कि गोमूत्र का अनुमान इस गोबर से नहीं लगाया गया। १६.५०-५१ की पशु संख्या और पशु विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार सब पशु धन में साढ़े ६ अरब मन गोमूत्र मिलता है। इसमें से कम से कम २ अरब मन मूत्र खाद के काम और शेष व्यर्थ जाता है। गोमूत्र में नाइट्रोजन अधिक होता है फिर भी उसका काम से कम मूल्य ५ अरब रुपये होता है। गोबर और गोमूत्र दोनों में २० अरब रुपये आय होती है। देश में कुल [गोयन और भैर धन] पशु धन १६ करोड़ है। इन हिमाव में प्रति पशु कम से कम २५ रुपये बापिक गोबर और गोमूत्र से मिलता है। इस हिमाव में गोमूत्र सम्मिलित नहीं जो काम में लाया जा सकता है पर व्यर्थ जाता है। ईंधन के स्थान पर जला दिये जाने वाले गोबर का मूल्य भी कम लगाया गया है।”

मैं आपके सामने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कि जो यह कहा जाता है कि यह पशु वैकार है यह पशु अधिक दृष्टि से रखने के काम में नहीं हैं, यह बिलकुल गलत बात है। उन्होंने तो मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि पशुओं में कोई वैकार पशु है ही नहीं। फिर उनके ऊपर जो खर्च होता है और उनसे जो आय होती है उसका हिमाव भी मैंने अभी प्रस्तुत किया। उसने यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर जो खर्च होता है वह उनसे जो आय होती है उससे बहुत कम है।

एक और भ्रम इस सम्बन्ध में है कि जब आर्दामियों को ही खाना नहीं मिलता, अच्छे पशुओं के लिये ही चारा नहीं मिलता तो इन पशुओं के लिये खाना और चारा कहाँ से आयेगा? मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूँ कि इससे ज्यादा गलत बातें और कोई नहीं हो सकती। पहले तो जो बेकाम पशु कहे जाते हैं उनको हम दाना नहीं देते। वह पशु केवल चारा खायेगा और वह चारा भी ऐसा चारा नहीं होगा जोकि पशुओं को दिया जाता है। मैंने अनेक बार निवेदन किया है और फिर आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल में चले जाइये। आपको दोनों तरफ ऐसा चारा मिलेगा जो किसी काम में नहीं आता। जाड़े में शीत से जल जाता है, गरमी में गरमी से जल जाता है और बरसात में पानी से सड़ जाता है यदि गोसदन स्थापित किये जायें तो इस चारे का पूरा उपयोग हो सकता है। जोकि साधारणतः व्यर्थ जाता है। इसलिये जो यह बात बार-बार कही जाती है; जब आदमियों को खाना नहीं मिलता तो पशुओं के लिये कहाँ से आयेगा, जब अच्छे पशुओं को खाने को नहीं मिलता तो ऐसे पशुओं के लिये कहाँ से चारा आयेगा, यह बड़ी गलत बात है। दो हजार पशुओं के गोसदन पर कितना खर्च होता है इसके सरकारी अक मेरे पास मौजूद है। १६० गोसदनो की योजना सरकार ने बनाई है और उसमें यह रखा गया है कि एक-एक गोसदन में दो-दो हजार पशु रखे जा सकते हैं। अब इन गोसदनो का जो नानरिफरिंग यानी जो हमेशा न चलने वाला खर्च है वह ५०००० रुपये होता है और जो लगातार खर्च लगेगा वह होता है २०,००० रुपये। जो सरकार अपनी दूसरी योजनाओं में करोड़ों रुपया लगा सकती है, जिसने सिदरी फैक्टरी में अभी करोड़ों रुपये लगाये, जिसने ट्रैक्टरों में इतना धन खर्च किया, वह सरकार क्या इस प्रकार के गोसदन नहीं बना सकती जिसमें कि केवल उतना धन खर्च करना पड़ेगा जितना कि मैंने अभी आप से निवेदन किया, और जहाँ पर पशु के रखने के बाद वे पशु हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिये यह कहना कि इसके लिये धन नहीं है, गलत है। इनके लिये इच्छा नहीं है, धन की कमी नहीं। यदि इच्छा हो तो धन तो हमको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से यह पन्ना कभी भी हानिकारक नहीं हो सकते लेकिन अगर कुछ चीजें आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हों भी तो क्या हमें उन्हें करना नहीं चाहिये ? जिस समय हमारे देश में अकर्म तीन को जाती थी, उस वक़्त क्या हम को उसमें श्राव नहीं था, उस अकर्म या चीन भोजन हमने क्यों बन्द किया ? अभी कुछ दिन हुए हमारी राज्य सरकारों को अनाद ने बिनती अधिक आमदनी थी, हमने उस अनाद को बन्द क्यों किया ? अगर धन ही कमाना है तो सरकार और भी ऐसे काम कर सकती हैं जिसमें धन उमाया जा सकता है और जो कि नैतिक दृष्टि में ठीक नहीं हैं । आज हमने अकर्म को भोजन बन्द किया, हमने मरावा को बन्द किया, हमने नमक कर को उठाया । नमक कर का उठाना आन्ध्र लोगों को जो भावनाओं को उन्हीं के अनुसार तो हुआ । अगर हम इस अनाद को चलाता चाहते हैं तो क्या हम का सोयी की भावनाओं को नरक आन नहीं देना चाहिये । मैं बार-बार इस बात को कहा है कि आप इस देश में रिफॉर्मिज्म या नेशनलिज्म लीजिये, आप इन सम्बन्ध में जनता में समनमाना कर लीजिये और सिद्धय कि मोदी का इस सम्बन्ध में क्या मन है और मैं आगे बढ़ कर यह भी कहना चाहता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से यदि गोदय-निषेध आदि हानिकारक भी हों, हानाकि मैं इसे नहीं मानता, ना भी हमें लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करना ही होगा ।

इस विषय में मैं आपके सामने फिर महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा, वही रखना चाहता हूँ । गांधी जी ने यह कहा—

“बाजार में बिकने वाले वाली तमाग गाये ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले । तनाम बूढ़े, लूरे, लंगड़े और रोमी लोगों की रक्षा राज्य को करनी चाहिये ।”

डा० एन. टी. खरे—नेहरू जी क्या कहते हैं, यह कहते क्यों करते हैं ।

सेठ गोविन्ददास—आप अधीन न होइये, वह भी मैं आप को

घतलाऊगा। उस के पहिले में अपना भाषण समाप्त करने वाला नहीं हूँ।

श्री सी. आर. नरसिंहमन्—(कृष्णागिरी) अध्यक्ष महोदय ! कानूनी आपत्ति

श्रीमान् जी, हूँ यह विषय कौनसी सूची में मिलेगा, सर्व की सूची में या समवर्ती सूची में।

अध्यक्ष महोदय—कानूनी आपत्ति क्या है?

श्री सी. आर. नरसिंहमन्—क्या यह सर्व की सूची में मिलेगा या समवर्ती सूची में।

सेठ गोविन्द दाग—भाषति जी, जब सन् १९४६ में मैंने यह विषय उपस्थित किया था तो अनन्तजननग जी ने अपनी कृपित दी थी। आपने उस समय इन विषय को उठाया था और कहा था :—

श्रीमान् जी, इस विषय के सम्बन्ध में कि क्या यह विधेयक विपरीत है, उद्देश्यो और कारणों का उल्लेख किया गया है। मेरा नम्रतापूर्वक यह विचार है कि केवल उद्देश्य और कारण ही यह देखने के लिये काफी नहीं है कि अनुक विधेयक अनुकूल है या प्रतिकूल, यदि हम विधेयक की भाषा को देखे तो इसका प्रयोजन यह लगता है कि यह इसके लिये ही दंड निर्धारित करना चाहता है जैसा कि भारतीय दंड विधि संहिता में वर्तमान है। उस दंड विधि के अनुसार ५० रुपये या इससे अधिक मूल्य के पशु को लंगडा करने या मारने का अपराध घोषित किया गया है और इसलिए यह शक्ति है कि जो प्रविष्टियों का उल्लेख डाक्टर अम्बेदकर द्वारा किया गया है इस मुकदमे पर लागू होंगी या नहीं। मैं जानता हूँ कि इन प्रविष्टियों का प्रयोग प्रान्तीय विषयों से सम्बन्ध रखता है परन्तु उसी प्रकार यदि इस विधेयक पर दंड निर्धारित करने की दृष्टि से विचार करना है तो मेरा नम्रतापूर्वक कहना है कि इस प्रकार के अपराध पूर्ण विषयों पर राज्य तथा केन्द्र दोनों को अधिकार है। उदाहरण के लिए प्रविष्टि १ सूचि २ में ऐसे अपराधों का वर्णन है और

यदि ये अपराध ऐसे हैं जो भारतीय दंड विधि संहिता में सम्मिलित हैं तो मेरा नज़रता पूर्वक निवेदन है कि फिर इन प्रकार पूर्णतया यह नहीं कहा जा सकता कि कोई बन्धन है।

अध्यक्ष महोदय ने तब कहा :—

“माननीय सदस्य चाहते हैं कि कृपि मंत्री महोदय अपने तर्क की और प्रवृत्त बनायें, जहाँ तक इस विशेष बात का सम्बन्ध है उसको कई बार रोका जा चुका है। अध्यक्ष के लिए यह मार्ग चुना नहीं कि वह उन उलझे हुये प्रश्न में पड़े। वास्तव में मैं एक ऐसे निर्णय का उल्लेख कर सकता हूँ जिसका वर्णन, अध्यक्ष के निर्णय के पृष्ठ ३२ पर है।

मल्टी यूनिट बोरोपेंटिव सोसाइटी बिल (अनेक नष्टवस्तु सहकारी समितियों) पर वाद-विवाद के समय श्री के. सी. त्रिभोगी ने विधान सभा के उन अधिकारों के सम्बन्ध में एक आपत्ति उठाई थी। जिसका वर्णन १९३५ के इंडिया एक्ट की संघ की तथा प्रान्त के विधान की सूचिया है।

कानूनी आपत्ति ! प्रायः आपत्ति उठाने के प्रश्न उन विषयों से सम्बन्धित होते हैं जिनके अनुसार सदन की कार्यवाही चलती है यह बड़े महत्व की बात है कि क्या विधान सभा को ऐसे विधेयक स्वीकार करने का अधिकार है या नहीं और मेरा मत है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना सदन का काम है। उसके अनिश्चित अन्य विषयों पर कि विधेयक पास किया जाये या नहीं, कोई निर्णय लेना भी सदन का ही काम है।

निश्चय ही इस प्रकार की आपत्तियों पर भी विचार करना सदन का ही काम है जो कि उठाई गई है और कहा गया है कि इस विधेयक के प्रति इस सदन को कोई अधिकार प्राप्त है या नहीं।

एक सदस्य—ईस हलिंग का यह निर्णय सम्पूर्ण क्यों पढ़ा गया है।

श्री एस. वी. रामास्वामी (मेलम) जब कोई आपत्ति उठाई जाती है तो हलिंग अध्यक्ष द्वारा ही दिया जाता है न कि माननीय सदस्य द्वारा।

अध्यक्ष महोदय—मैंने विधेयक उपस्थित करने वाले सदस्य को

उसने इस आपत्ति पर जो कुछ कहना है कहने की आज्ञा दे दी है। यह नहीं होता कि अध्यक्ष कोई हलिंग ही न दे। पर यह भी होता है कि अध्यक्ष मुनता रहे और कोई दूसरा सदस्य और विशेषकर विधेयक को उपस्थित करने वाले को जो कुछ वह इस सम्बन्ध में कहना चाहता है कहने दिया जाता है।

श्री एस. वी. रामास्वामी—श्रीमान् जो क्या मैं जान सकता हूँ...

अध्यक्ष महोदय—क्या माननीय सदस्य कानूनी आपत्ति के संबंध में ही कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एस० वी० रामास्वामी—पाइन्ट आफ आर्डर आपत्ति में विशेष बात क्या है।

अध्यक्ष महोदय—एक विशेष बात पर कानूनी आपत्ति उठाई गई थी और उसका उत्तर दिया जा चुका है। यदि वह कोई और कानूनी आपत्ति उठाना चाहते हैं तो मैं आज्ञा दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि वह उसी कानूनी आपत्ति के बारे में कुछ कहे।

सेठ गोविन्ददास—तो क्या मैं इसे और पढ़ूँ।

इसलिये यदि सदन की इच्छा है तो इस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं अन्यथा इसे अस्वीकार कर दें। यह कार्य न्यायालयों का है कि वे देखें कि यह विधेयक सराद के अधिकारों के अनुसार है अथवा नहीं। इस समय मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि यह कह सकूँ कि वह ठीक नहीं है। यह माननीय सदस्य का काम है कि इस कानूनी आपत्ति को ध्यान में रख कर जो उचित समझे निर्णय लें और यदि यह सिद्ध हो जाए कि यह विधेयक जो सदन ने पास किया है व्यर्थ है। तो इसका उत्तरदायित्व उस पर होगा। अब यह उस पर है कि निर्णय करे।

मैंने फिर कहा—

मैं विधेयक को वापिस लेना नहीं चाहता और अब मैं अपना भाषण दूंगा।

टिप्टो स्पीकर ने कहा—मैं माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने को नहीं कर रहा अध्यक्ष की ओर से ऐसा कोई मुझाव या प्रस्ताव नहीं है। यह उस पर है कि जो चाहे सो करे।

और उसके बाद मैंने अपना भाषण दिया।

श्री एम० बी० रामान्वामी—उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय—मैं माननीय सदस्य को तब तक बोलने का आजा नहीं दूँगा। जब तक वह एक नई आपत्ति नहीं उठाता।

श्री एम० बी० रामान्वामी—हाँ थियान् जी, मुझे एक नई आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय—हाँ अब वह बोल सकते हैं परन्तु इसके पूर्व कि वह दूसरी आपत्ति उठायेँ मुझे पहली आपत्ति को पूर्ण कर लेने दिया जाय, क्योंकि नियमानुसार दो आपत्तियाँ एक ही समय में नहीं उठाई जा सकती। पहले पूर्व की आपत्ति को समाप्त करना है। मैंने उस सदस्य का भाषण सुन लिया है जिसने इस विधेयक को उपस्थित किया है, क्या यह वही विधेयक है या कोई और?

सेठ राविन्द्रदास—बिन्कुल यही विल था।

अध्यक्ष महोदय—यह वही विधेयक है कि जिस पर आर्यन उठाई गई थी। उस समय उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने इस आपत्ति पर अपना निर्णय दिया था जो कि सदन को पढ़कर सुनाया गया था, वह निर्णय यह था कि अध्यक्ष अन्तिम निर्णय करने का अधिकार अपने ऊपर नहीं लेता। यहाँ तक कि अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सदन को सौंप दिया मैं पहले निर्णय को प्रस्तीकार करने को न्यायोचित नहीं समझता, इसलिए मेरा कहना है कि जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है उपाध्यक्ष महोदय का पूर्व निर्णय ही उचित और न्याय संगत है और सदन को विधेयक पर वाद-विवाद आरम्भ करना चाहिए।

सेठ गोविन्द दास—धन्यवाद । मैंने अभी आपके सामने कुछ उन बातों को रखा कि जिन बातों के आधार पर मैं ..

श्री एस. बी. रामास्वामी—श्रीमान् जी, प्रविष्टि १५ सूची २ की है ।

अध्यक्ष सहोदय—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूँगा कि वह अपनी आपत्ति उठाये और कुछ पढ़ें नहीं । आपत्ति के सम्बन्ध में नियम यह है कि आपत्ति संक्षेप में ही उपस्थित की जाये । आपत्ति क्या है ?

श्री एस. बी. रामास्वामी—श्रीमान् जी, यह भोरक्षा और परि-रक्षण का कार्य २ सूचि की प्रविष्टि १५ के अनुसार है । यह दूसरी सूची राज्य सूची है । श्रीमान् जी मैं कह रहा हूँ कि इस सूचि के अनुसार यह विधेयक इस सूची के अनुसार चलेगा या संघ सूची के अनुसार ।

अध्यक्ष सहोदय—यह वही आपत्ति है जो पहले माननीय सदस्य ने उठाई थी और डा० अम्बेदेकर ने उसी समय यह आपत्ति बिलकुल बर्ती है इसलिये इस को नहीं उठाया जा सकता ।

सेठ गोविन्द दास—सभापति जी, अब तक मैंने आपके सामने यह रखा कि इस देश में संपूर्ण गोवध क्यों बन्द होना चाहिए । अब इसके बाद मैं आपके सामने उस विषय को उपस्थित करना चाहता हूँ कि जिससे उपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है । और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक उपयोगी पशुओं के कत्ल बन्द करने का विषय है उस में कोई मतभेद नहीं हो सकता । तब प्रश्न उठता है कि क्या उपयोगी पशुओं का वध रुका हुआ है । मेरा दावा है कि आज सब से अधिक उपयोगी पशुओं का ही वध होता है और जब मैं यह कहता हूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूँ । आप बम्बई मद्रास के कसाई खाने को जाकर देखिये और देखिये कि वहाँ पर उपयोगी पशु मारे जाते हैं या अनुपयोगी पशु मारे जाते हैं । इन उप-योगी पशुओं का वध भी, बिना गोवध कतई बन्द किये रुक नहीं सकता । सरकार ने इसका बहुत प्रयत्न किया । उपयोगी पशुओं के वध

को रोकने का प्रयत्न आज ही नहीं उठा है। सरकार ने इसके कई प्रयत्न किये हैं लेकिन उन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। सब से पहला प्रयत्न उस सम्बन्ध में हुआ था। तारीख ११ जुलाई सन् १९४४ को, जबकि स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय की अंग्रेजी सरकार ने, एक आजा पत्र जारी किया था कि उस मान के नीचे की उम्र के पशु न मारे जायें। वह आजा पत्र इस प्रकार था :—

मुझे यह निर्देश हुआ है कि मैं यह कहूँ कि गत कुछ समय से पशुओं का वर्तमान अभाव सरकार के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। यायद् यह अभाव इसलिये है कि पशुओं की खेती करने, भार उठाने तथा दूध और मांस प्राप्त करने के लिए मांस बहुत बढ़ी हुई है इस समय को मुलमान का एक ढंग यही सोचा गया है कि जहां तक सम्भव हो वहां तक उपयोगी पशुओं की हत्या को बन्द किया जाये और विशेषकर ऐसे पशुओं की जो उपयोग में आते हैं या आ सकते हैं और जो नसल बढ़ाने की दृष्टि से अर्था उपयोगी हैं।

२, इस के अनुसार पशु-हत्या के सम्बन्ध में फौजी अधिका-रियों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि—

(क) निम्नलिखित पशुओं की बिक्री और हत्या बन्द की जाये।

१. तीन वर्ष से कम आयु के पशु,
२. ऐसे नर पशु जिन की आयु ३ या १० वर्ष के बीच है जिनको कार्य में प्रयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है।
३. ३ वर्ष से १० वर्ष तक की आयु की सभी गायें जो दूध देने के योग्य हैं, उनके अतिरिक्त जो नसल बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं।
४. सभी गायें जो गर्भिणी हैं या दुधारू हैं।

१९४४ में सरकार ने इस आजा को जारी किया था। इसका कोई फल नहीं निकला। इसका क्या नतीजा हुआ, उस सम्बन्ध में वर्तमान में

क्या हुआ यह मैं आप को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बर्मा उस समय भारत वर्ष का एक हिस्सा था ।

इस उद्देश्य से कि पशुवध पर जहाँ तक हो सके प्रतिबन्ध लगाया जाये सरकार ने गत वर्ष बर्मा के सुरक्षा कानून के अनुसार एक नियम लागू किया जिसके अनुसार विशेष प्रकार के पशुओं का ही वध हो सकता है । परन्तु यह बड़े दुःख का विषय है कि ऐसे प्रतिबन्धों ने पशु संख्या में कोई भी उन्नति का चिह्न दिखाई नहीं दिया । सरकार इस बात को भली-भाँति जानती है कि उपयोगी पशु और बछड़े बछड़ियों की किस प्रकार निर्मम हत्या भाँस और खालों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है ।

बर्मा सरकार के अतिरिक्त हमारे यहाँ दूसरे प्रान्तों में भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला । इसके बाद (डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स) भारत रक्षा कानून समाप्त होते ही यह-आज्ञा पत्र भी खत्म हो गया । उसके उपरान्त स्वराज्य की प्राप्ति के बाद सन् १९४७ के नवम्बर में जो (कैटल प्रिजर्वेशन) पशु रक्षा कमेटी बनाई गई, उसने जो कुछ कहा वह मैं आपके सामने अभी पढ़ चुका हूँ । उस पर श्री जयरामदास दौलतराम जी ने जो कुछ कहा वह भी मैं आपको बतला चुका हूँ । अब देखने की बात यह है कि जयरामदास जी की उस घोषणा के बाद, जिस घोषणा के अनुसार कि १४ वर्ष की उम्र के नीचे के पशु का वध रुकना चाहिए था, कहाँ-कहाँ पर क्या हुआ ? मद्रास, ट्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, बिहार । उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ । आसाम में कानून बना, पर लागू नहीं किया गया । सन् १९५० में बम्बई, बंगाल और हैदराबाद में कानून बने, पर दो साल यों ही रहे, लागू नहीं हुए, सन् १९५२ तक । और अब लागू हुए, तब भी क्या हुआ वह सुनिए । पूरे प्रान्त में वह कानून लागू नहीं किये गये । बम्बई और बंगाल में चौदह-चौदह म्युनिसिपल बोर्डों में और हैदराबाद में २२ में लागू किए

गए । अर्थात् इनके बाहर, बम्बई में १४ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर, बंगाल में १४ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर और हैदराबाद में २२ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर कल हो सकता है । बंगाल में फिर १५ मार्च सन् १९५२ को कसाइयों के आन्दोलन पर यह रोक दिया गया, फिर १ फरवरी को लगाया गया । फिर क्यों कि इन क्षेत्रों के बाहर गोवध हो सकता था इसलिये कानून की मंशा पूरी नहीं हुई । केवल हमारे प्रान्त में ही वह कानून बना जिस के द्वारा गोवध बन्द किया गया । अब जहाँ गोवध पहले बन्द था और हमारे यहाँ जो बाद में यह गोवध बन्द किया गया वहाँ पर एक गश्ती चिट्ठी पहुँच गयी भारत सरकार की ओर से । उस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा गया ?

श्री कुंनकुनवाला—(भागलपुर मध्य) आपका कौन से प्रान्त से मतलब है ?

सेठ गोविन्ददास—मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा था । एक मात्र केवल मध्यप्रदेश है, सारे देश में, कि जहाँ स्वराज्य के बाद गोवध बन्द किया गया । कुछ प्रान्तों में यह गोवध पहले से बन्द था । अब जिन प्रान्तों में यह पहले से बन्द था और जहाँ मध्य प्रदेश में यह बाद में बन्द किया गया वहाँ यह गश्ती चिट्ठी पहुँची । २० दिसम्बर १९५० को यह गश्ती चिट्ठी भारत सरकार की ओर से गयी ।

“मुझे यह लिखने का आदेश दिया गया है कि भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य सरकारों ने पशुवध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है और अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही हैं । इस सम्बन्ध में कानूनी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से कुछ विचार करने की आवश्यकता है । जहाँ तक इस का कानूनी सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्य सरकारों को यह भ्रम हो गया है कि भारत का विधान पशुवध को पूर्णतया समाप्त करता चाहता है । इस समय विधान के चौथे भाग की धारा ४८ का

जिसमें कि राज्य की नीति निर्धारित की गई है वहां वर्गान् करना अनुपुक्त ही रहेगा ।

इस सम्बन्ध में आप को बतला चुका हूं कि संविधान की उस धारा का मेरे अनुसार भी यही मतलब है । काउज और वाउज, (गाय और बछड़े) के सम्बन्ध में उस धारा का स्पष्ट मत है वह मेने आपके सामने पढ़कर बतला दिया है । अब आगे हैं ।

ऊपर की धारा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस धारा का उद्देश्य सम्पूर्ण पशुवध बन्द करना नहीं ।

यहाँ मैं सहमत हूं, सब पशु पर नहीं दुधार पशुओं का वध बन्द करता । अब देखिए कि यह जो गश्ती चिट्ठी गई वह कैसी निश्चित चिट्ठी है—

ऊपर की धारा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस धारा का उद्देश्य सम्पूर्ण पशुवध नहीं केवल गाय, बछड़े, बछड़ियों और अन्य दुधार तथा भारवाहक पशुओं का वध बन्द करना है ।

ठीक है पर गाय बछड़े बछड़ी और अन्य दुधार तथा भारवाहक पशुओं की हत्या बन्द करना ठीक है, जो गश्ती चिट्ठी जाती है उसका भी यही मतलब है जो मेने संविधान की धारा का बतलाया कि जहां तक गाय और बछड़े का सयान है वहां तक (टोटल) सम्पूर्ण वध निषेध होना चाहिए और जहाँ तक दूसरे जानवरों का सवाल है वहाँ कितने एंड स्लाइट कैटल का वध बन्द होना चाहिए ।

अब आगे देखिए कि इस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा है —

“जहां तक इस प्रश्न पर आर्थिक दृष्टि से विचार करने का सम्बन्ध है पशुवध पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना व्यर्थ सिद्ध होगा ।

इसका उत्तर भी मैं आपके सामने सिद्ध कर चुका हूं कि यह प्रश्न आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं है ।

फिर जो असली बात है, जिससे बिल्ली थैले में से निकल आती है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं ।

निर्यात के दृष्टिकोण से भी इस समस्या का बड़ा महत्व है। वध करके जो खाल प्राप्त होती है उसका अधिक मूल्य प्राप्त होता है। यदि गोवंश का वध बन्द कर दिया गया तो उत्तम प्रकार की खालें जो बाजार में मंहगी बिकती हैं वे नहीं मिलेंगी। इस प्रकार पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द करने से विदेश के व्यापार और विदेश के चमड़े के उद्योग की भारी हानि होगी।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उनको दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार को आना है कि राज्य सरकारें पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द करने से जो हानि होने वाली है उसे ध्यान में रखते हुए और देश के आर्थिक तथा अन्य हितों को दृष्टि में रखते हुए अनुपयोगी पशुओं के वध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगी।

इसके आगे फिर देखिए—

“जिन राज्यों में सरकारों ने पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द कर दिया है उनसे प्रार्थना है कि वह इस पर पुनः विचार करें।”

सौभाग्य की बात है कि इस संकुलर के जाने के बाद भी मेरे प्रान्त में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया.....

अध्यक्ष महोदय—क्या वह परिपत्रक वापिस नहीं ले लिया गया।

मेठ गोविन्ददास—मैं नहीं जानता कि वह संकुलर वापिस किया गया है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, कौन्सिल आफ स्टेट में हाल ही में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पृछा गया था और उस समय हमारे कृपि मन्त्री जी ने फिर इसी संकुलर लेटर का हवाला दिया था। जिसका अर्थ यह होता है कि अभी तक वापिस नहीं किया गया है। २० दिसम्बर सन् १९५० का पत्र २३ दिसम्बर सन् १९५२ को कृपि मन्त्री महोदय ने जो पटना में घोषणा की वह मैंने पढ़ी, हाल ही में कौन्सिल आफ स्टेट में जो कुछ कहा गया वह भी मैंने बताया, चूँकि उस समय सौभाग्य से श्री किदवई यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैं उनकी घोषणा को फिर पढ़े देता हूँ।

पटना, २३ दिसम्बर १९५२, आज यहां श्री रफी अहमद किदवई खाद्य मन्त्री भारत सरकार ने कहा कि "जब देश में गोहत्या को बन्द करने के पक्ष में इतना अधिक जनमत है तो इसका आदर होना चाहिए क्योंकि जनतन्त्र तभी सफलता पूर्वक चल सकता है।"

अगर वह कह दें कि उन्होंने उस गश्ती चिट्ठी को वापिस कर दिया

अध्यक्ष महोदय—इस सदन में कुछ समय पूर्व कहा गया था। यह प्रपत्रक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा वापिस ले लिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री किदवई—मुझे इस प्रपत्रक के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसे वापिस ले लिया गया।

अध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री से पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि इसे वापिस ले लिया गया।

श्री किदवई—मुझे स्मरण नहीं है कि क्या कहा गया था। यदि मुझसे पहले मन्त्री महोदय ने ऐसा कहा था तो उसे वापिस लिया गया ही समझ लेना चाहिए।

सेठ गोविन्ददास—बहुत खुशी की बात है। अतः अभी कौंसिल आफ स्टेट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मन्त्री जी ने जो कहा वह भी वापिस हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए और मैं उनको इस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय—राज्य परिषद में जो कुछ हुआ था वह एक तारा अंकित (Unstarred Question) प्रश्न के उत्तर में था जो उपस्थित किया गया था।

सेठ गोविन्ददास—अभी कौंसिल आफ स्टेट में इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर में श्री किदवई ने इसी सर्कुलर को वहां पर बतलाया था या नहीं बतलाया था।

श्री किंदवाई—जब यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर दिया गया तब मैं वहाँ नहीं था। जो कुछ भी मंत्रालय में होता है वह मन्त्री महोदय की आज्ञा से ही होता है।

सेठ गोविन्ददास—मे यह जानना चाहता हूँ सभापति महोदय ! कि उनके डिप्टी मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, यह उनको भी नहीं मालूम ?

श्री बी. जी देशपांडे—(गुणा) पर अब केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

सेठ गोविन्ददास—यह जो सकुनर भेजा गया था, वह अभी भी मौजूद है या वह उठा लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछ सकता है और माननीय मन्त्री महोदय उसका उत्तर देगे।

सेठ गोविन्ददास—तो मैं कृपि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि २० दिसम्बर को जो गश्ती पत्र गया अब उस पत्र की क्या स्थिति है ? वे कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, मुझे बड़ा दुःख है कि शायद किंदवाई साहब भी यह नहीं जानते कि वह पत्र मनसूख या रद्द हुआ या नहीं।

श्री श्यामनन्दन सहाय—(मुजफ्फरपुर मध्य) पता लगायेंगे।

सेठ गोविन्ददास—तो हम ने यह देखा कि सरकार ने इस बात का लाख प्रयत्न किया कि उपयोगी जानवर न मारे जायें, पर ये सब प्रयत्न निष्फल हुए और आज भी उपयोगी जानवरों का वध हो रहा है, अब यह मामला सभापति जी, और आगे बढ़ गया है, अब कसाईखानों में ही वध नहीं होता, बल्कि घरों में भी वध होने लगा है। इसके सम्बन्ध में समय-समय पर समाचार पत्रों में कई खबरे छपती हैं और इस संबंध में कितने ही मुकदमे चलते हैं और लोगों को सजाये होती हैं। मैं आप को उन स्थानों के नाम बता देना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार की कार्रवाई हुई है जो अखबारों में छपी है, जहाँ मुकदमे चले हैं और जहाँ

लोगों को सजाये हुई हैं और जहाँ आज भी मुकदमे चल रहे हैं। यह जगह हैं, बिजनीर, नगीना, हरिद्वार, टोंक, मुरादाबाद, अल्मोडा, बुलन्द-शहर, मथुरा, आगरा, मेरठ, हरदोई सहारनपुर, गुड़गांव और जीन्द। आप आज्ञा दें तो मैं इन जगहों के हाल पढ़कर भी सुनाऊँ।

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य ने यह बताया है कि कहां कहां हो रहा है। मुकदमों की कार्यवाहियों को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

सेठ गोविन्ददास—फिर बम्बई और कलकत्ते में इस नम्बन्ध में क्या हो रहा है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। सब से ज्यादा गोवध कहां हो रहा है तो वह बम्बई, कलकत्ते, मद्रास आदि में हो रहा है। बम्बई में अभी हाल ही में श्री मुरारजी देसाई से एक शिष्टमंडल मिला था और इस शिष्टमंडल में आपको यह सुनकर खुशी होगी कि कसाई भी गये थे। उस शिष्टमंडल का थोड़ा सा हाल बतला दूँ।

“बम्बई जीव दया मंडल, वान्दरा और कुर्ला की कसाई सघ और बडौदा के कसाईयो के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल श्री जे. एन. मानकर की प्रधानता में मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई और मान, जंगल तथा कृषि विभाग के मंत्री श्री हीरे से क्रमशः ७ और ८ अक्टूबर १९५२ को बम्बई तथा अन्य शहरों में हो रहे बहुत बड़ी संख्या में गैर कानूनी पशुवध के बारे में बातचीत करने के लिए मिला। शिष्टमंडल के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान म्युनिसिपल कानून के अनुसार लायसेंस प्राप्त बूचड़खाने से बाहिर पशुवध करना अपराध है। इसी प्रकार १९४८ के बम्बई राज्य पशुपरिरक्षण कानून के अनुसार बिना किसी पशु डाक्टर से आज्ञापत्र प्राप्त किये जोकि इस कार्य के लिए विशेष रूप में नियुक्त किया जाता है, पशुवध गैरकानूनी है। इसके होते हुए भी बम्बई नगर में कई स्थानों पर विशेषकर सांकली स्ट्रीट, मदनपुरा मिर्जारीट्रीट, उमरखादी, खम्बेदकर स्ट्रीट में उपयोगी दुधारू, कृषि उपयोगी पशु और बछड़े बछड़ियों का रात्रि में गुप्तरूप में घरों में वध होता है। इस गैरकानूनी वध

को रोकने के लिए म्युनिसिपल तथा पुलिस अधिकारियों को कई बार दिकायत की गई। फिर भी काफ़ी अधिकारों के अभाव में या उपेक्षा के कारण अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं।

यह बम्बई का हाल है। अब कलकत्ते का हाल सुनिये ! कलकत्ता कारपोरेशन की १३ फरवरी १९५३ की मीटिंग में श्री तुलसीराम मरावगी ने कहा—

गैरकानूनी हत्या की समस्या को अभी सुनसाना है कलकत्ता के आमपास गोहत्या होती है और गुप्त रूप में मांस मंडी में लाया जाता है, अन्वेषण यह कैसे सम्भव हो सकता है कि कारपोरेशन के टागरा के बूचड़खाने में हत्या कम हो रही है परन्तु मांस के व्यापार में कोई कमी नहीं हुई ? जब इस विषय में कमिश्नर और डिप्टी मेयर महोदय को सूचित किया गया तो उन्होंने इसके अनुसार एक दम कार्य आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता के बाहर के किसी स्थान में गैर-कानूनी रूप में पशुबध से प्राप्त गोमांस से लदी हुई एक कारी होग कार-केट के दरवाजे पर ही पकड़ी गई और इसके पकड़ने में स्वास्थ्य कमिश्नर डा० जे० पी० चौधरी ने सहायता दी। यह घटना उसका संकेत है जो पर्दे के पीछे हो रहा है और मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि इस प्रकार गैर कानूनी रूप में कलकत्ता से बाहर पशुबध करके और मांस प्राप्त करके नगर में लाना जोरों पर जारी है।

मैंने आपको यह बतलाने का प्रयत्न किया कि केवल उपयोगी पशुओं का बध कसाईखानों में किया जाता है, इतना ही नहीं, लेकिन यह बध अनेक शहरों में मैंने आपको पढ़कर सुनाया, बढ़ रहा है, बम्बई और कलकत्ते में यह कितनी दूर तक हो रहा है, यह मैंने आपको अभी निवेदन किया। अब उपयोगी पशुओं के बध का प्रधान कारण क्या है। यह मैं आपको केवल दो बातों में कहना चाहता हूँ इसके सम्बन्ध में। इसका प्रधान कारण है मांस के निर्यात और चमड़े के निर्यात के तीन बन्दरों

के आंकड़े मेरे पास हैं। यहाँ २२ वन्दर अर्थात् मी पोर्टन हैं, उस देश के २२ वन्दरों से कितना मांस बाहर जाता है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह मुझे मिल नहीं सके, लेकिन जिन तीन वन्दरों के आंकड़े मिले वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीन वन्दरगाहों से १ जुलाई १९५२ में ३० हज़ १६५३ तक निम्न रुपये का गोमांस भारत में अन्य देशों को भेजा गया।

बम्बई	३१	६९	६६६	रुपये
कलकत्ता	२१	६६	३४७	रुपये
मद्रास	२	६६	१३६	रुपये
कुल जोड़	५६	३८	४५२	रुपये

एक वर्ष में केवल तीन वन्दरों ने यह गोमांस बाहर रखा है। श्री करमरकर को मैंने यह आंकड़े दिये थे। उनको इन आंकड़ों को देख कर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि वे इसका पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन कई महीनों तक प्रतीक्षा करने पर भी अब तक इसका कोई पता नहीं लगा। यह तो मैंने मांस के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े आपके सामने रखे हैं जो मांस का निर्यात हमारे देश के २२ वन्दरों में से केवल तीन वन्दरों से हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना अच्छे पशुओं को मारे अच्छा मांस नहीं मिल सकता, और अच्छा मांस ही बाहर जा रहा है, इसलिए प्रधानतया अच्छे पशु यहाँ पर मारे जा रहे हैं।

फिर चमड़ा भी बाहर जा रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊँ कि १० वर्ष के पहले कितना चमड़ा बाहर जाता था और आज कितना चमड़ा बाहर जाने लगा है। इसके लिये कहा जायेगा कि चमड़ा जो बाहर जा रहा है वह बेकाम पशुओं का होगा। पहले मैं आपसे यह निवेदन कर दूँ कि जिस प्रकार बेकाम पशुओं का मांस अच्छा नहीं होता उसी प्रकार बेकाम पशुओं का चमड़ा भी अच्छा नहीं होता और अभी जो मैंने

आपके सामने पंचवर्षीय योजना और दूसरी चीजें पढ़ी, उससे भी आपको पता लगेगा कि अच्छे चमड़े से हम को अधिक दाम मिलें इसलिये हम अधिकतर अच्छे जानवर मारते हैं। खैर आप बड़े जानवरों को छोड़ दीजिये, आप बछड़ों को लीजिये। बछड़ों के लिये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे बेकाम हैं और मारे जायें। १९४२-४३ में केवल ढाई लाख खालें इस देश से बछड़ों की बाहर गईं, १९४६-४७ में जब स्वराज्य हुआ उस वक्त १ लाख २० हजार खालें बाहर गईं। यह जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ यह "एग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन इण्डिया (भारतीय कृषि बाजार) रिपोर्ट और "फारेन एण्ड एग्रर नैविगेशन" (विदेश का आकाश तथा जल व्यापार) नामी पुस्तकों से दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि १९४२-४३ में ढाई लाख, १९४६-४७ में एक लाख २० हजार और १९५३-५४ में २० लाख १८ हजार बछड़ों की खालें इस देश से बाहर गयीं। यह आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। आपके सामने यह पुस्तकें हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सरकार के महकमे का इन पुस्तकों को देखे और बतलावे कि यह सही है या नहीं।

फिर जो गायों का चमड़ा यहाँ से सन् १९५२-५३ में बाहर गया है वह भी देख लिया जाये, वह भी कम नहीं है। कुल गायों का चमड़ा गया है उसकी संख्या ४६ लाख ९६ हजार और १७३ और इस की कुल कीमत ७, ५६, ०६, १७३ रुपये। यह कुल गायों का चमड़ा है, बछड़ों के चमड़े इसमें अलग हैं।

यथार्थ में जो हमारे यहाँ उपयोगी पशुओं का बध होता है, वह इसलिये होता है कि हम गोमांस का निर्यात करते हैं, हम चमड़े का निर्यात करते हैं और इसके लिये उपयोगी पशु ही काम में आ सकते हैं। जो पशु बेकार हो जाते हैं वह काम में नहीं आते, अतः सभाषति महोदय मेरी दृष्टि से गोबध कतई बन्द हुए बिना यह प्रश्न हल नहीं होगा।

बार बार एक बात और कही जाती है कि गाय हम देश में निकम्मी क्यों है, जबकि अन्य देशों में अच्छी है। जो अन्य देश गोमयक है वहाँ पर तो गायें बहुत अच्छी हैं और हमारे यहाँ निकम्मी हैं। हमारे देश में गाय के निकम्मी होने का पहला कारण तो यहाँ पर अंग्रेजी राज्य का रहना था। अंग्रेजों ने गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से यहाँ पर गाय की उन्नति नहीं हुई। खेती की उन्नति नहीं हुई। दूसरा कारण गायों के अच्छी न होने का यह है कि अच्छी गाय को कत्ल कर दिया जाता है, जब अच्छी गायें कत्ल की जायेंगी तो बुगी तो बचेगी ही। फिर आज हम गाय को अच्छी बनाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, यह भी आप देखिए। हम दो पैसे प्रति वर्ष, प्रति पशु खर्च करते हैं और मैं आपको इंग्लैण्ड का उदाहरण दूंगा कि वहाँ पर कितना खर्च किया जाता है। वहाँ पर ५ रुपया खर्च किया जाता था। इंग्लैण्ड में जो कुछ किया गया था वह भी मैं आपको बतलाता हूँ—

“हर जनप्रिय स्वतन्त्र राज्य अपने कर्तव्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। वह अपना अधिक से अधिक ध्यान अपनी जनता को अच्छे से अच्छे भोजन के प्रदूषण की ओर देता है। इन अच्छे से अच्छे भोजन में दूध को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है—

श्री भगवत मा आजाद—[पूणिया और सन्थाल परगना]
श्रीमान् जी क्या हम यह जान सकते हैं कि माननीय सदस्य और कितने घण्टे लगायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय—जहाँ तक ऐसे विधेयक पर समय के बारे में प्रश्न पूछने का सम्बन्ध है, नियम यह है कि समय की कोई सीमा नहीं होती। पर मैं माननीय सदस्य से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह अधिक समय न लगायें। पहले दिन उन्होंने आधा और आज एक घण्टा और १० मिनट ऊपर ले लिया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ

अन्य सदस्यों को भी समय दें। वह इस बात को अनुभव करेंगे कि आज के कार्य में सदस्यों के किमी विधेयक (प्राइवेट मेम्बरज दिवज) के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय का एक प्रस्ताव है जो कि विधेयक की हर स्थान पर चार घन्टों की सीमा निश्चित करता है, इसलिये मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह समय का ध्यान रखें।

सेठ गोविन्ददास—भाषति जी, मुझे तो इस विधेयक पर अभी भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन चूँकि आपकी आज्ञा है इसलिये मैं बहुत जल्दी खतम करूँगा।

श्री किदवाई—मेरा विचार है उनको पूरे चार घन्टे का समय दिया जाय ताकि वह विधेयक के हर विषय पर अच्छी प्रकार प्रकाश डाल सकें।

श्री बी. पी. नायर—श्रीमान् जी, हममें से कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं।

सेठ गोविन्ददास—मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था क्योंकि यह तो मेरे जीवन भर का प्रश्न रहा है।

एक माननीय सदस्य—क्या समय बढ़ाया जा सकता है ?

श्री किदवाई—समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री बी. पी. नायर—इस वाद-विवाद में हम में से भी कुछ सदस्य भाग लेना चाहते हैं,

सेठ गोविन्ददास—मैं बहुत जल्दी खतम कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न एक से अधिक सदस्यों ने उठाया है और है भी यह उचित ही कि अन्य सदस्य भी यह आशा करें कि उनको भी बोलने का समय मिलेगा।

सेठ गोविन्ददास—मैं बहुत जल्दी खतम कर रहा हूँ।

जब से ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की है, ब्रिटेन में वहाँ के पशु और दूध में बहुत उन्नति हुई है। आगे देखें कि उन्होंने अपने देश में क्या किया है।

उसमें उन्होंने १,८५,८४,५८४ पाउंड खर्च किया वृद्ध में और फिर वह खर्च बढ़ते-बढ़ते २,६४,६६,०५५ पाउंड तक पहुँचा यानी आठ वर्ष में उन्होंने इतना खर्च किया जिसका मतलब यह होगा कि ४० करोड़ रुपया खर्च किया। आप देखें कि हम अपनी अन्य योजनाओं पर तो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन हम इनपर कुछ खर्च करने को तैयार नहीं। तो जब अच्छी गायें मार डाली जायेंगी तो दुरी तो बचेगी ही। जब हम उनपर कुछ खर्च नहीं करेंगे तो उनकी उन्नति कैसे हो सकती है। यह कहना कि गांधीवादी देशों में तो अच्छी गायें और हमारे गहाँ दुरी गायें हैं यह दलील गांधीवाद करने के लिए कोई ठीक दलील नहीं है।

फिर जो चीजें कि गाय से उत्पादित चीजों को खराब करने वाली हैं उनको आप जारी रखना चाहते हैं। सभापति जी, इतनी दूर आपने यहां पर वनस्पति के लिए विधेयक उपस्थित करने का प्रयत्न किया लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। कुछ भी नहीं हुआ। बार-बार हमसे कहा गया कि हम रंग बनाने का प्रयत्न करते हैं हमारे वैज्ञानिक ऐटम बम के महेश चीजे तो बना सकते हैं लेकिन उनको वनस्पति के लिए रंग बनाने में अब तक सफलता नहीं मिली।

श्री किदवाई—रंग है।

सेठ गोविन्ददास—तो हम वनस्पति को जारी रखना चाहते हैं। अब हम मूंगफली का दूध बनाना चाहते हैं। जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर गाय के दूध की उन्नति कैसे होगी? इसपर स्वयं सरकार को विचार करना चाहिए।

जैसा कि मैंने निवेदन किया मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस सारी पृष्ठभूमि में जोकि मैंने अभी आप से निवेदन की, जब अभी हाल ही में पं० जवाहर-

लाल जी का दिया हुआ कृषि मंत्रियों की सभा में भाषण मैंने पढ़ा तब मुझे बड़ा दुःख हुआ। उस भाषण में सामाजिक रुढ़ियों का प्रगति के रास्ते में बड़ा रोड़ा बताते हुए आपने कहा—

हमारे देश में मवेशियों का काफी बड़ा मवाल है। सारे देश में मवेशी पूजा की निगाह से देखे जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं और अन्य देशों में मवेशियों की पूजा नहीं होती पर वह अच्छे होते हैं। मवेशियों को न मारने का कानून बनाने का आन्दोलन होता है। यदि कानून बन गया तो दुगने मवेशी मरेगे। “आपने कहा यदि वैज्ञानिक विमान ने काम लेकर सामाजिक रुढ़ियां नहीं बदली गईं तो हमारा सारा पैसा लंगड़े, लूने मवेशियों और आदमियों के घोषण पर समाप्त हो जायेगा, दुग्ने के खान पर मुक्त सवाह हो जाएगा।” आपने कहा, “लोग चुनाव में हारने के डर में कोई बात न बोलें यदि वह ईमानदारी में सच कहेंगे तो चुनाव हारने की भी संभावना नहीं है।” २४ नवम्बर १९५३ पंडित जवाहरलालजी का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में जो भी उनको अधिक से अधिक सम्मान और इज्जत की दृष्टि में देखते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इन देश के लिए इसमें बड़ी राशायन की कोई बात नहीं हो सकती कि पंडित जी के सहज हमारे नेता हैं और हम भगवान में प्रार्थना करते हैं कि हमारे वेदों में जो गत वर्ष की आयु कही गई है वह पंडितजी का प्राप्त हो और वे इस देश को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाये इस देश के सम्मान की जिन प्रकार ने उन्होंने विदेशों में वृद्धि की है उसी प्रकार ने वृद्धि करते रहें। लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा एक निवेदन अवश्य है मगर मैं चाहता हूँ कि उन के पास यह निवेदन पहुँचा दिया जाये।

श्री क्रिश्वाई—आप ही कह दें।

सेठ गोविन्ददास—जो लोग इस देश में गोवध बन्द करना चाहते हैं उनको रुढ़िवादी कहना, उनको सम्प्रदायवादी कहना, बड़े से बड़ा

कसाईवाना घूम घूम कर देखा है। अन्त में मैं आपके सामने कुछ चित्र उपस्थित करना चाहता हूँ कि जिनमें आपको यह बात ज्ञात होगी कि यथार्थ में किस तरह की गायें मारी जा रही हैं। मैं यह चाहता हूँ कि कितनाई साहब इन चित्रों को देखें और इस बात का पता लगावे कि यह उपयोगी पशुओं का वध हो रहा है या निरूपयोगी पशुओं का वध हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह सारी बारा सभा इन चित्रों को देखें और इस बात का पता लगावे कि यह उपयोगी पशुओं के चित्र हैं या निरूपयोगी पशुओं के चित्र हैं। यह चित्र हैं जो मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रोमोडियम (कार्यवाही) में यह चित्र छप सकते हों तो इन को छपा जाये और जो नपया इनके ब्लाक बनाने में खर्च होगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ।

श्री के. के. वासू—(डायमंड हारवर) इन चित्रों को सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय—यह चित्र माननीय मन्त्राजी को दे देने चाहिये।

श्री बी. पी. नायर—उनको पुस्तकालय में रखें ताकि हम खाली समय में उन्हें देख सकें। (गायों के चित्र अन्त में देखें)

सेठ गोविन्द दास—तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसका पूरा हंस नस निकाल लिया जाये और यह देखा जाय कि जो लोग यह कहते हैं कि कतई गोवध बन्द हुए बिना उपयोगी पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती वे सही हैं या जो लोग यह कहते हैं कि यह बात नहीं है वे सही हैं। और इस सम्बन्ध में हमारे पंडितजी, हमारे कृषि मंत्री जी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनावे और मारे प्रश्न को देखें और निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय—एक कमेटी थी और यह विषय उसको सोपा गया था। क्या माननीय सदस्य और कमेटी चाहते हैं?

सेठ गोविन्द दास—मैं चाहता हूँ कि अगर उनको उस कमेटी से सन्तोष न हो तो वह दूसरी कमेटी बना लें। मेरा तो यह मत है कि मेरा यह विवेक ठीक है। लेकिन मैं पंडित जी और कृषि मंत्री जी से

निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनको जो कुछ हमने पेश किया है उस पर सन्तोष नहीं है तो वे एक कमेटी और बना सकते हैं। मैं एक घंटे का समय और चाहता था—मैं कहना चाहता था कि इस देश में कृषि की और दूध की क्या दशा है। मैं दशावह अंक आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय—शान्त शान्त। माननीय मंत्री महोदय के सुभाव कि माननीय सदस्य को चार घंटों तक जारी रखने की आज्ञा दे दी जावे, पर विचार करे इससे विधेयक स्वयं समाप्त हो जायगा।

सेठ गोविन्ददास—मैं समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस धारा सभा के सब दलों के लोग मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव उपस्थित किया गया था।

“निः देश के दुधारू तथा दूध सूखे पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।”

श्री वी.जी. देशपांडे—इस में एक सशोषण है।

अध्यक्ष महोदय—हां, श्री देशपांडे।

श्री वी.जी. देशपांडे—मुझे यह प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य—हिन्दी।

श्री वी.जी. देशपांडे—(गुना) हिन्दी अपनी राज्य भाषा है, किंतु इसके पश्चात् भी यह विधेयक की सूचना अभी तक सदन के मन्त्रालय से हिन्दी में नहीं आती और अंग्रेजी में ही सूचना आने के कारण मैंने अंग्रेजी में पढ़ना आरम्भ किया। इसका भाषान्तर करते हुए जो सूचना है वह मैं पढ़ता हूँ कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसके सदस्य हों।

सेठ गोविन्ददास,

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

श्री जी०डी० सोमानी

श्री नन्दलाल शर्मा

श्री चोइयराम पी० गिटवानी

श्री पी०एन० राजभोज,

श्री उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी

श्री शंकर दान्ताराम मोरे और सूचक ।

यह सूचना मैं कर रहा हूँ । यह सूचना करते वक्त.....

अन्यद् सहाय्य—माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि उमका प्रस्ताव पूर्ण नहीं है । अपने नियम निर्धारित नहीं की है जब तक कि कमेटी रिपोर्ट उपस्थित करे ।

श्री बी. जी. देशपांडे—श्रीर प्रवर समिति का प्रतिवृत्त १ फरवरी सन् १९५४ से पूर्व इस सदन के सामने उपस्थित किया जाये ।

एक माननीय सदस्य—बस १ ?

श्री बी. जी. देशपांडे—मुझे बोलना है ।

सभापतिजी, सेठ गोविन्ददास जी न यह प्रस्ताव बड़े प्रदीर्घ रूप में सदन के सामने रखा है । मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए, इस कारण से मान्यता देनी चाहिये कि यहां पर जानवरों की जो व्याख्या की गई है, इस प्रस्ताव में पशु की जो व्याख्या की गयी है, उसमें गाय और बैल के साथ भैंस, ही और गी बफलो, अर्थात् हिन्दी में भैंसे और भैंस को भी सम्मिलित किया है । मैं तो इस प्रकार की शब्द रचना नहीं करता । मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ । जैसे कि हमारे संविधान में गाय और बछड़े को अलग रखा है, उसी प्रकार गाय का स्थान स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था । किन्तु भारतवर्ष में एक विकृति आ गई है, इस विकृति का नाम है, "सैक्युनेरिज्म" (वर्मनिरपेक्षता) हिन्दू की कोई भी बात आज कही जाये तो वह बुरी है । हिन्दू, मुसलमान सिक्ख, पारसी आदि के साथ यह नाम लिया जाये तो अच्छा है लेकिन अकेले हिन्दू का नाम लिया जाय तो वह बुरा है । किसी ने कहा

कि अगर यह कहा जायगा कि गाय की रक्षा करनी चाहिये तो पंडितजी कहेंगे कि यह सम्प्रदायवाद है। इसलिए जायद सेठ गोविन्ददास जी आदि समझते थे कि यदि गाय के साथ भैंस आदि तो काने, पीले, गोरे सब साथ में आ गये और इसको पंडितजी सम्प्रदायवाद नहीं कहेंगे। लेकिन सत्य को सत्य ही मानना चाहिये। मैं तो मोटा ही कहना ठीक समझता हूँ और सभापति जी मैं समझता हूँ कि यदि सच मदमग्न अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबके हृदय में यही भावना है। वह अपने हृदय में समझते हैं कि हमको निर्वाचन के लिए देश में जाना है, जनता के पास जाना है। वोट की बड़ी चिन्ता उनके हृदय में है मेरे हृदय में वोट की चिन्ता तो नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान के ३५ करोड़ हिन्दू इस विषय में क्या सोचते हैं यह अपने हृदय पर हाथ रखकर आप देखें तो नालूम होगा कि यह ३५ करोड़ जनता गाय की रक्षा के लिए ही मांग करेगी।

मैं इस गोरक्षा के प्रश्न पर यह दृष्टिकोण नहीं रखता हूँ कि उसकी उन्नति क्या हो और वह दूध देने वाली हो या नहीं। यह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। गोरक्षा यह हिन्दुओं का मान बिन्दु है। गोवध देश में पूरी तरह बन्द करना चाहिये। इसके लिये मैं समझता हूँ कि देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह पूरे भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह बन्द कराये। इस मांग के अन्दर कोई सम्प्रदायवाद नहीं है, कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, यह पूरी न्यायोचित मांग है। और यह मांग करते वक्त हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं किसी प्रकार की हिचकिचाहट करना मानसिक दुर्बलता का लक्षण समझता हूँ। फिर आज ही नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष के पूर्व, आज तो हम हिन्दू शब्द कहते हुए इस सैक्युलैरिज़्म में हिचकिचाते हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व का हुमायूँ का अपना मृत्युपत्र लिखा रखा है। उसने लिखा है कि यदि इस देश में आप राज्य करना चाहते हैं तो इस देश की जनता की भावना के अनुसार गोवध नहीं होना चाहिये। इसलिये हमको गोवध बन्द करना है। उस

समय एक बाहर का व्यक्ति राज्य करता था। वह देखता है कि इस देश में राज्य करना है तो हिन्दू की भावना का सम्मान करना होगा और गाय का वध बन्द करना होगा।

फिर शाह आलम ने भी अपने एक फतवे में कहा है, माधव राव सिन्धिया को, कि इस देश में हिन्दू चाहते हैं और हमें इस देश में हिन्दुओं पर राज्य करना है, तो इस देश के हिन्दुओं की इच्छा का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, तो यह जान कर मुझे गोवध को बन्द करना चाहिये। मैं जानता हूँ कि गाय देश को आर्थिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक है लेकिन मेरे हृदय में आर्थिक भावना नहीं है मेरे हृदय में धार्मिक भावना है और यह मेरा मान बिन्दु है। इस कारण इस देश में जब तक गोवध बन्द नहीं होता है तब तक मैं यह गोवध का आन्दोलन चलाता रहूँगा। मेरे सामने इसका आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है, न यह दृष्टिकोण है कि गोमूत्र में कितना नाइट्रोजन है, गोबर में कितना नाइट्रोजन निकलता है यह इस प्रकार की बातें सोचने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ। चमड़े के लिये कितनी गायों का वध होता है। गोमांस के लिये करोड़ों रुपये का मांस इस देश से बाहर जा रहा है। कलकत्ते के अन्दर स्वयं डाक्टर पंजाबराव देशमुख गये थे तो इन किताबों में इस के पूरे मक और चित्र लाला हरदेव सहाय जी ने दिये हैं, जिन को सेठ गोविन्ददास जी ने बताया है वह सब चित्र और फीगर्स (अंक) आपके सामने रखे हैं कि देश में किस प्रकार गोहत्या, छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की, सब उम्र की ग्राज हो रही है। लेकिन मेरा सवाल उम्र का नहीं है मेरा यह आर्थिक मान दण्ड नहीं है कि दूध देने वाली कौन सी गाय है और दूध न देने वाली कौन सी गाय है। न मेरे सामने यह प्रश्न है कि इन के मारने से क्या मिलता है। यह मेरे लिये सीधा धर्म का प्रश्न है। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप आर्थिक दृष्टि से इस तरह गाय की बात करते हैं तो फिर फैमिली प्लानिंग के लिये भी आप के पास सीधा रास्ता है कि जितने बूढ़े हों। उन को आप मार डालें। फिर फैमिली प्लानिंग की कोई

अन्तर ही नहीं रहेगी। लेकिन मेरा तो स्पष्ट दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से मुझे तो पंडित नन्दलाल जी शर्मा की बात याद आती है कि गाय को जानवर कहना यह बात भी मान्य नहीं है। मेरे सामने तो सीधा धार्मिक प्रश्न है, इस कारण मैं तो मानता हूँ कि मेरे निचे गाय जानवर नहीं है, यह देवी है, या मेरी माता है। इस प्रकार माता का विचार करते हुए मैं तो यह सोचने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह गाय आर्थिक दृष्टि से मेरे लिए कितने फायदे की बीज है, यह मवाल मेरे सम्मुख नहीं है।

सभापति जी, सैठ गोविन्ददास जी ने एक बड़ा मौलिक सवाल प्राज नन्दन के सामने रखा है और मैं समझता हूँ कि आज सदन की परीक्षा का समय आगया है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, यह सब बातें आज मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता हूँ। पंडित जी ने सन् १९३९ में जो प्लानिंग कमीशन योजना कमीशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता पद से उन्होंने कहा था—

“सब कमेटी जनता के भोजन में परिवर्तन का नुभाव उपस्थित करती है। जो कि धार्मिक भावनाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन के प्रश्न ही सम्भव हो सकता है। वह यह है कि फालतू पशुओं को भोजन के प्रयोग में लाया जाये।”

इस देश की जनता की धार्मिक भावना में परिवर्तन करने की दृष्टि से पंडित जी ने यह बात कही थी।

दूसरे महान् नेता श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी जब यहां के कृषि मंत्री थे तब पंजाबी साहब ने प्रान्तों के पास कैसा सरक्युलर भेजा यह मुझे और आपको मालूम है। यहाँ डॉक्टर काटजू साहब बड़े जोर से कहने लगे कि यह हिन्दू सभाई जा जा कर प्रचार करते हैं कि कांग्रेसी गोवध बन्द नहीं कर रहे हैं और इसके लिये उन्होंने बड़े शासू भी बहाये। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप सीधे कहिये कि गोहत्या बन्द करना चाहते हैं या नहीं। पंडित जी के पास कुछ लोग जाते हैं तो यह कहते हैं कि यह तो स्टेटों का मामला है, राज्यों का मामला है, यह कहकर

वह टाल देते हैं। इधर यहाँ से यह पंजाबी आई० सी० एम० इस तरह का सरनयुलर प्रान्तों को भेजते हैं कि कांस्टीट्यूशन का, हमारे सविधान का अर्थ यह है कि गाय का वध हम रोकना नहीं चाहते हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं, उपयुक्त पशु हैं, उनका ही वध केवल हम रोकना चाहते हैं।

आगे चल कर जैसा सैठ गोविन्दराम ने बताया मध्य प्रदेश में भी नागपुर कारपोरेशन को सरनयुलर आगया कि आप सब गायों का वध नहीं रोक सकते हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार गोवध निषेध के लिए प्रस्ताव पास करती है और दूसरी तरफ से उनका हाथ पकड़ लेती है कि ऐसा न करो, सरकार की इस दुरंगी नीति का हमको पूरा अनुभव हांगया है और आज मैं सरकार से एक सीधा-सादा सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सदन के हर एक सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि आप वास्तव में इस देश के अन्दर गोवध रोकना चाहते हैं कि नहीं। इस सम्बन्ध में अब तक हमारा अनुभव यह है कि गोवध के सम्बन्ध में तरह-तरह की दलीलें दी जाती हैं और वाद-विवाद किया जाना है वह कहते हैं कि गोवध को तो आप रोकना चाहते हैं, लेकिन गाय को कोई नहीं पालता, या गाय को कोई खिलाना नहीं, या गाय दुध नहीं देती, इस तरह की उनकी दलीलें मुनकर में बहुत हरात रह जाता है कि आखिर हमारे सामक चाहते क्या हैं? यह भी ग़ुब है, कोई कतल करने के लिये आता है, आप सरकार के पास फरियाद लेकर जाते हैं कि यह हमें कतल करते हैं, हमको बचाओ, तो उनकी यह जवाब दिया जाता है कि इस देश में बेकारी है, हमारे नन्दा साहब ने ऐसा कहा और देशमुख गाहव ने इसको माना कि करोड़ों लोग बेकार हैं और भुखमरी गोरखपुर आदि स्थानों में हो रही है और चूँकि देश में बेकारी और भुखमरी फैली हुई है इसलिए इंडियन पैनल को (भारतीय दण्ड-विधान) से दफा ३०२ को हटा दो और कतल चल सकता है, सरकार की गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो दलीलें हैं, वह ठीक इस प्रकार की है। हमारी और

देशभर की यह आवाज है कि गोरक्षा होनी चाहिये, गोसम्बर्द्धन होना चाहिए। लेकिन गोरक्षा और गोसम्बर्द्धन दो अलग-अलग प्रश्न हैं, इस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व है, यह दलील दे कर हमारा मुँह बन्द करना और इस देश की जनता की आवाज की अवहेलना करना आप के लिए कदापि उचित और शोभनीय नहीं है और पार्टी डिस्मिन के नाते मेम्बरों का इस बारे में मुँह बन्द करना यह आपके लिए ठीक नहीं है और इस में तो जनता में व्याप्त असन्तोष ही फैलेगा क्योंकि यह एक स्वर से गोवध नियम के लिए माँग कर रही है और एक प्रजातन्त्रीय सरकार को जनता की आवाज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि प्रगले प्रवितेशन में इस विधेयक पर मतदान होगा तब काबिरी सदस्य प्रमोद चावुक के उर से उसके विरुद्ध मतदान करेंगे यह मैं जानता हूँ लेकिन मैं उनसे उतला देना चाहता हूँ कि मेरा वह मुँह बन्द नहीं कर सकेंगे मेरे ऊपर पार्टी का चावुक कोई असर नहीं करेगा और मैं यहाँ जाऊँ मतदानार्थी के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे देश के पैंतीस करोड़ लोगों का समर्थन है और वह चाहते हैं कि भारत सरकार कानून से इस देश में गोवध बन्द कराये और जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह माँग सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ

श्री ढाभी—(कैरा नोर्थ) श्री अव्यक्त महोदय, मैं यहाँ माननीय साथी सेठ गोविन्ददास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस देश में गो का जो महत्व है उस पर जोर देने की इस सदन में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह देश कृषि-प्रधान है। हम जानते हैं कि गो हम को घी दूध देती है जो आयुर्वेदिक के अनुसार जीवन प्रदान करती है। आयुर्वेधृतम्। गो से हमें खाद और बेल प्राप्त होते हैं जिनके बिना देश की कृषि नहीं चल सकती। मृत्यु के पश्चात् भी यह हमें खाल और हड्डियाँ देती है इस से गो का आर्थिक महत्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि देश के अधिकतम

वासियों के लिए गो माना हूँ और जिस प्रकार पुत्र द्वारा माना की हत्या घृणास्पद है इसी प्रकार इन देव की अधिक जनना द्वारा गोहत्या की भी घृणा की दृष्टि में देखा जाना है। इन दृष्टिकोण में भी यह अत्यावश्यक है कि गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। ऋग्वेद के अनुसार गोमाता अमृत का केन्द्र है। "अमृतस्य नाभिः" इस प्रकार भावनाओं और आधिक दृष्टिकोण में भी सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करना अत्यावश्यक है।

सर्वप्रथम हमें इस की आधिक दृष्टिकोण में देखा जाये। इन विषय पर तो किसी का भी हृन्मन भन नहीं कि उपयोगी गायों तथा अन्य पशुओं की हत्या बन्द की जाये। परन्तु आन्तरिकता यह है कि जैसे मेरे मित्र श्री मेठ गोविन्ददास जी ने स्वराज्य प्राप्त हुए पाँच वर्ष व्यतीत हो गए हैं पर अभी तक गोहत्या की बन्द करने के लिये कुछ भी नहीं हुआ है। नतमेश तो उन लूटी-लगाड़ी और दुष्ट गायों की रक्षा के सम्बन्ध में हैं जो बूढ़े-बूढ़ीयाँ नहीं दे सकती।

लूटी, लंगड़ी और दुष्ट गायों के उन बंध को बन्द न करने के पक्ष में दो तर्क उपस्थित किए गये हैं। पहला यह है कि इसलाम सम्प्रदाय के अनुसार गो की कुबली आवश्यक है इसलिए गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाकर हमें मुसलमानों की भावनाओं को रोक नहीं पाएँगे। मैं नहीं जानता, मैंने इसलामी नियमों का अध्ययन नहीं किया कि इसलाम मजहब में ऐसा आदेश दिया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा कोई आदेश इसलाम मजहब में नहीं दिया, क्योंकि जहाँ इस का जन्म हुआ, अरब में गायें नहीं थी तो मुसलमान उन्हें किस प्रकार दुर्दान्तों के लिए बंध करते। इसलिए मेरा विचार है कि गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर मेरे मुसलमान भाई भी कोई आपत्ति नहीं उठावेंगे। यदि यह मान ली जाये कि मुसलमानों में यह भावना पाई जाती है तो हमें अधिक लोगों की भावनाओं का पक्ष लेना होगा जो देश के करोड़ों लोगों का मत है कि गो की रक्षा होनी चाहिये और हर गवधारण

समझ वाले व्यक्ति को यह भलीभांति समझना चाहिये कि वह इस भावना का आदर करे।

दुमरा तर्क यह है कि लूनी, लंगड़ी और वृद्ध गायों का परिरक्षण आर्थिक दृष्टि से उपयोगी मुक्ताव नहीं है। मेरे मित्र सदस्य सेठ गोविन्ददास ने इस से पूर्व यांगड़ी द्वारा सदन में यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे तथाकथित अनुपयोगी पशु भी देश के अर्थ पर बाध नहीं, होंगे यदि उनको गोसदनों में रखने की उचित योजना बनाई जाये। इन सम्बन्ध में एक और बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति गौ को दूध पीने के लिये और बैत को काश में लाने के लिये उसी समय तक रखता है जब तक वे उपयोगी हैं तो यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें वह वृद्धावस्था में भी रखे। परन्तु हमारे सन्मुख आज कठिनाई यह है कि निर्धन व्यक्ति जो उन्हें रखने में समर्थ नहीं होते उनको बूचड़खानों को बेच देते हैं। पर यदि यह मानून बन जाये कि गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध है तो निर्धन लोगों को गायों की देखभाल पिजरापोलों में होगी और देश के सब से प्रेम करने वाले मनुष्य भी इस सम्बन्ध में बड़ा कार्य कर सकते हैं ताकि इन लूने-लंगड़े पशुओं से जो कुछ आर्थिक लाभ सम्भव है उसका अनुसन्धान आदि द्वारा पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये। आज लोग इनको बूचड़ के हाथों इसलिये बेचते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ इस विकरी से प्राप्त हो जाता है। यदि इनकी देखभाल पिजरापोलों और गोसदनो में हो तो वे देश पर आर्थिक भार नहीं रहेंगे।

मेरे मित्र सेठ गोविन्ददास ने विधान की धारा ४८ का उल्लेख किया है जिस के अनुसार दुधारू और भारवाहक पशुओं पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

अन्तिम बात जो मैं कहता था वह यह है। हम सदैव कहते हैं कि विधान एक आदर की वस्तु है। अभी सदन के सन्मुख आवंगर कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित हुई, उस के अनुसार विधान को आदर की वस्तु मानना चाहिये। पहले कहा गया था कि हमें ऐसा

कोई कार्य नहीं करना चाहिये जोकि विधान के साथ धोखे पर निर्भर हो। जब तक विधान है और हम इसे मानते हैं तो हमें इसके अनुसार चलना चाहिये। क्योंकि इस विधान में लिखा है कि सभी देशवासियों को इसका पालन करना चाहिये कि गोहत्या पर सन्पूर्णा प्रतिवन्ध हो। मेरा विश्वास है कि केवल यह मदन ही नहीं बल्कि सरकार भी इस विधेयक का स्वागत करेगी और शीघ्र से शीघ्र पास कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ।

अध्यक्षमहोदय—मैं इस संशोधन को मदन के सन्मुख प्रवर समिति का सौंपना हूँ। संशोधन इस प्रकार उपस्थित किया गया। कि यह विधेयक—

सेठ गोविन्ददास

श्री पुष्पोत्तमदास जी टंडन

श्री जी, डी, सोमानी

श्री नन्दलाल शर्मा,

श्री चौधुराम पी, गिडवानी

श्री पी, एन, राजा भोज,

श्री यू० एम० त्रिवेदी

श्री एस, एम, मोरे तथा उपस्थित करने वाले द्वारा बनी प्रवर समिति को सौंपा जाता है कि वह १ फरवरी १९५४ तक रिपोर्ट उपस्थित करें।

श्री किदवाई—मैं अपने नेठ गोविन्ददास का धन्यवाद करना हूँ।

अध्यक्ष महोदय—इस ने पूर्व कि माननीय नन्ही कार्यवाही आरम्भ करें से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह अन्तिम भाषण नहीं है। वह इस समय बाधा उपस्थित कर रहे हैं ताकि मदन के सन्मुख वह यह रख सके कि सरकार इस विधेयक के प्रति क्या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है। इसलिये यदि अन्य सदस्यगण इस पर बोलने के इच्छुक हों, यदि आवश्यक हुआ तो उनको समय मिलेगा।

उनके मत के अनुसार जब तक वर्तमान विधान चालू है, इस विधेयक को पास करना व्यर्थ है। माननीय मंत्री वही कह रहे हैं जो उनके विचार हैं। जहाँ तक अध्यक्ष का प्रश्न है उसने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया कि यह विधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। यह निर्णय अध्यक्ष ने सदन पर छोड़ दिया है कि यह सदन का कार्य है कि इस पर विचार करे कि क्या करना है।

श्री किट्टरार्ड—मैंने कहा था कि इस सदन के दो सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है और उनमें से एक स्वयं मेठ गोविन्ददास हैं। इस समय मुझे इतना ही कहना है कि यदि आप इस विधेयक को पास कर देते हैं। इसको देश की अधिकतम जनता की भावनाओं का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा, परन्तु यह उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। हमें विधि मंत्री और अटार्नी जनरल से परामर्श कर लेना चाहिए और यदि उनका विचार हो कि यह सम्भव नहीं है कि इसे उपयोगी न बनाया जा सके तो हमें इसे पास कर देना चाहिये अन्यथा सेठ गोविन्ददास के अपने मुन्नाय के अनुसार राज्य विधान सभाओं से अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्होंने जिस विधेयक को बनाया है वह यहाँ तक नहीं आता जहाँ तक हमने विचार किया है। मेरा विचार है कि उन्होंने कुछ कठिनाइयाँ अनुभव की हैं। उन्होंने इसे बनाया, उन्होंने इसे राज्य सरकारों को भेजा और उन्होंने देखा कि राज्य इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। यह वैधानिक स्थिति है, इसलिये मेरा विचार है कि हमें आगे चलने और जो कुछ हमारे पास समय है उसे नष्ट करने से पहले इस बात पर सोच-विचार कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय—अब पहले ही छः वज चुके हैं।

एक माननीय सदस्य—आपत्ति का निर्णय कीजिये या वैधानिक स्थिति को अपनाइये।

अध्यक्ष महोदय—जहाँ तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है रुलिंग पहले ही दिया जा चुका है। अब इस विधेयक पर उचित समय पर विचार

होगा। अब हमें सदन के दूसरे कार्य अर्थात् मिस्टर एम० ए० आर्थर के प्रस्ताव पर जो प्राइवेट मैम्बर्ज विल्ज की प्रथम रिपोर्ट के सम्बन्ध में है विचार करना चाहिए।

श्री के० के० वामु—जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है। उसके महत्व को दृष्टि में रखते हुये क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि जब यह विधेयक पुनः विचाराधीन हो, क्या सरकार विधि मंत्री या अटार्नी जनरल के मत का निश्चय करेंगी? अतः...

अध्यक्ष महोदय—जहाँ तक सदन का सम्बन्ध है आपत्ति उठाई गई थी और उसका निर्णय हो गया। पर यदि माननीय सदस्यगण... सारे सदस्यगण या उनकी बहुसंख्या, यह मत रखते हैं कि इस विधेयक पर यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, वे ऐसा कह सकते हैं और यह मत दे सकते हैं कि वे इस विधेयक पर विचार करना नहीं चाहते।

श्री के० के० वामु—मेरा केवल यह कहना है कि सदस्यगण यह निर्णय करने के योग्य हैं गर आप की अटार्नी जनरल का मत अवश्य ही लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय—जहाँ तक सदन का सम्बन्ध है आपत्ति का निर्णय हो चुका है। अब यह अध्यक्ष का काम नहीं कि इस प्रश्न में फिर से दखल दे। विधेयक के उपस्थित करने वाले या सरकार वह मार्ग अपना सकते हैं जो उनकी इच्छा हो।

विधि मंत्री—श्री विश्वास—विधि मंत्री से निवेदन किया गया है। इसलिए मैं कहूँगा जैसा कि बताया गया है या विधेयक सर्वप्रथम १९४६ में उपस्थित किया गया था और उस समय के विधि मंत्री डा० ग्राम्सेदकर ने यह मत प्रकट किया था कि वारतव में यह विषय विधान की सप्तम अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि १५ से सम्बन्धित है। यह ऐसा कानून बनाना केन्द्रीय संसद के अधिकार में नहीं। जहाँ तक मेरा इसकी व्याख्या से सम्बन्ध है मैं भी यही विचार रखता हूँ। पर यद्यपि यह विधि मंत्रालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया गया था तब भी इस

पर पिछली बार वाद-विवाद हुआ था। श्रीमानजी आपने अब भी यही निर्णय किया है कि इस पर विचार हो सकता है। मत देते समय सदस्यगण अपनी इच्छानुसार मत देगे। जहाँ तक विधि मंत्रों के मत का सम्बन्ध है यह वही है जो गत बार डा० अम्बेदकर का था।

अध्यक्ष महोदय—मुझे यह दिखाई नहीं देता कि इस विषय पर पुनः कैसे विचार किया जा सकता है। जहाँ तक अध्यक्ष का प्रश्न है निर्णय दिया जा चुका। सदन ने विधि मंत्री को भी सुन लिया है। इस समय सदन के सम्मुख डा० अम्बेदकर और खाद्य तथा कृषि मंत्री के मत उपस्थित हैं। निःसन्देह सदन एक उत्तरदायी संस्था है और यह किसी उचित समय पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार कर लेगा कि इसका क्या करना है ?

श्री आर. के. चौधरी—(गोहाटी) में यह कहना चाहता हूँ। इस सदन में हम एक ऐसे विधेयक को पास करना चाहते हैं जो वास्तव में बड़ा उपयोगी होगा और एक उपयोगी तथा प्रभावी विधेयक को पास करने के लिए हमें निश्चित मत चाहिए। जैसा कि मेरे मित्रों ने यह कहा है, यह मत किसी उत्तरदायी विधि अधिकारी अर्थात् अटार्नी जनरल का मत लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय—हमारे विधि मंत्री महोदय एक उत्तरदायी विधि अधिकारी हैं।

४

भारतीय गोवध संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

२६ फरवरी १९५४

अध्यक्ष महोदय—ग्रव सदन में सेठ गोविन्ददासजी के २७ नवम्बर १९५३ के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा—

“कि देश के दुधारू तथा भारवाहक पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये ।

डा० एन, बी, खरे (ग्वालियर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न हमारे मित्र सेठ गोविन्ददास ने इस विधेयक के रूप में इस सदन के सामने उपस्थित किया है, यह सदियों से लटक रहा है, त्रिशकुः के समान न जमीन का है और न आसमान का है, बीच में लटक रहा है । इस की पार्श्व भूमि यह है कि जब यहाँ पर मुसलमानों का राज्य आया, हम जब परतंत्र हुए, मुसलमानों ने हम को जीत लिया, उस वक्त से यहाँ पर गोहत्या की प्रथा जारी हो गयी, कुछ खुराक के लिये और कुछ कुर्बानी के लिये । लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भी

इस प्रश्न की उपेक्षा बहुत नहीं की और मुसलमानी शासन काल का इतिहास हमें बतलाता है कि बाबर, हमायूँ, अकबर और जहांगीर आदि बादशाहों ने समय-समय पर गोहत्या निषेध के फरमान निकाले हैं। बादशाह शाह आलम ने भी इस प्रकार के फरमान निकाले। लेकिन इसके लिये कहा जा सकता है कि वह महादजी सिन्धिया के जेरे-असर था, उन की पावर में था, लेकिन उस के पहले जो मुसलमान बादशाह गुजरे उन के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। फिर उस के बाद यह दूसरी बात है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों पराभूत हो गये और अंग्रेजों के राज्य ने यहाँ अपने कदम जमाये। अंग्रेज चाहते थे कि इस देश के ऊपर वह हमेशा के लिये राज्य करे, इस वास्ते इस देश में जो दो कौमें हिन्दू और मुसलमान बसती हैं, उन में मतभेद और फूट पैदा करने के हेतु अंग्रेजों का सदा प्रयत्न रहा और यह सब को विदित है कि उनका प्रयत्न यह था कि इस गोवध के ऊपर उन में झगड़ा पैदा किया जाये। अंग्रेजों ने यह झगड़ा यहाँ दो सौ वर्ष तक कायम रक्खा। जब अंग्रेजों का राज्य गया और कांग्रेस का राज्य आया तो आशा यह थी कि कांग्रेस का राज्य आते ही यह गोवध प्रथा कायदे से बन्द कर दी जायगी और गोवध निषेध आज्ञा कांग्रेस सरकार जारी करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में जो ८५ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं उन के दिल में हमेशा यह ठेस कायम रही। मैं इस तरफ भासदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने जब आन्दोलन शुरू किया तो उस समय खुद कांग्रेस का ही पहला गोहत्या निषेध था। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के वक्तव्य हैं, उन को दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहता।

यह देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि-प्रधान देश में बैलों का और उस की माता गाय का बड़ा उपयोग है। इस के बारे में यहाँ किसी बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है। आजकल इस देश में ट्रैक्टर

ला कर खेती करने की चेष्टा की जा रही है । लेकिन इस देश में सदियों तक भी ट्रैक्टर का काम यगस्त्री नहीं होगा और बैल को लेना ही पड़ेगा । मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है कि जिस बैल को आप ने जुताव में अपना चिन्ह माना है उस की माता गाय की हत्या करने से हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती ।

कहते हैं कि गाय की उपयोगिता बहुत है, दूध देती है, उस के दही, मक्खन, घी और गोबर तक की बड़ी उपयोगिता है । खेती के काम में गाय और बैल दोनों आते हैं । वेदों तक में गाय को 'अव्या' (अह्न्या) कहा है जिस का हनन नहीं हो सकता, जो मारा नहीं जा सकता । लेकिन मैं इस सवाल के धार्मिक । आर्थिक या जो किसी किस्म का उपयोग है, उस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस में सदन का समय नष्ट होगा । मेरा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है जिस पर जोर देना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो हिन्दू इस देश में ८५ प्रतिशत हैं उनका गाय मानविन्दु है । हिन्दू इस के लिये अपना जीवन तक कुर्बान करने को हर समय तैयार रहता है और हमारा इतिहास यह साबित करता है कि शिवाजी तक, जिन को हम पूज्य मानते हैं, भले ही कुछ लोग उनका मिसगाइडेड पेट्रियट मानते हों, वह गाय की रक्षा केलिये सदा तैयार रहते थे । उन के पिता शाहूजी महाराज आदिलशाही दरबार में वर्जार् आजम थे, ऐसे ही 'कनु' मरनु' मन्यवाकनु'म्' थे जैसे कि आजकल पंडित नेहरू हैं । शिवाजी को एक बार एक मुसलमान ने ललकार दिया कि मैं गाय को मारता हूँ, है कोई हिन्दू जो इस कोवचा सके । हमारे छत्रपति शिवाजी जो उस समय किंगोरावस्था ही में थे । आगे आये और उन्होंने उस मुसलमान का मिर नतार लिया । उन को सजा नहीं मिली क्योंकि वह आजम के पुत्र थे । आप जानते हैं कि इस चीज से हिन्दुओं को कितनी ठेस लगाई जा रही है । मैं नहीं कहता कि आज भी कोई ऐसे किन का सिर उतार ले, मैं तो केवल इतिहास की एक घटना हाउस के सामने

रखना चाहता हूँ। इसीलिये गिधाजी को भी योंही ब्राह्मण पात्रक की पदवी दी गई थी।

अंग्रेज के राज्य में क्या हुआ ? एक तो उन्होंने हिन्दू और मुसलमान का फुर्क डालने के वास्ते उन प्रान्तों को बार बार हल करने में रोक कर रक्खा और दूसरे व्यापार की दृष्टि में गोदूना जारी रखी। उनको मालूम हुआ कि वैजों के मान और चमड़े के व्यापार में परदेशों में से लाखों करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान में आता है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो कांग्रेस सरकार आई उसका भी व्यापार का ख्याल है और इसीलिये वह गोदूना बन्द करना नहीं चाहती। मैं इस बात को बिल्कुल माफ कर देना चाहता हूँ।

बात ऐसी है, कि भ्रम से कहें या किर्सी भी तरह से, हिन्दू गांव को माता मानते हैं, कैसे भी मानते हों लाक्षणिक या पञ्चगव्य, लेकिन मानते हैं, इसमें उनकी भूल है या नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा होता है। आज देश में हिन्दुओं का सैजारिटी है और कहा जाता है कि यहा पर जनतन्त्र (डिमोक्रेसी) है, तो जो बहुमत की राय हो उसको मान लेना चाहिये और उसी पर चलना चाहिये। हम लोग अगर जनतन्त्र को मानते होते तो जरूर ही गोदूना को बन्द कर देते, अगर मैं जनतन्त्र (डिमोक्रेसी) को हिन्दुआइज कर दूँ तो डिमाक्रेसी का दीमकराशि बन जाता है, जिस की अगर अंग्रेजी की जाय तो हो जायगा ("एन्हांप आफ ह्वाइट ऐट्स")। इस तरीके से हम डिमाक्रेसी से हिन्दुओं को दास बनाते हैं। जब भी हिन्दू कोई बात कहते हैं तो उसमें बाधा आती है हमारे सैकुलरिज्म की, जिसको कि मैं सैकुलरिज्म कहता हूँ जान बूझकर। यह एक ऐसा सवाल है जिस के बारे में मैं सब लोगों के दिल का हाल जानता हूँ कांग्रेस वालों के दिल का भी। यहाँ नहीं लेकिन लाबी में वह इस गोवध निषेध के बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन वह इसे पास नहीं होने देगे। यह है हमारे यहाँ की डिमाक्रेसी जिसको कि मैं दीमकराशि कहता हूँ। सैकुलरिज्म का मतलब क्या है यह

तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हिन्दुओं के विश्वास को इसकी आड़ में दबाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अगर हिन्दू गाय को माता मानते हैं, तो कांग्रेस या कांग्रेसी इस्लाम को अपना पिता मानते हैं इन वास्तविकों को ऐसा करना चाहते हैं। मुझे परशुराम की बात याद आती है जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता गण्डिका का वध किया। कांग्रेस या कांग्रेसी इस भ्रम में है कि वह महा पराक्रमी वीर परशुराम के पथ पर चल रही है और माता का वध करवा रही है पिता को गुप्त करने वास्ते।

जो हमारे विश्वास की धारा ४८ है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि इस देश में ६० फीसदी जो शोर है वे बेकार हैं और उनका कलन करना बहुत जरूरी है ताकि इस देश में अन्न का प्रश्न भी हल हो जाये जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष (इन्डास्ट्रियली) कि गोमांस खाया जाये, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज का सख्त विरोध करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे गोविन्ददास जी मरीखे जितने भी लोग इस समय हैं वे कितना ही प्रयत्नशील हों, कभी भी सफल नहीं होंगे जब तक कि यह राज्य कायम है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उनके दिल को जरा भी इस चीज से ठेस लगी है, उनको हमारे पास आना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास:—मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही गोदत्याग्न की है।

डा० एन० बी० खरे:—यह भी जानता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिये हैं कि इसे बन्द न किया जाय और मध्य प्रदेश में कमाईखाने खुलने की चर्चा चल रही है।

सेठ गोविन्ददास:—जिम सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं वह वापिस कर लिया गया है यह आप को मान्य होना चाहिये।

डा० एन० बी० खरे:—बहुत अच्छा, यँक यू। जो कांग्रेस आज

हमारे ऊपर राज्य कर रही हैं अगर उनका इसमें कोई विरोध नहीं है तो हमारी उमसे दरखास्त है कि वह इसे बन्द करे । लेकिन वह इस पालिसी पर चलेगी नहीं क्योंकि वह इस पर तुरी हुई है कि जो-जो भी चीजें हिन्दुओं की मानविन्दु हैं उनका नाश करें । यह कांग्रेस का ध्येय है अपने सेकुलरिज्म की दृष्टि से । कांग्रेस का तो वही हाल है जैसा कि इस छोटी सी कविता में कहा गया है ।

‘सिर पर है गांधी टोपी, पंजामे में चूड़ियाँ,

हिन्दू गरीब जान लगाती है जूतिया ।

यह हिन्दुओं का देश है लेकिन कांग्रेस इस बात पर दृष्टि नहीं करती है । वह कभी इस काम को नहीं करेगी । बाहर वाले यहां आते हैं और हम को सर्टिफिकेट दे जाते हैं कि इस देश का कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है । सभी जगह हमारा बोलबाला है । यह बात कहां तक ठीक है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनता जानती है कि उन के मन की बात नहीं हो रही है । आज यहां कहा जा रहा है कि हमारी जवाहर सरकार है । जवाहर याने डायमण्ड ज्युवेल यह सरकार है जरूर लेकिन वह परदेशियों के वास्ते है क्योंकि वह वहां से सर्टिफिकेट पाती है, देश के वास्ते तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जवाहर में से ‘वा’ निकाल दिया जाये तो जो बचता है अर्थात् ‘जहर’ वहीं वह रह गया है ।

यह कहते हुए मैं इस विल का समर्थन करता हूँ लेकिन मुझे डर है कि यह विल पास नहीं होगा ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह (गढवाल)—हम जानते हैं कि हम अपने पशुओं से आज या व्यवहार करते हैं । प्रायः जनता पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अपने पशुओं की ओर उचित ध्यान नहीं देती । यह आरोप निर्वन किसान पर नहीं लगाया जा सकता जोकि पशुओं से अपनी सन्तान के समान प्रेम करता है, बल्कि यह आरोप आधुनिक शहरियों पर और स्वार्थी मालिकों पर लगाया जाता है जो क उनके

प्रयोग तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को बेच कर लाभ उठाते हैं और जो जब से उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं करता या तो उन को गलियों में छोड़ देते हैं जिससे वे मन्द खाते हैं या बूचड़ों में बेच देते हैं। हर मानव जिसके हृदय में इन पशुओं के प्रति कुछ भावनाएँ हैं तथा देश के हित के विचार हैं मुझे विश्वास है मेरे साथ सहमत होंगे कि अपने देश में गोहत्या पर प्रतिबन्ध न लगा कर हम अपने विद्वान की द्वाारा ४८ की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही हम करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य तथा कृषि के दृष्टिकोण और देश के आर्थिक हित जिसका सम्पूर्ण आधार पशुधन है, की भी पूर्णतया उपेक्षा कर रहे हैं।

उम बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम पशुओं का परिरक्षण नहीं कर रहे हैं और गोहत्या जब से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, बहुत बढ़ गई है। यह हमारे लिये और विशेष कर हिन्दुओं के लिये बड़ी लज्जास्पद बात है जो कि आज केवल वही एक जाति है जो अपनी सभ्यता में विमुक्त हो रही है और उन धार्मिक विद्वानों की उपेक्षा कर रही है जो निसर्ग के नियमों पर आधारित हैं। हमारे पूर्वजों ने जो परम्पराएँ और रीति-रिवाज हमारे भले के लिए बनाये थे आज हममें से बहुत से उनकी शिल्ली उड़ाते हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि हम कितने आधुनिक हो गये हैं, हम प्रगति तभी कर सकते हैं जब कि हम निसर्ग के नियमों पर चलें। क्या इसमें कोई सन्देह है कि यदि हमने निसर्ग के नियमों का पालन नहीं किया तो निसर्ग हमें कोई दण्ड नहीं देगी? और यद्यपि यह बड़ा व्यर्थ धार्मिक विश्वास कहा जायगा पर तथ्य है कि हम तभी धन धान्य पूर्ण होंगे जब हम अपने पशुधन का परिरक्षण करेंगे जो आयु भर हमारी सहायता करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम भारत मोसेवक समाज के प्रधान मन्त्री द्वारा उपस्थित किये गये आँकड़ों तथा को अमत्य घोषित कर सकें। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो यह कहते हैं कि केवल अनुपयोगी और वृद्ध पशु ही कल

होते हैं वे प्रमत्त बोलते हैं और गोहत्या के विरुद्ध कानून के विधान होने पर भी केवल पुरानाबाद में प्रतिदिन चारसौ मुन्दर और उपयोगी गायों की हत्या होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार इसे प्रोत्साहन देती है। सरकार पंजाब कांग्रेस और हिसार तथा रोहतक जिला बोर्डों का मुनती नहीं। उन्होंने भिन्न भिन्न हत्या के केन्द्रों के नाम और साथ ही कितनी-कितनी दुधारू गायें हर वर्ष बलकता जाती हैं और वहां जाते ही बछड़े-बछड़ियों को और जब दूध सूख जाता है सब सभी गायों को किस प्रकार बध किया जाता है।

उमरा अर्थ केवल यही है कि कानून भंग करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो अपनी सुविधा अनुसार कानून का व्याख्या कर लेते हैं। इससे यह प्रगट होता है कि हम लोगों का दृष्टिकोण कितना सकुचित है। हम इस योग्य नहीं रहे कि यह देख सकें कि हम अपने आप को एक कोष से वंचित कर रहे हैं और निराधार अर्थ का सहारा ले रहे हैं।

अन्य देशों में जहां गोमांस खाया जाता है दुधारू और भारवाहक पशुओं की हत्या पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। भिन्न भिन्न-मतों को मानने वाले जैसे वर्मा के प्रधान मंत्री इस प्रयत्न में हैं कि गोहत्या को बन्द कर दिया जाये, परन्तु हमारे देश में जब से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है यह दुगनी हो गई है और एक प्रकार से दैनिक कार्यक्रम का अंग बन गई है।

अब हमें यह देखना चाहिये कि हमें गोहत्या और इसके शरीर के भिन्न अंगों को विदेश में भेजने से कितना और किस प्रकार का लाभ है। गोमांस के निर्यात आदि से हम केवल आय का हिस्सा कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि हमें एक करोड़ वृद्ध अनुपयोगी पशुओं से भी छुटकारा पाना है ताकि उपयोगी और नौजवान पशुओं का लालन-पालन भली भांति हो सके।

इस बहानेबाजी और लंगड़े तर्क के लिए हम अपने हृदय से उत्तर

प्राप्त करते हैं। भारत तथा विदेशों में जोखान तथा स्वस्थ अन्धों गावों का मांस ही स्वीकार किया जाता है। ये इस रोग को चेनावनी देती हैं। जहां तक आय का सम्बन्ध है हमें आराम से कार्य रोक देने चाहिये जैसे जिन द्वारा कलकत्ता में पनान द्वारा कम्बल धुल में मिला दिये गये और १९४६ से आर्द्रिड रिपोर्ट में तीन हज़ार पचास लाख का आँटा दिखाया गया है। यह हर वर्ष १८.२३ लाख बढ़ता जायेगा। तीन लाख रुपये पेट्रोल और भी में उड़ गये। ऐसे ही और भी कई सभ्य हैं जिन्हें यस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा जानों को मन्त्री ने रोकने की आवश्यकता है जिससे जंगल द्वारा रक्त अलासर समाये हुए धन को बचाया जा सके न कि गोहत्या द्वारा धन कमा कर देश को अनी बनाने की।

यह बड़े दुःख की बात है कि हमें जो अमूल्य लाभ पशु धन में है उन्हें नहीं देखा जाता। यह जल में मृत्यु पर्यन्त और उनके पदचिह्न तक हम लोगों को दूध और उससे बनी लोहनामा प्रकार की उत्तम वस्तुएँ देने है। और ग्राम और नगरों में हमारे यानी कार्यों में महाप्रताप देने है और जब बुद्ध और अनुपयोगी हो जाते हैं तब भी एक पशु-साधकत्वा में नारे पर रह कर हमें पचास रुपये प्रति वर्ष की राशि देना है जब कि दुगरी उतनी सोई बनाने पर यस्वी रूपया बरत जाती है। मृत्यु के पश्चात् इसकी खाज और हड्डियां भी प्रभुत उपयोगी होती हैं जिनको हम धन में पड़ कर आर्थिक लाभ के लिए विदेशों को भेज देते हैं। उस प्रकार अपनी धरती और अपने आप को निरर्थक कर लेते हैं। मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें स्वीकार नहीं कि यह पशु हमारे लिये बड़ा उपयोगी साथी और मित्र है और क्या उस उपयोग के लिए उन्मत्त बंध करना न्याय उचित है ?

हमारे वैज्ञानिक आज पीढ़ी और भूगर्भला आवि ने दूध तथा भक्षण निकालने के पीछे लगते हैं जो केवल डोंग मात्र है और दूध द्वारा बनी हुई वस्तुओं के स्थान पर इनका प्रयोग केवल मानविक ज्ञान ही है और

वह भी बड़ी दुर्बल । मैं सदन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम झालझाल वनस्पति या अन्य वनस्पति तेलों के प्रयोग में अधिक बलशाली हैं, स्वस्थ हैं ? क्या हम तभी से वास्तव में सुखी हैं जब से निगम द्वारा निमित्त वस्तुओं का स्थान मानव द्वारा निमित्त वस्तुओं ने प्राप्त कर लिया है ?

आज विश्व में वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति हो जाने पर हम जो कुछ समय पूर्व थे अब केवल उसका प्रतिबिम्ब मात्र ही रह गये हैं । हम में से बहुत सों में बल, सहनशीलता तथा मानसिक और शारीरिक शक्ति नहीं रही है जिस से हम सत्य के पक्ष में डट सके और उन रोगों तथा आपत्तियों को रोक सके जो दिन दूनी रात चौगुना बढ़ रही हैं । हम में कुछ धनाढ्यों को छोड़ कर प्रायः सभी पेट भर भोजन न मिलने के कारण हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गये हैं । इसको हमारा रोगियों जैसा स्वरूप सिद्ध करता है । हमारे नवयुवक कुछ ही वर्ष जी पाते हैं । कब तक हम लोगों को इतनी मंहगी दवाइयों और बड़े-बड़े हस्पतालों का सहारा लेना सम्भव होगा । जब कि हमारे पास जीवित रहने के लिये भोजन के लिये भी धन नहीं जिस बारे में कहा गया है कि आज बहुत है । क्या इसमें कोई सन्देह है कि यदि कुछ वर्षों तक हमें शरीर को पुष्ट करने वाले खाद्य पदार्थ न मिलेंगे तो एक दिन सभी घरों में रोग का वास हो जायगा ? हमने जो हृदयहीन होकर यन्त्रों का निर्माण किया था, शनैः शनैः हम भी यन्त्र होते जा रहे हैं । धन प्राप्ति हमारे जीवन का केवल मात्र लक्ष्य रह गया है और इसके लिये हमें बड़े से बड़े मित्र को दुःख पहुँचाते तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती । अपनी दुर्बलताओं के कारण हम बहुत निधन हो गये हैं । क्या हम वही हैं जो कुछ समय पूर्व ही सत्य के लिये लड़ते और सत्य का ही पालन करते थे ? पराधीनता काल में हमारा लक्ष्य हमारे सन्मुख विल्लस्प था । अपनी स्वतन्त्रता के लिये हमने कितनी वीरता से संघर्ष किया और इसे प्राप्त किया । आज हम उस महान् सत्य का साथ क्यों छोड़ते हैं ? जिससे हम पराधीनता के वश में हो । मैं सदन से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह

गाय को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। आज किसी हिन्दू के यहां चले जाइये जो हमारे देश में रहता है, आप पायेंगे कि जिस वक्त शाम का उसकी गाय उसके मकान पर आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद उसके चरणों पर पानी देते हैं। इसी तरहसे जब हमारे यहां का कोई कार्तकार बैल खरीदता है तो वह समझता है कि हमारे यहां एक लक्ष्मी आयी है। अतः हमारे देश में गाय को वह स्थान दिया जाता है जोकि लक्ष्मी को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी जितनी भी रक्षा कर सकते हैं करें। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हमारी सरकार कार्य करने वाली है तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस तरह का कोई कानून बनाये ताकि हिन्दुस्तान में यह जो चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं वह बन्द हों। सभानेत्री महोदय हमारे एक माननीय सदस्य हिन्दू महासभा के भूतपूर्व सभापति ने यह कहा कि जो कांग्रेस वाले हैं यह उन दूसरे लोगों को जोकि यहां पर रहते हैं पिता के तुल्य मानते हैं। मैं तो उनसे कहता हू कि उनको शर्म मालूम होनी चाहिये। यदि हम लोग उनको पिता समझते हैं तो आखिर आप भी यही पैदा हुए हैं वे यहां पर रहते हैं तो आप अपने को क्या समझते हैं? क्या वह आप के पिता नहीं हैं। इस तरह के लाछन कांग्रेस वालों पर लगाना ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि वह बुजुर्ग हैं बड़े हैं और वह एक प्रान्त के प्रधान मंत्री रह चुके हैं। पर, यहां पर आने के बाद उनकी अक्ल में इस तरह की कमी हो गयी है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो कहूंगा कि इस तरह की बातों पर उनको ख्याल रखना चाहिये और यदि कोई उचित सुझाव हो तो उसको सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार से गलतियां होती हैं यह मैं मानता हू। कोई भी पार्टी आयेगी इससे कोई न कोई गलती जरूर होगी। कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी जो यहां पर आ जाती है वह एकदम सीख कर वह पक्की होकर नहीं आती। खामियां रहती हैं। उनको दूर करना हमारा और हमारे जो और भाई

इस हाऊस में हैं उनका कर्तव्य हो जाता है । खाली टीका टिप्पणी करने से कोई कार्य नहीं चल सकता । फी जमाने में जबकि हम सब मिल कर प्रजातंत्र मिष्ठान्त पर काम करने के लिये आगे हुए हैं तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम यह देखें कि देश की वृद्धि कैसे हो सकती है ।

यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के विषय में मैं तो अपने यहाँ के जो माननीय मन्त्री महोदय हैं, उनसे अर्ज करूँगा कि आप इसमें विलम्ब न करें और जल्दी में जल्दी एक बिल लावें ताकि इस तरह का वातावरण कहीं देश में तैयार न हो जिसमें कि हमें और हमारे देश को नुकसान पहुँचे । इसमें पहुँचे ही एक इस तरह का बिल लाये जिससे कि हमारे यहाँ जो चौपाये हैं, गाय है, बछड़े हैं और बैल हैं उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके । जितने गोसदन है, जहाँ गायों की सेवा की जाती है, उनकी प्रान्तीय सरकारों से कह कर ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्थापना कराये । इसके लिये अपने बजट में भी सरकार कुछ थोड़ी रकम जरूर खे । और प्रान्तीय सरकारों को दे । जिससे कि वहाँ उनकी रक्षा हो सके । यदि प्रान्तीय सरकारें गोसदन नहीं बनाती हैं तो उनको आगाह करें कि तुमको यह काम करना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जो हमारे माननीय सदस्य सेठ गोविन्ददास जी लाये हैं उसका समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय:—इसमें पूर्व कि मैं वादविवाद को जारी रखूँ, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सदन का कोरम पूरा नहीं है । मैंने पहले ही सबको कहला कर भेजा है, इस पर भी यहाँ केवल थोड़े से सदस्य उपस्थित हैं, यह आवश्यक है कि कम से कम कोरम तो पूरा हो ।

एक सदस्य:—कोरम की घण्टी बजाई जाये ।

अध्यक्ष महोदय:—अब मैं इसे नहीं बजाऊँगा । मुझे आशा है कि अगले भाषण में कोरम पूरा हो जायेगा ।

श्री नन्दलाल शर्मा:—(नीटल)—

“भालक्ष्मीलोकपालानां या च स्वर्गे व्यवस्थिता ।

धेनुरुपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥”

माननीय उपाध्यक्षा नमोदय, प्रारम्भ में पूर्व एक शब्द कह देना उचित है । यद्यपि मैं किसी भी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, किन्तु गऊ के सम्बन्ध में, विशेष करके जबकि दोनों ओर से, कांग्रेस पक्ष में और विरोधी दल से, सभी व्यक्ति गोहत्या बन्द हो, ऐसा कहा है तो ऐसी परिस्थिति में इसको किसी पार्टी का या किसी पक्ष का प्रश्न बनाना उचित नहीं है । यद्यपि स्वयं मेरा अपना बिल उपस्थित है और जब भी हो वह सदन के सामने आ सकता है, फिर भी मैंने स्वयं इस बात का निश्चय कर लिया था कि यद्यपि मेरी समझ से श्री माननीय सेठ गोविन्ददास जी के बिल से मुझे पूर्ण मन्ताप नहीं, वह मेरी व्यक्तिगत भावना के अनुकूल नहीं जाता, फिर भी यदि कांग्रेस सरकार और हमारा यह सदन इस बिल को स्वीकार करे तो मुझे उस समय अपना बिल लौटा लेने में कोई खेद नहीं होगा । उसका कारण यह है । आज सबसे बड़ी वस्तु देश के सामने यह है कि भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जनता इस गोहत्या की मानसिक पीड़ा से तड़प रही है और जनता की यह बड़ी भारी मांग है कि गोहत्या बन्द हो । एतावत मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि कोई भी वैधानिक अड़चने डाल कर, इसमें कृपि का विषय लगा कर यह कह देना है कि यह प्रान्तों में जाना चाहिये, मैं समझता हूँ कि यह अनुचित है । मुझे सेठ गोविन्ददास जी क्षमा करेंगे जब मैं यह कहता हूँ कि उन्होंने “इंडियन कैटल प्रिजर्वेशन” शब्द रखा है तो इसके रखने में उनकी जो कांग्रेसी भावना थी वह थोड़ी कमजोरी लाती थी, कि कहीं गऊ का नाम आ जाने से देश की सांस्कृतिक भावना उठ न जाये और देश की सांस्कृतिक भावना उठने से कोई दूसरे व्यक्ति इससे छूट न हो जाये । मैं

जानता हूँ कि उनके हृदय में गऊ के लिये कितना दर्द है और वह उसका कितना आदर करते हैं और वह चाहते हैं कि गोहत्या बन्द हो। किन्तु गोहत्या न कह कर किनी भी प्रकार से गऊ को लाकर उसकी हत्या बन्द हो जाये तो यह जो उनकी भावना है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

एतावत अब इसमें केवल कृषि के दृष्टिकोण को आप डाल देंगे, जैसे कि हमारे मियां साहब, श्री किदवाई साहब ने कहा था कि इस संसद में इस पर बहस करना निष्फल हो जायगा और यह प्रान्तों में जायगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे उद्देश्य को ही निष्फल बनाना होगा। इसलिये हमको उसका सांस्कृतिक, उसका धार्मिक और उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो इस प्रश्न का स्वरूप है, जो इन दृष्टिकोण के लाभ हैं, उस प्रकार गऊ का प्रश्न प्रत्यक्ष रखना पड़ेगा, हम समझते हैं कि और कुछ नहीं तो लोकतन्त्र की दृष्टि से हमको गोहत्या बन्द करना स्पष्ट आवश्यक है। आज हमारी सरकार जनतन्त्र सरकार कहलाती है। लोकतन्त्रात्मक सरकार कहलाती है। और जनमत अधिकाधिक संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी मांग कर रहा है कि गोहत्या बन्द हो। हम यदि उसको बन्द नहीं करते और हम में से कोई खड़ा होकर, कोई भी नेता खड़ा होकर यह कहता है कि जनता मूर्ख है, समझती नहीं, तो मैं कहता हूँ कि वह लोकतन्त्र के नाम पर नाम मारना है और कलक लगाना है। हमको इस बात का ध्यान होना चाहिये कि लोकतन्त्र का विचार रखते हुए गोहत्या का बन्द होना परम आवश्यक है।

हमको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर बड़े-बड़े राजपि और धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। राजपि दिल्लीप ने अपने शरीर को मांस के एक लोखंड की तरह शेर के आगे फेंक दिया और कह दिया कि मेरे शरीर का खा जाओ, लेकिन गऊ को छोड़ दो। यह कहना कि बूढ़ी गायों को, निष्फल गायों को भार देना चाहिये, क्योंकि वह हमारा अन्न खा जाती है, पिछले आपके अधिवेशन में आकड़े देकर

इस बात को सिद्ध कर दिया जा चुका है कि गऊ वूढ़ी भी होकर, जर्जरित और निरिन्द्रिय होकर भी वह गोबर और गोमूत्र के द्वारा जितना खाद देती है, जितना ईंधन देती है वह भी उसके चारे से कहीं अधिक होता है। ऐसी गायों को कोई भी अनाज नहीं देता है। इसलिये यह कहना कि वह हमारा अनाज खा जायेगी, दूसरे पशुओं का अनाज खा जायेगी, यह कहना भूठ है। मुझे माननीय सहगल साहब धमा करेगे जब मैं यह कहूँ कि उन्होंने 'चौपाये' शब्द का प्रयोग किया। हम समझते हैं कि यह कहना कि जन्ता गऊ का जो पूजन करती है वही हत्या करती है, यह भूठी भावना है। यह हमारे राष्ट्र के मानविन्दु का परित्याग करना है। उसी तरह की यह भावना है। अंग्रेज यहाँ आ जाते और चाहते वह ले जाते, कोई रुकावट डालते कि इतना ले जाओ इतना मत ले जाओ। आपने हमको क्लोरोफार्म (एक दवाई) सुंघा करके और खुला करके छोड़ दिया और हम चल सकते नहीं। अब हमारी जेब को कोई भी काट सकता है कोई भी गला काट सकता है। इस तरह जंजीर तोड़ने से और क्लोरोफार्म (एक दवाई) सुंघाने से क्या होता है। इस लिये इस तरह की प्रतिकूल भावना रखने से और अपने मानविन्दु का परित्याग करने से और अपनी संस्कृति का नाश करने के लिये तैयार रहना यही राष्ट्र के नाश के और राष्ट्र के पतन के कारण है। केवल पर्वतों का नाम, नदियों का नाम लेने से ही राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो राष्ट्र का मानविन्दु है उसको बीच में से हटा दिया जाये तो राष्ट्रवाद ही खत्म हो जाता है। एतावत राष्ट्रवाद के नाम से, प्रजातन्त्रात्मक सरकार के नाम से और जनता की आवाज के नाम से आपको इस भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विभूति, जिसके लिये वेद ने आज्ञा दी है,

मा गामनागामदितिं बधिष्ठ ॥

कहा गया है कि हमको यह अमरत्व देती है, यह हमको अमर बनाने वाली है, इसलिये 'ए मनुष्य, इसकी हत्या न करना'। आपको इसकी

हत्या बन्द करनी पड़ेगी । कहा है कि इसकी हत्या से तुम दिति के 'पुत्र' बनोगे, मृत्यु को प्राप्त होवोगे । दिति क्या है, मृत्यु । तुम निरन्तर मृत्यु के गाल में चले जाओगे ।

इसलिये मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, इतना ही निवेदन करता हूँ कि गोपाल कृष्ण की पवित्र भूमि में, जहाँ भगवान् कृष्ण, अखिल ब्रह्माण्डनायक भगवान् अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना करने वाले, जहाँ भगवान् कृष्ण नंगे पैर घूमे हैं, गऊ को सेवा के लिये, जहाँ वह कहते हैं:—
पूयेमेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ।

कि गऊ के चरणों से जो धूल निकलती है, उठती है, उसके कण से मेरा शरीर पवित्र होता है, इस प्रकार जिस देश में घी और दूध की नदियाँ जहाँ पहले बहती हों और जहाँ आज खून की नदियाँ बह रही हों, वहाँ यह हमारा दुर्भाग्य ही इसका कारण है । मेरा स्वप्न भाव है कि यही क्रम रहा तो हमारा देश नाश की ओर जायेगा और हमारे शत्रु बलवान् होंगे ।

अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ।

त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥

जिस देश में पूजा करने योग्य देवता का पूजन नहीं होगा, अपूज्यों का सम्मान बढ़ेगा, उसमें तीन दोष सदा रहेंगे । उसमें अकाल बढ़ेगा, अनाज नष्ट होगा और मरण होगा । वहाँ अकाल मृत्यु होगी, छोटे-छोटे बच्चे मरेंगे और सदा ही शत्रु का, चोर का और अग्नि का भय रहेगा । इन तीन दोषों से यदि बचना है तो आपको गोहत्या ग्रीवातिग्रीव बन्द करनी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विल का पूर्णतया एवं हृदय से समर्थन करता हूँ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी:—मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूँ । “कि अब प्रश्न किया जाये ।”

श्री वी० जी० देशपांडे:—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय:—मैं सदन का मत चाहता हूँ । प्रस्ताव यह है—
“कि अब प्रश्न किया जाये ।” प्रस्ताव पान्न हुआ ।

अध्यक्ष महोदय:—मेरा विचार है सेठ गोविन्ददास उत्तर देगे ।

सरदार अमरसिंह सहगल:—एक प्रस्ताव यह है कि विधेयक का प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

अध्यक्ष महोदय:—सर्वप्रथम विधेयक के उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का अधिकार है ।

सेठ गोविन्द दास—अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे इस विधेयक का सम्बन्ध है; मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें इसके पहले कह चुका हूँ । २७ नवम्बर को मैंने इसे उपस्थित किया था और ११ दिसम्बर को भी यह इस सदन के सम्मुख आया था । उन दोनों दिनों में मैंने कोई दो घंटे के भाषण में इस विषय पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है, उतना डालने का प्रयत्न किया था । बहस का उत्तर तो मुझे तब देना होता जब इस विधेयक का विरोध किया जाता, परन्तु आपने देखा होगा कि २७ नवम्बर को मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ था । ११ दिसम्बर को जब मेरा भाषण पूरा हो गया, उसके बाद जिस ने भी इस विधेयक पर कुछ कहा, उसने मेरे समर्थन में कहा, यहाँ तक कि हमारे कृषि मन्त्री श्री रफीअहमद क़िदवाई ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया । उन्होंने पटने के एक भाषण में इस बात को कहा था कि यदि इस देश का बहुमत गोवध वन्द चाहता है तो गोवध वन्द होना चाहिये और जब मैंने उन्हें भाषण का स्वरण दिलाया तब उन्होंने ११ तारीख को इस बात को दुहराया कि जो बात उन्होंने पटने में कही थी, उस पर वह आज भी कायम है और उस सम्बन्ध में वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तो यह सरकारी मत था । उन्होंने ज़रूर कहा था कि यह विषय प्रान्तीय विषय है, परन्तु सभानेत्री महोदय, आप यह जानती हैं कि जब यह आवाज उठाई गई कि यह प्रान्तीय विषय है, उस समय हमारे

उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी हलिंग दी थी जिस में उन्होंने कहा था कि वह इस विषय को प्रांतीय विषय मानकर अलग नहीं करना चाहते और इसको इस सदन के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। तब अब यह प्रश्न उठाना कि सरकार इसका विरोध तो नहीं करती, लेकिन यह प्रांतीय विषय है कुछ उपयुक्त बात नहीं होगी। यह बात हुई ११ दिसम्बर की जब इस विधेयक पर कुछ भाषण हुए और आज आपने देखा कि इस विधेयक पर जितने भी भाषण हुए, तबों ने इसका समर्थन किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। हिन्दू मना की ओर से डा० खरे नाहव बोले, रामराज्य परिषद् की ओर से श्री नन्दलाल शर्मा बोले। इसके अलावा हमारा जो एक दूसरा दल यहाँ पर स्थापित हुआ है, उसकी ओर ने हमारी राजमाता टिहरी बाँकी, कांग्रेस की ओर ने हमारे सरदार सहजल बोले और वह सिद्ध भी है। इस तरह आपने देखा कि किसी दल का भी इससे विरोध नहीं है। कांग्रेस के सम्बन्ध में जो बातें आप ने कही जाती हैं, वे बातें बहुत हद तक गलत हैं। जब डा० खरे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस के समर्थन में नहीं है, कांग्रेस वाले इसके समर्थन में नहीं हैं और यह कभी पास होने वाला नहीं है। मैंने उनको स्मरण दिलाया कि मध्यप्रदेश में जहाँ यह विधेयक रखा गया और पास हुआ, वहाँ आखिर कांग्रेस की ही सरकार तो है, कोई दूसरे की तो सरकार नहीं है। वहाँ यह विधेयक सरकार की ओर ने रखा गया और पास हुआ। अभी आपने सुना होगा कि भूपाल में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी यह विधेयक रखा गया और भूपाल में भी यह पास हुआ। चायद आप जानती होंगी कि बिहार प्रान्त में भी इस प्रकार का एक विधेयक वहाँ की विधानसभा में उपस्थित है, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है। वह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी की सुपुर्द किया गया है मैं अभी बिहार गया था और मुझे यह मान्य हुआ कि चायद बिहार विधान सभा के अगले अधिवेशन में वह पास हो जायेगा। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस सरकारें और

कांग्रेस वाले इसके विपक्ष में हैं, जनता को एक गलत बात कहनी है। मैंने आपके सामने इतने दृष्टान्त दिये। आप जानती हैं कि मैं कांग्रेस दल का सदस्य हूँ, कांग्रेस दल में आज शामिल हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में मैं सन् १९२० से शामिल हूँ, आज भी मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारी के पदों में रह चुका हूँ। अपनी प्रान्तीय कांग्रेस का मैं सभापति हूँ और इतने समय से सभापति हूँ जितने समय तक शायद कोई भी किसी प्रान्त का सभापति न रहा होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मैं मेम्बर रह चुका हूँ और त्रिपुरी कांग्रेस की स्वागत समिति का मैं अध्यक्ष था। आपके इस सदन का तीस वर्षों में सदस्य हूँ और कांग्रेस की ओर से मैं सदस्य हूँ तब यह कहना कि कांग्रेस इसके विरुद्ध है ठीक नहीं है।

श्री बी, जी, देशपांडे—आपकी सरकार क्या कर रही है ?

सेठ गोविन्द दास—अगर कांग्रेस इसके विरुद्ध होती तो मैं कांग्रेस दल के अन्दर रहते हुये यह विधेयक पेश नहीं कर सकता था। मुझे ह्विय द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश नहीं मिला कि मैं इस विधेयक को सदन में पेश न करूँ, तब यह कहना कि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस दल इसके विरुद्ध है, लोगों को भुलावे में डालना है।

श्री बी, जी, देशपांडे—कांग्रेस सरकार यह बिल क्यों नहीं ला रही है ?

सेठ गोविन्द दास—पर मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूँ कि मैं इस विषय में राजनीति को बिल्कुल नहीं लाना चाहता, मेरे कुछ मित्र राजनीति को दृष्टि में रखकर इस विषय पर बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह या तो भूमिदान का जो विषय है, इस प्रकार के निर्माण करने के जो विषय हैं, उनमें हम राजनीति को न आने दें और सब दल मेल कर उन कामों को करें। मेरा शुरू से यह मत रहा है और आज भी मेरा यही मत है। इसलिये जहाँ तक गोरक्षा का विषय है मैं इसमें राजनीति को नहीं आने देना चाहता। राजनीति को पृथक् रख कर मैं

इस विषय को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह सदन इस विधेयक को पास करे। जैसा कि हमारे श्री नन्दलाल बर्मा ने कहा मैं एक बात सरकार को जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय में आपत्ति उपस्थित करके कि यह प्रान्तीय विषय है, उसका विरोध न करे। उपाध्यक्ष महोदय ने इस विषय को इस सदन के ऊपर छोड़ा था। अगर थोड़ी देर के लिए यह समझ भी लिया जाये कि यह विधेयक कानून के विरुद्ध है, इतने पर भी अगर यह सदन इसको पास कर देता है तो सदन को इस बात का हक है। उस वक्त हम उस विषय को एक दूसरी तरफ से देखेंगे और यहाँ से उसके पास हो जाने के बाद दूसरी प्रान्तीय सरकारों को तो एक रास्ता मिलेगा उनके सामने हम दावेगे और कहेंगे कि देखिये केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस दल का बहुमत रहते हुए और इस विषय पर मतभेद रहते हुए भी कि यह विषय केन्द्र का है या प्रान्त का है, केन्द्र ने इसको पास किया और अगर केन्द्र ने इसको पास कर दिया है तो प्रत्येक प्रान्त का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इसको पास करे।

श्री नन्दलाल बर्मा—सविधान का संशोधन तो हो सकता है।

सेठ गान्धिविन्दास—इसके यहाँ पान होने से हमको बहुत बड़ा बल मिलेगा।

एक बात और कह दूँ। यदि आप केन्द्र और प्रान्तों के विषयों को देखें तो आपको मान्य होगा कि अगर दो प्रान्तीय सरकारें केन्द्र को यह लिखें कि प्रभु-प्रभु प्रकार का विधेयक पास होना चाहिये तो प्रान्तीय विषय रहते हुए भी केन्द्र उसको पास कर सकता है। आज इतने प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और कोई भी प्रान्त पास कर मेरा प्रान्त तो सबसे पहले इस बात के लिये राजी होगा कि वह केन्द्र को लिखे कि केन्द्र ऐसा विधेयक को पास करे।

मैं चाहता हूँ कि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उसके अनुसार यह विषय सदन पर छोड़ दिया जाये कि वह इसको पाम करे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्लोजर मोशन आ गया है, और सात वजने के पहिले इसको समाप्त करना है, जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने २७ नवम्बर और ११ दिसम्बर को कह दिया है। उन भाषणों को यदि आप देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सब बातें कही जा चुकी हैं और अब जबकि यहां पर किसी दल के द्वारा या सरकार के द्वारा इसका विरोध नहीं हुआ है तो मुझे उत्तर देने की कोई बात नहीं दिखाई देती। मैं चाहता हूँ कि यह सदन इस विधेयक को पास कर दे।

अध्यक्ष महोदय—एक प्रस्ताव है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। पहले मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करूँगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलोर)—कोई भी यह जानना चाहेगा कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई भी मत नहीं।

अध्यक्ष महोदय—मैं पाँच मिनट मन्त्री महोदय को भी दूँगा।

उपकृषि तथा खाद्य मन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—)
विधेयक पर।

अध्यक्ष महोदय—हाँ, विधेयक पर।

श्री एम. वी. कृष्णाप्पा—संसद के गत अधिवेशन में इस विधेयक पर बोलते हुये कृषि तथा खाद्य मन्त्री श्री रफी अहमद किदवई ने इस विधेयक से सम्बन्धित देश की जनता की गरीबी के प्रति भावनाओं का आदर और समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप में कहा था कि यह विधेयक अवैधानिक है। सेठ गोविन्ददास ने श्री किदवई के पटना के भाषण का उल्लेख किया था, उन्होंने पटना में कहा था कि जिस काम को देश का बहुमत यह चाहता है कि हो जाये तो उस पर बिना इधर-उधर का विचार किये उसे करना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने ने कहा आज भी वह उस पर दृढ़ है। पर आपको यह देखना चाहिये कि जो विधेयक अवैधा-

निक है उसे कैसे पास कर दिया जाये। सेठ गोविन्ददास द्वारा उपस्थित किया यह विधेयक समस्त देश पर लागू होगा। "पशु नसल का परिक्षण संरक्षण और उन्नति" का विधान की मन्मथ अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि ११ में उल्लेख है। विधान की धारा २४६ (३) के अनुसार 'क' और 'ख' श्रेणी की राज्य विधान सभाओं का यह अधिकार है कि वे राज्य सूची में आये हुये किसी भी विषय पर कानून बना सकती हैं। विधेयक के प्रवेश के अतिरिक्त उत्तरी अनामयिक समझा गया है क्योंकि यह समस्त भारत में गोहत्या को सम्पूर्ण बन्द कराने की माँग करता है। जब तक अनुपयोगी और पशुओं के लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता तब तक सम्पूर्ण गोहत्या को बन्द करने में देश के पशुधन के परिरक्षण और उन्नति की दृष्टि ने सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करने से कोई लाभ न होगा।

श्री मन्दलाल शर्मा—क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है ?

श्री एम० वी० कृष्णास्वामी—मुझे आपकी भावनाओं के प्रति बड़ी महानुभूति है... इसके लिये सारे देश में जांच की जाये और आवश्यकताओं को देखा जाये। गोमदनों पर व्यव करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी। सन् १९४८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पशुरक्षा तथा उन्नति कमेटी ने जिसके सदस्य का मेरा विश्वास है सेठ गोविन्ददास भी थे, यह अनुमान लगाया कि कुल २८.४ करोड़ तानरैकरिंग और १२.८ करोड़ रुपये रैकरिंग इस कार्य पर व्यय आयेगा। इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सम्बन्धित सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी—(चित्तौड़)—क्या यह सब कुछ प्रासंगिक है ? यहां प्रश्न कानून बनाने का है, गोमदन का नहीं।

अध्यक्ष महोदय—उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री एम० वी० कृष्णास्वामी—जब इन विधेयक के सम्बन्ध में बात करते हैं तो माननीय सदस्यों को यह गन्धना चाहिये कि यह सारे देश

के साथ सम्बन्धित है। मानो आज हम उपयोगी और अनुपयोगी सभी पशुवध बन्द कर देते हैं। अनुमान है कि इस देश में डेढ़ करोड़ अनुपयोगी पशु हैं। हम इन डेढ़ करोड़ पशुओं के बारे में क्या करने जा रहे हैं? हमें समझना चाहिये कि उनको कहाँ रखना है और कहाँ उनका लालन-पालन करना है। यही कारण है कि देश में गोसदनो की आवश्यकता है। हमें पूरी जाच करनी चाहिये और भली-भाँति यह समझना चाहिये कि इन गोसदनो में पशुओं को रखने पर क्या खर्च आयेगा।

पं० ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव)—क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गवर्नी महोदय ने यह डेढ़ करोड़ अनुपयोगी पशुओं के आँकड़े कहाँ से प्राप्त किये हैं?

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—यह सरकारी आँकड़ों से प्राप्त किये हैं।

पं० ठाकुरदास भार्गवः—यह सरकारी आँकड़े नहीं हैं। इससे बहुत कम संख्या है। यह आँकड़े असत्य हैं। कोई आँकड़े एकत्र नहीं किये गये।

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—हमारे आँकड़ों के अनुमान अनुसार देश में २० करोड़ पशु हैं, उनमें से १५ करोड़ गाय और बैल हैं और ५ करोड़ के लगभग भैंसे। लगभग १० प्रतिशत या कम से कम ऐसे डेढ़ करोड़ पशु हैं जो अनुपयोगी हैं। इसलिये जब हम गोहत्या को बन्द करने के लिये कानून बनाने के विषय पर सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि गोसदन बनाने और उन्हें चलाने पर भविष्य में रैकरिंग और नानरैकरिंग क्या व्यय होगा।

श्रीमति जी, मुझे यहाँ देश की गायों के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं किसान हूँ। और इस देश के ग्रामीण आर्थिक जीवन में गौ का क्या महत्व और स्थान है, मैं भली-भाँति जानता हूँ। मैं गौ की तुलना सिन्दड़ी के कारखाने से कर सकता हूँ। मेरे लिये हर

गौ छोटा सा सिन्दड़ी का कारखाना है। दूध के अतिरिक्त यह खाद भी देती है। हमारे ट्रैक्टर खाद नहीं देते जबकि गौ खाद भी देती है।

श्री नन्दलाल शर्मा—एक आपत्ति है। मैं यह संकेत करना चाहता हूँ कि सदस्यों को सदन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि कौरम पूरा न रह सके।

श्री वी० जी० देशपांडे—वह मत विभाजन नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय—कोई आपत्ति नहीं। यदि कौरम पूरा न हुआ तो मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित करने पड़ेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे—वे इसे लम्बा कर रहे हैं।

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—मैंने गौ की तुलना सिन्दड़ी के कारखाने से की, दूध देने और किमानों को हल आदि के काम में आने के अतिरिक्त यह खाद भी देती है और जो अन्न उत्पन्न करने के लिए बड़ा महत्व रखती है। मैं हर पशुचाला का चितरञ्जन कारखाने से तुलना कर सकता हूँ। यह साँड और बैलों के रूप में महान खेचने वाली शक्ति का निर्माण करती है और इन देश की सहायता करती है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि मैं जनता के साथ महानुभूति नहीं रखता जो देश में गोहत्या को बन्द करने के महत्वपूर्ण कार्य पर जोर दे रही है। पर ऐसा करने में उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं माननीय सदस्यों को यह महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। एक गौमन्वर्धन परिपद है जिसके सेठ गोविन्ददास भी सदस्य हैं। वहाँ हमने उचित काम किया है सेठ गोविन्ददास उस उपसमिति के भी सदस्य हैं जिसने एक विधेयक बनाकर सारे देश में भेजा। हमने एक नमूना के लिए विल बनाया और वह सभी राज्यों को भेजा गया और सेठ गोविन्ददास इस बात पर सहमत हैं कि गोहत्या को रोकने के लिये केन्द्र को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

सेठ गोविन्ददास—श्रीमति जी, व्यक्तिगत व्याख्या के लिए।

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त। उन्हें समाप्त कर लेने दीजिए।

सेठ गोविन्ददास—मैंने यह कभी नहीं कहा । हमको तो उस वक्त तक सन्तोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून की एक बुँद भी इन पुण्यनयी भारतभूमि पर गिरनी है । मैंने केवल यह कहा था कि अगर सरकार अभी इतना करने को तैयार नहीं है तो कम से कम एक नमूना का बिल पास करदे । इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस से सहमत हूँ । मैं तो सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करने के पक्ष में हूँ । आज ३३ वर्षों से वरन् जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इस पक्ष में हूँ ।

पं० टाकुरदास भार्गव—क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार इस विधेयक को लागू करना चाहती है ?

श्री एम० बी० कृष्णाप्पा—हां, यही कारण है कि कमेटी ने इस विधेयक को भेजा है ।

श्री एन० राचिया—(मैमूर सुरक्षित) श्रीमति, एक ग्रापति है, कार्रम पूरा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय—यदि होता भी तो समय समाप्त होजाने के कारण अब कार्यवाही समाप्त होती है ।

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

१२ मार्च १९५४

श्री उपाध्यक्ष महोदयः अब सदन सेठ गोविन्ददास जी के २७ नवम्बर १९५३ के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा ।

“देश के दुवारू तथा भार वाहक पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये ।”

श्री वी, जी, देशपांडे (गुना)—मैं यह कह दूँ कि स्वयं गित करने का प्रस्ताव उपस्थित और पान हुआ था ।

कृपि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख)—जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह आपत्ति की गई थी कि यह अवैधानिक है । मैंने यह मुझाव दिया था कि विवि मन्त्री का इस विषय पर अपना मत देना चाहिये ।

श्री वी, जी, देशपांडे—यह क्लिग दिया जा चुका है कि यह अवैधानिक नहीं है इसे उपस्थित किया जा सकता है । इस लिये हमें इस पर और समय क्यों गंवाना चाहिये ।

पं० ठाकुरदास भागवत (गुड़गांव)—यह आपत्ति उठाई गई थी और अध्यक्ष महोदय ने यह क्लिग दिया था कि सदन के अनुसार इसके

वैध होने का निर्णय सदन द्वारा दिया जायेगा और विधेयक को वैध घोषित किया गया था। इसलिये अब यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

सेठ गोविंद दास यह-रूलिंग आप ने दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय-विधि मन्त्री को अपना मत देने के लिये बुलाना इस रूलिंग के अनुकूल ही है। विधि मन्त्री को अपना मत देने के लिये बुलाने में मेरा यह उद्देश्य है कि सदन कोई निर्णय ले सके। यह मेरे रूलिंग के विपरीत नहीं है। विधि मन्त्री को मुनगा सदन का अधिकार है और विधि मन्त्री को सदन में भाषण देने का अधिकार है। इसलिये मन्त्री महोदय कुछ बोलेंगे।

डा० पी. एस. देशमुख-बया मैं एक मिनट के लिये दगल दे सकता हूँ। हमारी यह इच्छा थी कि इस विषय पर अटार्नी जनरल अपना मत व्यक्त करें, पर दुर्भाग्य से वह आज प्राप्त नहीं। मेरी इच्छा है कि इसे आज किसी और दिन के लिये छोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय-तब किसी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करना चाहिये।

पं० ठाकुरदास भार्गव—विधान के अनुसार अटार्नी जनरल को सदन में भाषण देने का अधिकार है। मेरा विचार है कि आज हम इस विधेयक पर विचार करना स्थगित करके इसे किसी और मरकाज के दिन पर छोड़ दिया जाये, क्योंकि यह विधेयक अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और इस में समस्त देश रुचि ले रहा है। मैं नम्रता से सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वह इस विधेयक को प्रधानता दे ताकि जिन दिन इस पर विचार होगा इस पर आधा घंटा से अधिक समय नहीं लगेगा।

संसदीय विषय सम्बन्धी मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) जिस दिन सरकारी कार्यक्रम का दिन होगा, सरकार इस के लिये समय देने को तैयार है।

श्री एन. सी. चैटरजी-बया मुझे कुछ बताया जा सकता है कि

सरकारी विधेयक वाले किस दिन समय दिया जायेगा ?

श्री सत्यनारायण सिनहा—जब गृह्यता की मांगें समाप्त हो जायेंगी तो हमें १५ या १६ दिन मिलेंगे, जिन में सरकारी कार्य करने हैं। उन में से किसी भी दिन इस विषय के लिये समय दिया जा सकता है।

श्री पं० ठाकुरदास भार्गव—यदि हम विधेयक की बिना सरकारी दिन निश्चय किये ही बारी आ जाये तो सरकारी दिन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ? यदि इसकी अपनी बारी नहीं आती तब इसके लिये सरकारी दिवस पर अवश्य ह्रा समर्थ मिलना चाहिये।

सैठ गोविन्ददास—मुझे यह कहना है कि अगर आप इस विधेयक को किसी गैर सरकारी दिन के लिए मुलतवी करना चाहते हैं तो वह मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि गैर सरकारी दिन के लिए इसको बैलट में लाना होगा, लेकिन अगर मुझे सरकारी दिन मिलना दे और वह भी इसी सेशन में, जल्दी में जल्दी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्री० जी० देशपांडे—एक आपत्ति है। स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित और पास हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य उस समय आपत्ति उठा रहा है जबकि मैं उठ रहा हूँ। जहाँ तक विधेयक का सम्बन्ध है अन्य किसी विधेयक की अपेक्षा इसे प्रधानता मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि इसके कुछ भाग या अंश पर ही विचार हुआ है।

सैठ गोविन्ददास—परन्तु नियमानुसार ऐसा नहीं होता। मेने सचिव महोदय से परामर्श किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि यदि इसे किसी गैर सरकारी दिन के लिए स्थगित किया जाए तो इसे क्रमानुसार रख दिया जाता है। मैं इस विधेयक को नहीं चाहता कि अपनी बारी पर आवे।

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री इस बात पर सहमत होंगे हैं कि जैसे मांगें पास होंगी, इस को समय दे दिया जायेगा।

श्री एन० सी० चैटरजी—यदि वह सहमत हैं तो हमें कोई दिन बजट के पास होने के बाद जीघ्र ही मिलना चाहिये ।

श्री सत्यनारायण सिनह—हमने उसके लिए विराम दिला दिया है और वह क्या चाहते हैं ?

श्री एन० सी० चैटरजी—हम चाहते हैं कि केवल आधा घण्टा ही न दिया जाये, यदि विधि मन्त्री और प्रान्तीय जनरल ने इस विषय पर बोलना है कि विधेयक अवैध है तो मेरी प्रार्थना है कि हमें भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर प्राप्त होना चाहिये ।

डा० पी० एस० देशमुख—हमारे वह इच्छा नहीं है कि समय पर कोई बन्धन लगा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय—कोई सदस्य यह प्रस्ताव करे कि अब इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाये ।

सेठ गोविन्ददास—किसी सरकारी दिन के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय—सदन ऐसा विश्वास नहीं दिना सकता ।

पं० ठाकुरदास भार्गव—इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करूँ कि इस विधेयक को किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये ? यदि गैर सरकारी दिन इसकी वारी पहले आ जाये तो उस दिन अन्यथा सरकारी दिन...

उपाध्यक्ष महोदय—ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता ।

पं० ठाकुरदास भार्गव—कोई प्रतिबन्ध नहीं है । आपने अभी कहा था कि इस विधेयक को प्रधानता मिलेगी । मेरी कैपल यही इच्छा है कि इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र ले लिया जाये । यदि इसको अपनी वारी पर प्रधानता नहीं मिलती तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको पहले ही सरकारी दिन ले लिया जाये ।

“कि इस विधेयक पर आगे विचार स्थगित किया जाये”

सेठ गोविन्द दास—कृपया यह भी सम्मिलित कर लें, जैसे ही

बजट पर वाद-विवाद समाप्त हो इसको पहले ही सरकारी दिन ले लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय—मैं आज तिथि निश्चित नहीं कर सकता । नियम बने हुये हैं और उनके अनुसार ही कार्य होगा ।

डा० पी० एस० देशमुख—हमने जो विश्वास दिलाया है ।

सेठ गोविन्द दास—नियमानुसार भी यदि सरकारी पार्टी का मुख्य सचिव हमें विश्वास दिलाये कि वह गैर सरकारी दिनों में पहले या सरकारी दिन इसे लेने को तैयार हैं तो भी मेरे विचार में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री सत्यनारायण सिनहा—मैंने उनको पहले ही विश्वास दिलाया है । मैं नहीं जानता कि अब वे और क्या चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया है कि किसी सरकारी दिन इस विषय के लिये समय दे दिया जायगा । सरकारी समय का अर्थ है वह समय जब सरकारी विधेयक सम्बन्धी समय हो और बजट पर वाद-विवाद का नहीं । अब मैं सदन का मत प्राप्त करने के लिए प्रश्न रखूंगा ।

प्रश्न यह है—

‘कि इस विधेयक पर आगे विचार करना स्थगित किया जाये ।’

प्रस्ताव पास हुआ ।

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर

१ मई सन् १९५४

को

अटार्नी जनरल का वक्तव्य

अटार्नी जनरल (श्री एम. सी. सेतलवाड)—श्रीमान् जी, मेरा विचार है कि १९५२ के “भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक” के सम्बन्ध में पास करने का इस संसद को अधिकार है यह नहीं, यह प्रश्न है। वास्तव में प्रश्न का विधेयक औचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं, प्रश्न तो केवल यह है कि क्या यह विधेयक संसद के अधिकारों की सीमा में आता है अथवा नहीं।

हम सब जानते हैं कि देश की विधि बनाने की शक्ति दो भागों संसद तथा राज्य में बटी हुई है। संसद का अलग क्षेत्र है। संसद और राज्य का समवर्ती क्षेत्र है और राज्यों का भी अपना अलग क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कुछ बचे-खुचे क्षेत्र हैं जिन पर संसद का अधिकार है।

जब ऐसा करना उत्पन्न होता है तो उसको समझने का ढंग ही अच्छा समझा जाता है। उस समय विधेयक के विषय का निरीक्षण

किया जाता है जिसे कानून की भाषा में विधेयक का सार कहते हैं यह सार केवल विधेयक की ऊपरी भाषा से नहीं देखा जाता बल्कि भाषा के पीछे भाव, विधेयक का वास्तविक उद्देश्य और इसके अनुसार कार्य कैसे होगा आदि बातों से किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है उस ढंग के अनुसार इस विधेयक पर विचार करने से पहले हम विधेयक सम्बन्धी सूत्रियाँ देखें जिन में इस विषय का वर्णन प्राप्त होता है। यदि यह संसद् के क्षेत्र में है या राज्य के क्षेत्रों में तब तो इसके सम्बन्ध में सीधे ही लिया जा सकता है कि या तो इसे बनाने का अधिकार संसद् को होगा या राज्य को और यदि यह समवर्ती क्षेत्र में आता है तो दोनों संस्थाएँ विधेयक के अनुसार उसे बना सकती हैं।

इस नियम को इस पर लागू करें तो पहले इसके विषय को देखना होगा। इस विधेयक का लम्बा शीर्षक यह है "देश के दुधारू तथा भारवाहक पशु परिरक्षण विधेयक" यदि इसके उद्देश्य को देखा जाये तो बड़ा स्पष्ट है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसको भारवाहक पशुओं की आवश्यकता है। यहाँ दूध का भी अभाव है इसलिये दुधारू पशुओं की भी आवश्यकता है। इसलिये दुधारू और भारवाहक पशुओं का परिरक्षण और सम्बर्द्धन इनके बच को रोक कर करना अत्यावश्यक है। इस विन का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि देश के दुधारू और भारवाहक दोनों प्रकार के पशुओं के परिरक्षण के लिये कानून बनाया जाये। इसकी पूर्ति के लिये इस विधेयक की तीसरी धारा बनाई गई है जो पशु को खाद्य तथा अन्य किसी कारण से बूचड़वाने, किसी सार्वजनिक या गुप्त स्थान पर मारने से रोकती है। यदि विधेयक की हर वस्तु को ध्यान से देखा जाये तो उद्देश्य और तत्व तथा सार की दृष्टि से विधेयक स्पष्ट है। इसका उद्देश्य अपने देश के कृषि करने वाले, भारवाहक, हल चलाने वाले और दुधारू पशुओं का परिरक्षण करना है।

विधेयक के सार को समझने के पश्चात् हमें यह देखना है कि विधान के अनुसार यह कहा उचित बैठता है। और जबकि वर्तमान स्थिति में संसद् से इसका सम्बन्ध है, पहले हमें पहली सूची सत्र की

सूची देखनी चाहिये ऐसा करने पर हमें इस सूची में कोई ऐसी प्रविष्टि नहीं मिलती जिसमें यह समा सके। फिर हमें समवर्ती सूची देखनी चाहिये और उसमें देखा जाये कि यह उसकी किसी प्रविष्टि के अनुसार है। यहाँ भी मुझे ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई देती जिसमें इसका वर्णन हो। जब हम इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं तो समस्या समाप्त समझनी चाहिये क्योंकि जहाँ तक संसद् के अधिकारों का सम्बन्ध है उनका वर्णन संघ तथा समवर्ती क्रमशः प्रथम तथा तृतीय सूची में है। पर यह देखना भी उपयोगी रहेगा कि क्या इस विषय का वर्णन राज्य सम्बन्धी सूची की किसी प्रविष्टि में है अथवा नहीं। ऐसा करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इस विधेयक का सम्बन्ध राज्य से है। मैं प्रविष्टि १५ का वर्णन कर रहा हूँ जो इस प्रकार है। पशु की नसल का परिरक्षण संरक्षण और उन्नति। इस विधेयक के उद्देश्यों में से एक यह भी है कि पशु नसल का परिरक्षण और संरक्षण हो। आगे जहाँ तक इसका सम्बन्ध ऐसे प्रयत्नों से है कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ाया जाये उनका सम्बन्ध जगता के स्वास्थ्य से है, जो राज्य की सूची में प्रविष्टि ६ के अनुसार है। इससे यह बात स्पष्ट होगी कि यह विधेयक राज्य से सम्बन्ध रखने वाली इन दो प्रविष्टियों के अनुसार है। हम उस प्रविष्टि के बारे में भी विचार कर सकते हैं जो कृषि सम्बन्धी है क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्यों में से एक कृषि सम्बन्धी है। यह प्रविष्टि १४ है और इसका तात्त्विक प्रविष्टि २७ से है जिसमें 'वस्तुओं के उत्पादन सम्मरण और वितरण' का उल्लेख है। इस दूध का उत्पादन सम्मरण और वितरण भी सम्मिलित माना जा सकता है।

इससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस बिल का विषय उन सूचियों में नहीं मिलता जो संसद् के अधिकार में हैं अर्थात् पहली तथा तीसरी सूचियों में इसका वर्णन नहीं। इसका वर्णन दूसरी सूची में है जो राज्य विधान सभा के अधिकारों से सम्बन्ध रखती है। इसका परिणाम निकलता है कि संसद् को इस विधेयक को पास करने का अधिकार

नहीं है।

“राज्य की नीति के निर्देशक तत्व” की धारा ४८ के सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता है। निःसन्देह इस धारा में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का वर्णन है। मैं उन शब्दों को पढ़ता हूँ—“गी तथा बछड़े, बछड़ियों और अन्य दृवाह नया भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध। मेरा धारा ४८ की नीति ने कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा तो इससे इतना ही सम्बन्ध है कि मैं यह बता दूँ कि इस धारा का वैधानिक अधिकारों के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। जिस परिच्छेद में यह धारा दी गई है उसमें राज्य के निर्देशक तत्व दिये गये हैं। जैसा हम जानते हैं। यह शीर्षक विधेयक बनाने के नहीं और यह वैधानिक अधिकार किसी विधान सभा को नहीं देता। हम यह भी जानते हैं कि यह निर्देशक तत्व विपरीत नहीं है कि इस विषय को कानून के लिये न्यायालय में उपस्थित किया जाये। दूसरे शब्दों में इन निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया जा सकता। मेरे विचार में इस मामले विषय की यह स्थिति है।

श्री गुरु० सी० चैटरजी—यथा हम भी इस विधेयक को संसद के अधिकारों की सीमा में सिद्ध करने के लिये वक्तव्य दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त। माननीय सदस्यों ने देखा कि माननीय अटार्नी जनरल ने अपने मतानुसार इस विषय पर वक्तव्य दे दिया है। प्रायः वक्तव्यों पर वाद विवाद करने की हमारी रीति नहीं है। और यह विधेयक अपने ठीक समय पर पुनः विचाराधीन होगा और उस समय माननीय सदस्यों को इस पर वाद विवाद का अवसर प्राप्त होगा। वे अटार्नी जनरल के मत का भी लाभ उठा सकते हैं और उसके अनुसार इसे अस्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं। उस समय सदन में इस विषय पर मुला विवाद होगा। आज उनके वक्तव्य पर विवाद करने का अवसर नहीं।

श्री रायवाचारी (पेनू कोंडा) यदि कोई शंका हो और उसे कोई

दूर करना चाहे तो इसकी आज्ञा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय—मुझे भय है कि इसकी आज्ञा नहीं। यदि मैंने एक बार किसी शंका या प्रश्न या शका के रूप में किसी तर्क-वितर्क की आज्ञा दे दी तो इसका अर्थ होगा कि मैंने वाद विवाद को नियन्त्रण दे दिया है। इसका यह परिणाम होगा कि यह भविष्य के लिये रीति-वन जायेगी।

श्री राधेलाल व्यास—(उज्जैन) मैं कुछ कह सकता हूँ ? अटार्नी जनरल महोदय ने हमारे विचारों को नहीं सुना। यदि उनके लिये उस दिन उपस्थित होना सुविधाजनक हो जिस दिन इस विधेयक पर वाद-विवाद होगा...

अध्यक्ष महोदय—इस पर विचार किया जा सकता है। यदि सदन की ऐसी इच्छा होगी तो उनसे प्रार्थना की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ऐसे दिनों में वह ऐसी सुविधा प्राप्त कर लेंगे कि सदन में उपस्थित हो सकें।

श्री गैडगिल—(पूना) क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ? अव्यक्ष ने यह रूलिंग कभी नहीं दिया कि अमुक विधेयक वैध है या अवैध। क्या यह रूलिंग उस समय वापिस ले लिया जायेगा। जब यह निर्णय हो जायेगा कि यह इसके अधिकार में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय—शायद मैं माननीय सदस्यों पर प्रकाश डाल सकूँ कि इस सदन में क्या हुआ। यदि मैं भूल नहीं करता, प्रश्न उठाया गया था पर अव्यक्ष ने इसका निर्णय सदन के ऊपर छोड़ दिया था। सदन की इच्छा थी कि अटार्नी जनरल महोदय इस विषय पर अपना मत व्यक्त करें। अटार्नी जनरल महोदय से वक्तव्य देने की प्रार्थना की गई। दो मिनट पूर्व जो मैंने यह कहा कि इस प्रश्न पर सदन में खुला वाद विवाद होगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने कोई निर्णय दे दिया है।

सेठ गोविन्ददास—अव्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था

कि यदि यह विधेयक आगे फिर वहम के लिये आने वाला है तो यह कब आयेगा, क्योंकि जिस समय मैंने इसका मुन्तर्वा किया जाना स्वीकार किया था उस समय मैंने यह कह दिया था कि मैं यह नहीं चाहता कि यह विधेयक फिर से गैर सरकारी दिन आये क्योंकि उसमें वैंलट का भगड़ा पड़ जाता है, और पार्लियामेंटरी अफेयर्स के जो मन्त्री सहोदय हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इसी मेगन में किसी न किसी सरकारी दिन ले आया जायेगा। अब यह अधिवेशन २१ मई को समाप्त हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहता था कि उनके आश्वासन के अनुसार यह किस सरकारी दिन आयेगा। क्योंकि उन्होंने ही यह आश्वासन दिया था कि यह सरकारी दिन आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि इसको इस तरह मुन्तर्वा कर दिया जाये ताकि यह न उस सेशन में आ सके और न अगले सेशन में आ सके और वैंलट के भगड़े में पड़ जाय। सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है यह सरकार को घोषित करना चाहिये क्योंकि देश यह जानना चाहता है कि सरकार इन विषय में क्या करना चाहती है। यह विषय सारे देश में इतने महत्व का हो गया है कि वह चाहता है कि वह किसी न किसी सरकारी दिन आ जाये और इसी सेशन में हो जाये।

अध्यक्ष महोदय—मैं तो यह समझता हूँ कि सरकार को जैसा योग्य लगे उसी रीति से वह निवेदन करे। अभी जो वक्तव्य अटार्नी जनरल साहब ने दिया है उसके साथ इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने तो वैधानिक स्थिति के द्वारे में अपनी राय दी है। तो यह इतना ही है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि जब यह बिल आयेगा, मैं नहीं जानता कि कब आयेगा, उस वक्त अभी जो चर्चा चल रही है वह हो जायेगी।

सेठ गोविन्ददास—कब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय—कब आयेगा यह तो आप मिनिस्टर साहब से मिल कर तै कर लें।

सेठ गोविन्ददास—आप उनसे पूछ लें।

अध्यक्ष महोदय—हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

७

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर

२१ मई सन् १९५८

को

कृषि मन्त्री डा० पी. एस. देशमुख का वक्तव्य

कृषि मन्त्री डा० पी. एस. देशमुख---श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं सेठ गोविन्ददास के "भारतीय पशु संरक्षण विधेयक, १९५२" के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूँ। ग्रटार्नी जनरल महोदय ने तो इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यद्यपि इसमें कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है इसे स्पष्ट करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पशु परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये जो साधन अपनाये हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकारों को जो आदेश भेजे गये उनका उल्लेख भी आवश्यक है।

यह ऐसा सर्वप्रिय विषय है जिसके साथ समस्त समाज की भावनाएँ सम्बन्धित हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि मैं सदन के सन्मुख इस कठिन और महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता और इसके भ्रंभट तथा इसके

प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, इस पर प्रकाश डाला जाये। यह इस कारण और भी आवश्यक है क्योंकि इसमें राजनैतिक लाभ उठाने के प्रलोभन को सदैव रोका नहीं जा सकता है और समय पर ऐसे सत्य तथ्यों की उपेक्षा की जाती रही है जिनके करने के लिये किसी प्रकार की भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। सरकार को ऐसे सभी वास्तविक तथ्यों पर विचार करके एक ऐसी नीति निर्धारित करनी है जो जनता के भावनाओं को ठेस भी न पहुंचाये और देश के हितों की रक्षा भी हो सके।

मे सबसे पहले इन समस्या के महत्व और परिमाण को लूंगा। देश के पशुओं की कुल संख्या २२ करोड़ है। इसमें से १० से लेकर ३० प्रतिशत तक को पशुसंख्या अनुपायोगी कहलाने वाले पशुओं की है। पशुओं की इतनी बड़ी संख्या की देश की ३६ करोड़ जनसंख्या से ख़ाद्य पदार्थ और चारे की दृष्टि से जो देश की कृषि योग्य भूमि में प्राप्त होता है। (एक प्रकार की स्वभाव गणी हुई है) अनुमान यह है कि एक पशु के लिये २ एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

इस आधार पर पश्चिमी जंगल में जहाँ एक करोड़ पशु हैं, दो करोड़ भूमि की आवश्यकता है। पर क्योंकि वहाँ केवल १ करोड़ भूमि ही कृषि योग्य है। इसलिये ये २२ करोड़ पशुओं की ३६ करोड़ जनता से तुलना के बन्धों का प्रयोग किया है उनकी उपयोगिता यहाँ सिद्ध होती है। सोभाग्य से सारे देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जितनी कि समस्या है जटिल है और यदि इसका धम ठोक-ठीक हल में प्रबन्ध करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सम्भव नहीं।

श्री गैडगिल—(पुना) प्रश्न यह है कि क्या इस विषयक को पान करने का अधिकार इस नसद को है। इस विषय पर सरकारी दृष्टिकोण क्या है यह बनावट अन्य बातों का सबको पता है।

डा० पी. एम्. देशमुख—श्रीमान् जी, मेरा विचार है कि मैं कहता चूँ।

मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत अधिक संख्या को पाला जाता है पर उसको पेट भर चारा नहीं मिलता। ऐसा सम्भव भी नहीं है। इसका यह परिणाम हुआ कि पशुओं की स्थिति बहुत ही खराब है। जितनी स्थिति खराब होगी पशु उतना ही कम उत्पादक होगा। इस प्रकार पशुओं की प्रगतिपूर्ण अवन्नति हो रही है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं.....

अध्यक्ष महोदय—यदि सदन को अधिकार नहीं है, इस सबको पढ़ने का क्या अर्थ है? माननीय मन्त्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि यह विषय संव सम्बन्धी सूची में नहीं इसलिये इस संसद को इसे पास करने का कोई अधिकार नहीं।

डा० पी. एस. देशमुख--श्रीमान् जी मैं आपके निर्णय के अनुसार कर रहा हूँ। मैं इसे सदन की मेज पर रखने को तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय---माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपियां बांट दी जायेंगी।

सेठ गोविन्द दास--उपाध्यक्ष जी, यह वक्तव्य होने के बाद मैं यह जानना चाहता था कि अब मेरे विधेयक का क्या होगा, क्योंकि पहले एक वक्तव्य हुआ अटार्नी जनरल साहब का उसके बाद दूसरा वक्तव्य हुआ मन्त्री जी का, और जो श्री सत्यनारायण सिन्हा जी ने मुझे विश्वास दिलाया था, १२ मार्च को, वह यह था कि यह बिल किसी दूसरे सरकारी दिन लाया जायगा। तो अटार्नी जनरल साहब का वक्तव्य हुआ, उस पर भी हमें बहुत कुछ कहना है और आपका जो अभी वक्तव्य हो रहा है और जो अभी टेबुल पर रखा जा रहा है उस पर भी हमें बहुत कुछ बोलना है और मैं जानना चाहता हूँ कि वह विश्वास जो हमारे संसदीय मन्त्री साहब ने हमें दिलाया था कि यह विधेयक किसी न किसी सरकारी दिन प लिया जायगा वह अभी भी मौजूद है या नहीं और मैं जानना चाहता हूँ कि यह बिल अगले सेशन में किसी सरकारी

के लिये प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहना चाहिये । यह विधेयक से तनिक भिन्न है । मैं नहीं जानता, यदि कोई भूल हो तो ठीक कर दें, कि कृपि मन्त्री महोदय सम्भवतया इतने लम्बे वक्तव्य को कब समाप्त करने का निश्चय किया है । मेरा विश्वास है कि वह अपने वक्तव्य के अन्त में कोई विशेष कमेटी बनाने का घोषणा करेंगे जिसे खाद्य तथा कृपि मन्त्री शीघ्र ही नियुक्त करने वाले हैं यह इतनी विशाल समस्या पर नहीं बल्कि कुछ ऐसी आवश्यक बातों की जाँच के लिये होगी, जो इससे सम्बन्धित है और जिनकी रिपोर्ट विशेषज्ञों को शीघ्र ही देनी चाहिये ।

श्री एन० सी० चैटरजी—मैं एक बात कहना चाहता हूँ । अटार्नी जनरल महोदय के भाषण के एकदम बाद ही मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ यह सिद्ध करने के लिये कि यह वैध और विधान के अनुसार है कहना चाहता था । अध्यक्ष महोदय ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि अगली बार जब विधेयक पर वाद विवाद होगा तो हमें यह विधेयक वैध है या नहीं यह सिद्ध करने के लिये बोलने को समय मिलेगा । मेरे विचार में उस दिन वाद विवाद स्थगित इसी आधार पर हुआ था । इसलिये हमें भी इस विषय पर वक्तव्य देने का अवसर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय—स्थिति स्पष्ट है । यदि विधेयक गैर सरकारी दिन या अपनी बारी से आयेगा तो इसको वहीं से आरम्भ किया जायेगा जहाँ छोड़ा था । सदन की स्वीकृति के बिना अध्यक्ष अपनी इच्छा से किसी विधेयक को समाप्त करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेता । अध्यक्ष सदन पर छोड़ देता है । मैं तो सुझाव ही दे सकता हूँ । सम्भव है अध्यक्ष कोई अन्य मार्ग अपना ले । पहले वह वैधानिक विषयों को समाप्त कर ले, दोनों ओर के तर्क-वितर्क सुने, उसे सदन के सम्मुख उपस्थित करे और यदि सदन यह निर्णय दे तो हम बढ़ते हैं और उस विषय पर वाद विवाद करते हैं । यह उसके लिये छूट है । मैं अध्यक्ष को विवश नहीं कर सकता वह किसी भी विषय पर अपने उचित दृष्टिकोण

जब अगले अधिवेशन में यह संसद् के सम्मुख उपस्थित हो बना सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आज मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् यह विधेयक पूर्णतया समाप्त हो जायेगा या आगे के लिये इस पर वाद विवाद करने पर कोई प्रतिबन्ध लग जायगा। यह सदन के हाथों में है। सदन को इससे वंचित कर दिया गया है। आगे इस पर वाद विवाद नियमानुसार होगा। हमें आरम्भ करना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

डा० पी० एस्० देशमुख—मैं अपने वक्तव्य का बचा अंश अब उपस्थित करना चाहता हूँ।

कुछ सदस्य—अच्छा, तो सारा ही लीजिये।

कृपि मन्त्री डा० पी० एस्० देशमुख का वक्तव्य

श्रीमानजी, आप की आज्ञा से मैं सेठ गोविन्ददास के “भारतीय पशु संरक्षण विधेयक १९५२” के सम्बन्ध में एक गभित वक्तव्य देना चाहता हूँ। अटार्नीजनरल महोदय ने तो इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यद्यपि इस में कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है इसे स्पष्ट करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पशु पारिक्षण तथा संरक्षण के लिये जो साधन अपनाये हैं और महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकारों को जो आदेश भेजे गये उन का उल्लेख भी आवश्यक है।

यह ऐसा सर्वप्रिय विषय है जिस के साथ समस्त समाज की भावनाएँ सम्बन्धित हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मैं सदन के सम्मुख इस कठिन और महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता और इस के भङ्ग तथा उस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, इस पर प्रकाश डाला जाये। यह उस कारण और भी आवश्यक है क्योंकि इन से राजनैतिक लाभ उठाने के प्रलोभन को सदैव रोका नहीं जा सकता है और समय पर

ऐसे तथ्यों की उपेक्षा की जाती रही है जिन के करने के लिये किसी प्रकार की भी सुविधा प्राप्त नहीं थी सरकार को ऐसे सभी वास्तविक तथ्यों पर विचार करके एक ऐसी नीति निर्धारित करनी है जो जनता के भावनाओं को ठेस भी न पहुंचाये और देश के हितों की रक्षा भी हो सके ।

नै सत्र से पहले इस समस्या के महत्व और परिमाण का लूंगा देश के पशुओं की कुल सख्या २२ करोड़ है । इस में से १० से लेकर ३० प्रतिशत की पशुसंख्या अनुपयोगी कहलाने वाले पशुओं की है । पशुओं की इतनी बड़ी सख्या कि देश की ३६ करोड़ जनसंख्या से खाय पदार्थ और चारे की दृष्टि से तुलना है । जो देश की कृषियोग्य भूमि से प्राप्त होता है । अनुमान यह है कि एक पशु के लिये २ एकड़ भूमि की आवश्यकता है ।

इस आधार पर पश्चिमी बंगाल में जहाँ एक करोड़ पशु हैं, दो करोड़ भूमि की आवश्यकता है पर क्योंकि वहाँ केवल १ करोड़ भूमि ही कृषियोग्य है । इसलिये मैंने २२ करोड़ पशुओं की ३६ करोड़ जनता से तुलना के शब्दों का प्रयोग किया है उन की उपयोगिता यहाँ सिद्ध होती है । सौभाग्य से सारे देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जितनी कि समस्या जटिल है और यदि इस को हम ठीक रूप में हल करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सम्भव नहीं ।

मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ । बहुत अधिक सख्या को पाला जाता है पर उस को पेट भर चारा नहीं मिलता । ऐसा सम्भव भी नहीं ? इस का यह परिणाम हुआ कि पशुओं की स्थिति बहुत ही खराब है । जितनी स्थिति खराब होगी पशु उतना ही कम उत्पादक होगा । इस प्रकार पशुओं की प्रगतिपूर्ण अवन्नति हो रही है ।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं देश के भिन्न-भिन्न भागों में जब वे पशुओं की सन्तोषजनक रूप में देख-भाल नहीं कर सकते तो उन्हें

खुला छोड़ देते हैं। इस प्रकार यह पशु एक आपत्ति खड़ा कर देते हैं और जब वह जंगली हो जाते हैं जैसा कि कई स्थानों पर देखने में आया है तो वे फसलों को बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट करते हैं और पुनः उनको पकड़ना और पालना सम्भव नहीं होता है।

इस प्रकार हमारे देश में अन्य देशों में पशु संख्या में अधिक है। गुणों के दृष्टि से वह इतने अनुपयोगी हैं कि वह इतना भी दूध नहीं देते जितना कम से कम देश-वासियों के लिये आवश्यक है। उससे भी कम देते हैं। आज भी हमारे देश में अच्छे रूप में चल रहे दुग्धशाला में प्रत्येक पशु घर में पाले जाने वाले पशुओं से चार पांच गुना अधिक दूध देते हैं। आज हमारे पशुविभाग के क्षेत्र पशुओं को दूध और भारवाहन दोनों दृष्टि से उन्नत करना सम्मिलित है। साथ ही यह भी उत्तरदायित्व उसी पर है कि पशु उत्पादन का कार्य अच्छे नस्लों के सांडों द्वारा किया जाये और जब वे जवान और उपयोगी हो तो उनका पालन अच्छे ढंग पर हो और जब उनका उपयोग न रहे तो उनकी देखभाल सन्तोषजनक हो।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ पशु हल चलाने, भार उठाने, खाद देने, के प्रतिरिक्त निरामिष भोजी इतनी भारी बहुसंख्या को दूध देने के काम आता है। गौ का परिरक्षण तथा नस्ल सुधार और उन्नति का कार्य अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है। भारत का आर्थिक ढांचा वास्तव में गोधन पर आधारित है और इसी कारण गौ के प्रति समाज के सभी वर्गों में श्रद्धा की भावनाएँ पाई जाती हैं।

१९४७ में जब डा० राजेन्द्रप्रसाद जी खाद्य तथा कृषि मन्त्री थे एक पशु रक्षा तथा उन्नति कमेटी बनाई गई थी। उसने नवम्बर १९४८ में अपनी रिपोर्ट उपस्थित कर दी। २४ मार्च १९४९ को श्री जयरामदास दोलतराम ने जबकि वह सदन में भाषण दे रहे थे कहा था कि सरकार ने कमेटी के निम्नलिखित सुझावों को क्रियान्वित करना स्वीकार

कर लिया है ।

१. सर्वप्रथम निम्नलिखित पशुओं के प्रतिरिक्त सभी पशुओं के वध पर एक दम प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

(क) १४ वर्ष से अधिक आयु के और अनुपयोगी पशु ।

(ख) ऐसी सभी पशु जो आयु, चोट आदि के कारण मदा के लिये अनुपयोगी हो चुके हैं ।

२. बिन लाइसेंस और आज्ञा के पशुवध पर एक दम प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और ऐसा कानून बनाया जाये जिसके द्वारा पशुवध प्रवराध माना जाये ।

इसलिये सरकार ने गौशाला और पिंजरापोली की उन्नति के लिये भिन्न भिन्न राज्यों के गौशाला और पिंजरापोली के मध्य तथा केन्द्रीय गौशाला उन्नति बोर्ड बनाया । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इन संघों की नीति अनुसार कार्य करने का निवेदन किया है । उनके प्रतिरिक्त सरकार ने "केन्द्रीय ग्राम योजना" खोलन, सांड पालने और अनुपयोगी पशुओं को रखने के लिये गोशालाओं को सहायता देने की नीति को स्वीकार कर लिया है । पशुओं के परिरक्षण के लिये सरकार ने संतद ने गोसम्बर्धन विधेयक उपस्थित किया है । यह केवल 'ख' श्रेणी में राज्यों में लागू होगा । ३० जनवरी १९५२ के प्रस्ताव के अनुसार देश में गोसम्बर्धन की नीति को नई दिशा प्रदान की गई है और गोशाला उन्नति बोर्ड के स्थान पर केन्द्र में गोसम्बर्धन परिषद का निर्माण किया गया है ताकि पशुओं की नसल सुधार, उनके परिरक्षण और संरक्षण प्रथित उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग पर किया जा सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय गोसम्बर्धन परिषद काम कर रही है और यह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है ।

इस समय में राज्यों की स्थिति क्या है यह बतलाना चाहता हूँ । मध्यभारत, भोपाल और मैसूर में पशुवध सम्पूर्णतया बन्द है जबकि पेप्सू राजस्थान में गाय, बैल, बछड़े, उछड़ियों आदि की हत्या बन्द है

और बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, ट्रावकोर, कोचीन, मध्यप्रदेश और अजमेर में उपयोगी पशुओं के बच पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कोर्ग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मर्नापुर, त्रिपुरा, और विन्ध्य प्रदेश में पशुवध विशेषकर गोवध होता ही नहीं इसलिए उन राज्यों में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। कुछ क्षेत्रों में पहले ही से ऐसा कानून विद्यमान है जिस द्वारा बध बन्द है। दिल्ली की नगरपालिका ने गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। उत्तरप्रदेश में उन प्रश्न पर विचार और जाँच करने के लिए गोमम्बर्द्धन जाँच समिति बनाई गई है और बिहार विधान सभा में इन सम्बन्ध में विधेयक उपस्थित है।

सरकार विधान की धारा ८८ में दिए निदेशक तत्व की अपने आप को पाबन्द समझती है और उसके अनुसार नीति निर्धारित की है। सरकार कृषि तथा एनिमल इन्डस्ट्री दोनों में आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग पर उन्नत करना चाहती है। ३४० से अधिक की विलेज सैण्टर पहले ही स्थापित कर दिए गये हैं और अगले दो वर्षों में इनकी संख्या बढ़ा कर ६०० कर देने की योजना है। कृत्रिम गर्भाधान के १०० से ऊपर केन्द्र खोले जा चुके हैं और प्रथम योजना काल में १५० ऐसे केन्द्र खोलने की योजना है। सहायक (सर्वसाइडर्ड) योजना में सांड पालने के काम का प्रोत्साहन दिया गया है। इन केन्द्रों में प्रत्येक में कुछ ग्राम सम्मिलित है जहाँ के पशुओं की उन्नति की देखभाल इसके द्वारा होती है। ऐसे क्षेत्रों में नाकारा सांडों को बिक्री किया गया और जो गाय भैंस, नमल आदि के कार्य में आ सकती हैं इन केन्द्रों में उनके लिए बढ़िया नसल के सांड रखे गए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों की पशु संख्या आवश्यक रूप में शनः शनः उन्नति करेगी। साथ-साथ गोसदन भी स्थापित किये जा रहे हैं। जिन में अनुपयोगी पशु रखे जा सकते हैं यह योजना बनाई गई है और उसके अनुसार प्रायः उनकी स्थापना भी हुई है। कि वे ऐसे क्षेत्रों में बनाये जायें जहाँ अधिक चारा उत्पन्न होता है। जहाँ तक गोसदनों की उन्नति का प्रश्न है मुझे यह बात खेद से कहनी

पटनी है कि आजाओ के अनुसार उनका कार्य मन्तोपन्जन और नष्ट नहीं है। परन्तु मुझे विज्ञान है कि उन नौगदनों को नष्ट करने और इस से आवश्यक संख्या में पशु रखने के काम में जन नौगदनों को सकेना जो आज प्राप्त नहीं और अधिक नौगदनों की आवश्यकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए नौगदनों के पशुओं को रखने की योजना बनाई है और निम्नलिखित ही दूसरी योजना में भी इस ऐसा ही करेगी।

मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्दराय ने कहा कि मैंने बड़े नगरों में होने वाली गोहत्या का दिमाग उलट दिया है। मैंने बहुत सभ्यता जैसा कि सब जानते हैं पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को रखने शुरू जाते हैं उनका ऐसे नगरों में रखना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को रखना है। कुछ सीमित रूप में ऐसे दूध देने वाले पशुओं को रखने शुरू जाते हैं परन्तु एक व्यक्ति के लिए अपने सभी पशुओं को रखना बहुत बाहिर भोजन पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। मैंने बहुत बड़े बछड़े, बछड़ियों को मरने में नहीं बनाता क्योंकि अब नगरों में कदाचित्त या दूध देने के योग्य नहीं बन जाते लाभदायक निष्पत्ति नहीं मिले। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार चाहती है कि जितना शीघ्र हो सके ऐसे पशुओं को बड़े नगरों से ग्राम पास के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जाये जहाँ उनकी देखभाल पर आवश्यकता से अधिक व्यय न आवे। इस दिशा में कुछ सक्रिय पग उठाये गये और इस कार्य को और भी प्रगति की ओर ले जाने के लिए हर प्रयत्न किया जायगा। मेरे स्वयं अभी अभी कलकत्ता का दौरा किया है और मैं सबको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस दिशा में हृदय से कार्य करने की दृष्टि से बहुत अच्छा आरम्भ हो गया है। इन दोनों बड़े नगरों में सरकार स्थिति की बात करके उसे सुधारने और उत्तम करने के साधनों को अपनाता चाहती है। मैं इस बात का भी वहाँ वर्णन करूँगा कि मेरे मन्त्रालय के कारण दूध सूखी गायों को पंजाब में लाने के लिये रेल के किराये में कूट दी गई है। इस

सदन की इस विशेष मांग पर सरकार ने गोमास के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

इस प्रकार आपको पता लगेगा कि सरकार की योजना इस महान कठिन समस्या को रचनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और पूरी शक्ति लगा कर मुलभूत चाहती है और जो कुछ उसने किया है वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं । जो पशु ऐसे हैं कि उनको उन्नत किया जाना सम्भव है उनको उन्नत करना है और जो इस काम के अयोग्य हैं उनकी ऐसे क्षेत्रों में रख कर देख भाल करनी है, जहां पर्याप्त चारा है और उनकी देखभाल के लिये अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं । जहां तक समस्या के बड़े होने का प्रश्न है मुझे विश्वास है कि तथ्यों और इसकी जटिलता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं और यह ऐसी है कि हमें अपने साधनों और जनता की निष्क्रियता को सीमित करना होगा । मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा आरम्भ किया है । जैसा कि मेरा विचार है हमारी नीति बहुत अच्छी है इसके परिणाम अवश्य ही और विशेषकर प्रारम्भिक काल में शनैः शनैः प्राप्त होंगे । परन्तु जैसे ही जनता इसके महत्त्व को समझकर पूर्ण रूप में सहयोग देगी मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी । आज तो इतना भी सहयोग प्राप्त नहीं है जिसकी कम से कम उपेक्षा की जा सकती है । उदाहरणार्थ जैसा कि मैंने पहले कहा है, लोगों द्वारा वृद्ध और अनुपयोगी पशुओं को आज गोमदानों में भिजवाना बड़ा कठिन है । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी आर्थिक सहायता देने के आश्वासन पर भी प्रत्येक राज्य सरकार कई एक कारणों से “की विनेज स्टर्ज” और गोसदन खोलने के समान रूप में योग्य नहीं है ।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है इसके अतिरिक्त सरकार ने भी विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्णय किया है जो शीघ्र ही इस बात पर विचार करेगी कि वह क्या कदम उठाये—

१. उन दुधारू गायों की हत्या को जो अस्थायी रूप में सूख

जाती हैं रोकने के लिये विशेषकर कलकत्ता और बम्बई नगर में ।
 २. कृका जैसे दोष पूर्ण कार्यों को रोकने के लिये विद्यमान कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिये ।

३. उचित केन्द्रों में दूध का पाउडर बनाने की सन्धता की खोज करना और,

४. पशुओं के अन्तर्राज्यी निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना ।

श्रीमानजी, मुझे विश्वास है कि जो वक्तव्य मैंने दिया है उस से सदन के भीतर तथा बाहिर के लोगों को यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये हृदय से प्रयत्नशील है और वास्तव में इसे सुलझाने के लिये सावधानी से सारी शक्ति लगा रही है ।

परन्तु अटार्नी जनरल द्वारा दिये गये मत के कारण और यह भी तथ्य है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने अपने अधिकारों और राज्य सूची की प्रविष्टि १५ के अनुसार सक्रिय कदम उठा रही हैं । सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं कि यदि विधेयक पर मत लेने का निर्णय हुआ तो वह इसका विरोध करेगी ।



८

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

२ अप्रैल १९५५

अध्यक्ष महोदय—सदन के सम्मुख अगला कार्य सेठ गोविन्द दास का विधेयक है। प्रारम्भ में इस उपलक्ष में कुछ शब्द कहूँगा।

विधेयक १६ जुलाई १९५२ को उपस्थित किया गया था। २७ नवम्बर १९५३ को इस पर विचार हुआ। पुनः ११ दिसम्बर १९५३, २६ फरवरी १९५४ और १२ मार्च १९५४ को इस पर वाद-विवाद हुआ। १२ को वाद-विवाद का विषय भविष्य में विचार करने के लिये छोड़ दिया गया।

सदन की इस इच्छा पर कि अटर्नी जनरल का इस सम्बन्ध में मत लिया जाये कि क्या ऐसे विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार है? अटर्नी जनरल ने १ मई १९५४ को संसद में एक वक्तव्य दिया। जिस में यह बताया गया कि यह विधेयक राज्य-विधान सभाओं के अधिकार में है।

परिणाम स्वरूप २१ मई १९५४ को कृषि मन्त्री ने इस विधेयक पर एक वक्तव्य दिया जैसा कि सदन अपने वैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में

जानता है। अध्यक्ष ने यह सदन के निर्णय पर छोड़ दिया है। सदन की इच्छानुसार आज अटर्नी जनरल महोदय यहाँ उपस्थित हैं।

इस विधेयक के लिये जो चार घंटों का समय निर्दिष्ट किया गया था उस में से २ घण्टे और ५६ मिनट तो समाप्त हो गया और बाद-विवाद के लिये १ घण्टा और ६ मिनट बचे हैं।

सेठ गोविन्ददास अपने स्वयंसेवक पर अग पुनः विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

सेठ गोविन्द दास—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के दुष्कार और बाहक दोरो की रक्षा करने वाले दिन पर विचार किया जाय।

श्री एस, एस, मोरे—श्रीमान जी, क्या उन्होंने पहले ही प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय—क्योंकि पहले स्थगित हो गया था इसलिये उस पर पुनर्विचार के लिये फिर से प्रस्ताव करना होगा।

सेठ गोविन्ददास—मैंने वही तो कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाय यह मैं आप के सामने प्रस्ताव करता हूँ।

आप ने अभी बतलाया कि यह विधेयक यहाँ पर कब उपस्थित हुआ था और अबतक इस पर क्या क्या हुआ। मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि यद्यपि यह विधेयक यहाँ पर सन् १९५२ में ही उपस्थित हुआ परन्तु यथार्थ में केन्द्रीय धारा सभा में यह विषय सन् १९२६ से उपस्थित है। मैंने उस समय, यानी आज से २६ वर्ष पहले, इस विषय को कौंसिल आफ स्टेट में उपस्थित किया था और तब से किसी न किसी रूप में यह बराबर आता रहा है। आप ने अभी यह बताया कि इस पर हमारे एटर्नी जनरल का वक्तव्य हो चुका है, श्री पंजाबराव देशमुख का वक्तव्य हो चुका है और श्री पंजाबराव देशमुख के उस वक्तव्य के अनुसार उसी दिन श्री पी इन नन्दा के सभापतित्व में इस विषय पर विचार करने के लिये एक कमिटी नियुक्त हुई थी ' उस कमिटी के निर्देशन

की गत पर, उस के मुद्दों पर मैं आप का व्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस के मुद्दे थे।

१. उन दुधारु गावों की हत्या को जो अस्वाइ रूप में मूख जाती हैं रोकने के लिये विशेषकर कलकत्ता और बम्बई नगर में,

२. फूका जैसे दोषपूर्ण कार्यों को रोकने के लिये विद्यमान कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिये।

३. उचित केन्द्रों में दूध का पाउडर बनाने की सम्भवता की खोज करना, और

४. पशुओं के अर्न्तराज्यी निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण लगाना।

अब आप यह देखिये कि उस के बाद—

अध्यक्ष महोदय—मेरा विचार है कि पहले पुनर्विचार का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जाये उस के पश्चात् मान्य सदस्य बोलते जायें।

सेठ गोविन्ददास—मैंने पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव आप के सामने रखा और उस के बाद बोल रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में भी रख दूँ। मैंने हिन्दी में रखा था। अगर आप की समझ में नहीं आया है तो मैं अंग्रेजी में भी रख देता हूँ।

मैं यह उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ कि निम्नलिखित विषय पर जो वादविवाद १२ मार्च १९५८ को स्थगित कर दिया गया था उस को पुनः चालू कर दिया जाये। “कि देश में दुधारु और बाहक डोरों की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जावे।”

अध्यक्ष महोदयः प्रथम प्रस्ताव को ही उपस्थित करना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास—मैंने यह हिन्दी में उपस्थित कर दिया है कि अब मैं इस पर बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय—मैं यह कह रहा था कि यदि सदन आज्ञा दे तो सभी वह बोल सकते हैं।

सेठ गोविन्ददास—मुझे यह अवसर मिलना चाहिये कि मैं सदन के सम्मुख यह कह सकूँ कि वह मेरे इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करें।

श्री एस, एस, मोरे—क्या मैं कानूनी आपत्ति उठा सकता हूँ। हम इस पुनर्विचार के प्रस्ताव को तो समय दे सकते हैं। परन्तु जब मान्य सदस्य अपने विधेयक के उपस्थित करते समय ही पूरा भाषण दे चुके हैं तो क्या वह फिर उसी को दोहरा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय—मान्य सदस्य को संक्षेप में काम लेना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास—मैं तीन चार मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं इस पर इतना बोल चुका हूँ और मेरी, इस पर बोलने की इतनी इच्छा है कि जब तक गोवध यहाँ बन्द हो नहीं जाता तब तक मैं दिन रात, महीने में तीस दिन और साल में ३६५ दिन इस पर बोलना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर बहुत कुछ कह चुका हूँ। इसलिये बहुत थोड़े में मैं इसको खत्म कर दूंगा। मैं आप को यह बता रहा था कि इस कमेटी की राय क्या थी और उस कमेटी को रिफरेन्स होने के बाद उस ने क्या कहा यह मैं आप को बताना चाहता हूँ।

“पशु रक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार के विशेषज्ञों की समिति आठ भास पूर्व यह रिपोर्ट दे चुकी है कि उस के विचार में सम्पूर्ण गोहत्या को बन्द करना अनुचित है।”

मेरी यह समझ में नहीं आया कि कमेटी मुकर्रर की गई थी एक बात के लिए और कमेटी ने फैसला किया और सिफारिश की दूसरी बात की। मुझे संस्कृत का एक पद याद आ जाता है—

“विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरं”

यानी कमेटी को काम दिया गया था गणेशजी बनाने का लेकिन उसने मूर्ति बनाई केवल बन्दर की।

सभापति जी—अब जब हम इस विषय को केन्द्र में लाते हैं तब यह कहा जाता है कि इसको राज्यों के पास भेज देना चाहिए और जब हम इस विषय को राज्यों में उठाते हैं तो चूंकि केन्द्र में और राज्यों में दोनों जगहों पर कांग्रेस की हकूमते हैं इसलिए जो कार्रवाई कभी-कभी यहाँ पर हो जाती है उस कार्रवाई का असर राज्यों पर भी पड़ता है।

मुश्किल यह है कि हम इस विषय को निपटाना चाहते हैं पर कोई न कोई पैसा प्रश्न उपस्थित कर दिया जाता है जिस से यह प्रश्न न यहाँ निपटता है और न वहाँ निपटता है।

अब यह जो नन्दा साहब की रिपोर्ट है उसमें नन्दा साहब ने सन् १९४७-४८ में जो गज़ले गोरक्षा कमेटी बनाई गई थी उसमें यह सिफारिश की थी कि इन क्षेत्रों में गोवध बन्द किया जाये। इन्हीं नन्दा साहब ने उसके पक्ष में अपने दस्तावेज किए थे और इन्हीं नन्दा साहब ने आज इस कमेटी की रिपोर्ट के विषय में दस्तावेज किये हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या रवैया है और सरकार के अफसरों का जिनको कि विशेषज्ञ कहने में उनका क्या रवैया है। मैं इस सम्बन्ध में आज महात्मा गांधीजी की राय को फिर दोहराता हूँ। गांधी जी ने कहा था—

सभापति महोदय—प्राप जरा जल्दी खत्म कीजिये।

सेठ गोविन्ददास—मैं तीन चार मिनट में खत्म कर दूँगा।

अध्यक्ष महोदय—जो कुछ मैं बता रहा हूँ वह यह है। इस विषय पर वैधानिक आपत्ति उपस्थित की गई है और अटर्नी जनरल को यहाँ उपस्थित रहने तथा दूसरे सदस्यों के विचार चुनने के लिए कहा गया है। इस कारण उन सदस्यों को बोलने की आज्ञा दी जायेगी जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

सेठ गोविन्ददास—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मेरी भावनाएँ हैं और जिन को मैं रोके रखता हूँ उनको व्यक्त करने का जो भी मौका मिलता है उसको मैं जाने नहीं देना चाहता। मैं केवल दो मिनट के अन्दर अन्दर ही खत्म कर दूँगा।

मैं महात्मा गांधी की जो राय थी वह बता रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि गोवध की योजना में यह तो आ ही जाता है कि तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी-होयों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिये।

अभी वित्तीवा जी ने भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में राय दे दी है।

क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, केवल इतना कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में राय दी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पशुधन से इस देश को दो हजार करोड़ रुपये की आय : होती है। तकरीबन २३ प्रतिशत की आय : होती है, पर पंचवर्षीय योजना जिस पर बीस अरब रुपया खर्च होगा उसमें केवल चार करोड़ रुपया यानी ५०० वा भाग उस काम के लिए रखा है। रेलें जो कि डार्ड करोड़ रुपये की आय : देती हैं उनके लिए ४०० करोड़ रखा गया है। १६० गोसदन खुलने चाहिये थे पर खोलें गए हैं केवल १७, इन सब बातों को देखते हुए मेरे सुझाव हैं कि सरकार पंचवर्षीय योजना में गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करे। चमड़े यादि के निर्यात को बन्द करे पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक अरब रुपया गोसम्बर्धन के लिए रखे। कृषि तथा जंगल विभाग ने जो भूमि अनुचित रूप में रोक ली है, उसे गोचर भूमि के लिए छोड़ दे। किसान तथा पशुधन को दृष्टि में रखते हुए अमरीका से आने वाले धी हो बन्द करे। वगस्पति धी को या तो रग दे या यदि वह सम्भव न हो तो उसका जसाया जाना बन्द करे।

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है। कि सेठ गोविन्ददास द्वारा १२ मार्च १९५४ को उपस्थित किए जाने वाले निम्न प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद स्थगित हो गया था उसे पुनः आरम्भ किया जाए—

“कि देश में दुधारु और वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जावे।”

जो पक्ष में है वे कृपा करके ‘हां’ कहेंगे।

कई सदस्यगण—“हां”

अध्यक्ष महोदय—जो विपक्ष में है वे कृपा करके ‘नहीं’ कहेंगे।

कई सदस्यगण—‘नहीं’

अध्यक्ष महोदय—‘हां’ वालों के अनुसार इस पर विचार होगा प्रस्ताव पास हुआ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—(मुद्रावध) अध्यक्ष महोदय, हमने एटोर्नी जनरल की राय १ पर की इस सदन में भुली...

कुछ माननीय सदस्य—अधिका से अधिक ।

पंडित ठाकुरदास जी भार्गव—यह एक राष्ट्रीय सवाल है और मैं मुताबिक यही समझता हूँ कि मैं इसमें से हट रहा हूँ ।

श्री एस. सी. सामन्त—(मुद्रावध) भुली का क्या है । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि यदि इस सदन में अध्यक्ष का अधिकार नहीं जो सदस्य पहले बोल चुके हैं क्या उसके भी अधिकार की आज्ञा होगी या नहीं ?

कुछ सदस्य—'नहीं'

अध्यक्ष महोदय—क्या मैं समझूँ प्रत्येक यह है कि क्या सदस्य को इस विषयक के बोलने का अधिकार भी है । क्या इस सदन में इस सदन की अधिकार है या नहीं । (तब सदन में) । यह सदनपूर्ण प्रश्न है इसका निर्णय करना होगा । अब निर्णय है यदि सदन पर तो बोलने के लिए अधिक कुछ नहीं है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—आप ने मेरे परम मित्र की सूचना ठीक नहीं है और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर अभी तक नहीं बोला अगर मैं बोला भी होता तो भी मैं जनताका चाहता हूँ कि स्वयं स्वीकार महोदय ने विद्युत् द्वारा बताया था कि एटोर्नी जनरल अब राय दें चुकेंगे उनके बाद सदस्यों को बोलने का समय दिया जायेगा कि वे भी अपनी राय दें ।

श्री एस. सी. सामन्त—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो सदस्य इस सदन पर पहले बोल चुके हैं उनका पुनः बोलने का आज्ञा होगी ?

अध्यक्ष महोदय—मान्य सदस्य कहता है कि वह इस विषय पर नहीं बोला ।

श्री एस. सी. सामन्त—मैं किसी कानून की ओर से निर्देश नहीं करता ।

श्री एन. सी. चैटरजी—संसद के अधिकार के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि पं० ठाकुरदास नहीं बोले ।

श्री सामन्त—वह बोल सकते हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो केवल जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय—एटार्नी जनरल ने अपना मत दे दिया है । जो सदस्य इस विषय पर नहीं बोले वह अपने विचार प्रगट कर सकते हैं । परन्तु जो इस पर हमारे सम्मुख इसके उपस्थित होने के पश्चात् बोल चुके हैं, उनको अब कोई अवसर नहीं दिया जायेगा ।

शिक्षा मंत्री के संसद् सचिव—डा० एम० एम० दास क्या हमें यह समझना चाहिये कि यह वर्तमान वाद-विवाद अटार्नी जनरल द्वारा दिये गये मत पर हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय—यह इस विषय पर है कि यह हमारे अधिकार में है अथवा नहीं ।

श्री नन्दलाल शर्मा—(सीकर) अन्यथा विधेयक तो वास्तव में पास हो चुका था ।

कुछ सदस्यगण—नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय—मैं बोलने वाले मान्य सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक सम्भव हो सके वे सक्षेप में बोलें ताकि अधिक सदस्यगण इस वादविवाद में भाग ले सकें ।

पं० ठाकुर दास भार्गव—अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा सवाल इस में यह है कि इस सदन की कम्पपैटेंस में यह बिल है या नहीं । मैं इस सम्बन्ध में बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सवाल तो इस से भी लम्बा-चौड़ा है लेकिन हमारे पास इस पर बोलने के लिये केवल एक ही घंटा है और मैं यह नहीं चाहता कि इस पर बोलते हुए एक घंटा मैं स्वयं ही लगा दूँ और दूसरे मੈम्बरों को बोलने का समय ही न मिले । यह ठीक न होगा इसलिये मैं जितना भी थोड़ा बोल सकूंगा

बोलूंगा। लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस हाऊस में साधारण नियम यह है कि जब कर्मा इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उस पर न चैंबर जिम्मेवारी लेती है और न कोई और। इनका निर्णय करने का तो इस हाऊस को ही अधिकार है। पहले यहाँ पर जब डा० अम्बेदकर महोदय ला मिनिस्टर थे और जब सेठजी का बिल आया उस समय उन्होंने ने अड़चन डाली कि यह इस सदन के अधिकार में नहीं है। उस समय मैं ने कहा था कि इस हाऊस को पूरा अधिकार है कि वह इस बिल को पास करें। उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि वह बतौर उपाध्यक्ष के इन की जिम्मेवारी नहीं लेंगे और सदस्यों को ही अधिकार होगा कि वे अपने आप ही इसका फैसला करें कि यह इस सदन के अधिकार में है या नहीं और यह निर्णय वोटों द्वारा किया जायगा। मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान में एक नियम है नम्बर १४३ जिस में सरकार को अधिकार है कि अगर वह चाहे तो किसी वैधानिक बान पर हमारी सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकती है।

पंडित ठाकुरदाम भार्गव—(जारी) तो वह धारा इस तरह पर है १४३ : १ यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी मुनवार्ट के पदवात् जैसा कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

मैं खुश होता यदि सरकार धारा १४३ के नीचे इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेज देती और उसका निर्णय हर आदमी पर आवश्यक होता। लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा। मैं उन बातों में नहीं जाता चाहता कि क्या सरकार ने उचित नहीं समझा।

सरकार ने केवल हमारे एटार्नी जनरल का मत मांगा और उनको यहाँ बुलवाया एटार्नी जनरल महोदय की कोई भी राय हमारी इज्जत के काविल है और मैं उस राय को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। लेकिन जहाँ मैं उसको इज्जत की निगाह से देखता हूँ वहाँ मैं यह भी जानता हूँ कि जहाँ तक कानून का सवाल है वहाँ एक वकील को दूसरे वकील की राय को इस निगाह से देखना होता है कि उसने जिन कारणों पर यह राय दी है। उस वकील की स्थिति (पोजीशन) ने उन्हें दबना नहीं चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यगण से प्रार्थना करूँगा कि वे इसी निगाह से इस राय को देखें और यह न सोचें कि यह राय किस ने दी है। हम लोग बड़े विश्वासी हैं और बहुत बार इस बात को देखते हैं कि कौन इसको कह रहा है। हमें केवल यह देखना चाहिये कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह कहाँ तक ठीक है। इसलिये हर मेम्बर इस वक्त उच्चतम न्यायालय की हैसियत रखता है यह देखने के लिये कि यह हाऊस इस कानून को पास करने के लिये योग्य है या नहीं।

अब मैं उन बातों पर आता हूँ जिनके कारण हमारे एटार्नी जनरल महोदय ने यह मत दिया है कि इस पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है। पहले तो मैं यह कहूँगा हमारे एटार्नी जनरल मुझे क्षमा करेंगे कि जो उनका दृष्टिकोण था इस सवाल की ओर मैं उसे ठीक नहीं समझता। हमारे विधान में तीन सूचियाँ बनी हैं, जिनमें दो राज्य सरकारें और विधान सम्बन्धी अधिकारों की सूचियाँ हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी सम्बन्धी सूची है। इसमें दृष्टिकोण यह है कि केन्द्रिय सरकार को हर एक चीज का अधिकार है, हर कानून को पास करने का अधिकार है। हमने जब इस विधान को बनाया था तो जानबूझ कर इसको एकात्मक बनाया था। उसमें हमने धारा २४८ रखी है जिसकी मनशा है कि जो चीजें इन तीनों सूची में नहीं हैं उनके लिए सारी शेष अधिकार केन्द्रिय सरकार को हैं। अगर हमको साफ तौर पर पता नहीं चलता कि कोई खास चीज इन सूचियों में है तो उसके लिये इस धारा के अनुसार केन्द्रिय

सरकार को ताकत दी गई है। इसलिये अब केवल एक ही सवाल है जो कि माननीय सदस्यगण को देखना चाहिये कि यह विषय राज्य की सूची में आता है या नहीं। यदि यह राज्य की सूची में नहीं आता तो फिर किसी और सूची में जाने की जरूरत नहीं है। सूची १ और ३ में केन्द्रिय सरकार को ताकत दी हुई है और विधान की धारा २४८ में उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। तो अब सीधा सवाल यह रह गया कि प्रायः यह सूची में आता है या नहीं। अब हमारे एटार्नी जनरल साहब सूची २ पर बहस कर रहे थे उन्होंने प्रविष्टि क्रमांक १५ का हवाला दिया था। लेकिन फिर शायद उनको ख्याल आया कि प्रविष्टि १५ साफ नहीं है। तो उन्होंने दो तीन और आइटम्स की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रविष्टियां ६, १४ और २७ का उल्लेख किया। उन धाराओं का हवाला देना ही यह सिद्ध करता है कि हमारे एटार्नी जनरल महोदय इन धारा में यह समझते थे कि यह मामला साफ तौर पर धारा १५ के मानहत नहीं आता है में धारा ६, १४ और २७ को अभी न लेकर केवल धारा १५ को लेता हू। धारा १५ में यह लिखा है—

“पशु के नमन का परिरक्षण, सरसाण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का जाली-हीत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।”

इसके बाद आप देखें कि दफा ६ में यह लिखा हुआ है—

“मार्बजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औपचालय”

मे नम्रता से कहूंगा कि इनका मार्बजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औपचालय में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो चिकित्सालय और औपचालय हैं इनका सम्बन्ध मनुष्यों से है। धारा ६ में कोई भी जिक्र पशुओं का नहीं है। यदि एटार्नी जनरल महोदय इसके सार को देखें तो इस धारा ६ का सम्बन्ध पशुओं से नहीं है।

इसी तरह से आप धारा १४ को देखें उसमें लिखा है—

“कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि, शिक्षा और गवेषणा, भरकों से रक्षा तथा उद्भित रोगों का निवारण भी है।

मैं नम्रता से कहूँगा कि यह कहना कि दफ्ता १४ को देखने से यह पता लगता है कि बिल यहां पर नहीं आ सकता है यह ठीक नहीं है। इसके अन्दर न तो गाय का जिक्र है और न किसी और जानवर का जिक्र है। यदि कहा जाये कि इसका सम्बन्ध गाय से इसलिए है कि कृषि में गाय काम में आती है तो मैं नम्रता से कहूँगा कि यह दलील बिल्कुल गलत होगी।

अब आप देखिये धारा २७ को। उसमें उन्होंने लिखा है—

“सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के आधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन सम्भरण और वितरण।”

इससे किसी जानवर का सम्बन्ध नहीं है।

अब आप लिस्ट ३ के आइटम ३३ को देखें। वह इस तरह पर है—

“जहां संसद से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और आणव्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण।”

मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह कहा जा सकता है कि यह जितने जानवर हैं यह गुड्स हैं क्योंकि पहली चीज धारा २७ में यह है कि—

वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण

यह गायें गुड्स नहीं हैं। मेरी तो अकल में नहीं आता कि इसका कोई सम्बन्ध कैसे गोहत्या के साथ हो सकता है। मुझे तो ऐसा नजर आता है कि जब उन्होंने यह देखा कि यह चीज धारा १५ में नहीं आती तो उन्होंने दूसरी धाराओं का उल्लेख किया है कि कहीं न कहीं तो यह आ ही जायगा। लेकिन उनके इस उल्लेख से ही जाहिर है कि धारा १५ में नहीं आता। इससे पहले कि मैं धारा १५ के ऊपर और कुछ कहूँ मैं

हाउस का ध्यान जो ममवर्ती विधियों की पूर्ण है, निम्न नम्बर २, उसके प्रविष्टि नम्बर १७ की तरफ विधाना जाता है। उसमें लिखा है—

कुरता से पशुओं का संरक्षण प्रारम्भिक और करवन्दी से एनीमल तो आप देखें कि धारा ६, १४ या २० (यदि विवेकी) मान्यता नहीं रखती। इनकी तुलना में समयवर्ती सूची की धारा १७ इसके अधिक मान्य है।

तो जहाँ तक धारा १५ का ध्यान है उसके प्रत्यक्ष तो यह माना नहीं है। इसमें यह है कि—

“पशु के नसल का परिचक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालीहोती प्रविधान और व्यवसाय।”

पशु का शब्द स्टाक के साथ प्रयोग नहीं होगा। जब किसी विधान की किसी धारा में एक शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वह हमारे शब्द से परिवर्तन नहीं होता। तो इसका परिणाम यही निकलेगा कि विधान सभा ने जान बूझकर उन शब्दों को विशेष अर्थ में प्रयोग किया है। इसीलिये उसमें लिखा है “इन्फ्रूवमेंट आफ स्टाक एंड प्रोवेंशन आफ एनीमल डिजीजेजे” यह नहीं लिखा है कि “इन्फ्रूवमेंट आफ एनीमल”। तो स्टाक के लिए एनीमल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि स्टाक में और पशु में अन्तर है। आगे धारा २० में दिया है, “प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड इन्डोमल्स एंड बर्ड्स (वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा) इसमें भी शब्द स्टाक नहीं दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि “एनीमल” और “स्टाक” में बड़ा अन्तर है। इसके पहले कि मैं इसके अर्थ शब्दकोश से आपको सेवा में उपस्थित करूँ आप विधान की धाराओं को देखने जहाँ से यह सारा जनाजा चला है। धारा ४८ को हमारे विधान में है वह इस तरह पर है—

“राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरो की नसल के परिचक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।”

यह दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग उन चीजों में सम्मिलित है जो नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के बारे में हैं, उनका दूसरा भाग गांधी बख्शे तथा अन्य दृष्टान्त और सामूहिक पशुओं की हत्या के बारे में है। यह दो अलग अलग चीजें हैं और एक दूसरे के समान नहीं हैं। नस्ल का परिरक्षण और विशेष पशुओं की हत्या एक ही चीज नहीं है। एक सामूहिक हस्त ने सम्भव रखना है कि नस्ल की रक्षा होगी, दूसरा एक विशेष वंश के सारे जानों में सम्भव रखता है। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपका ध्यान सार्वजनिक हत्या के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जिसने बड़े समय में यह धारा के अन्तर्गत को अनुरोध के रूप में माना। भारतीय संविधान के अन्तर्गत गवर्नर की व्याख्या दी हुई है धारा ४२८ और ४२९ के अन्तर्गत में बला कीसेवा में नास तीर पर कहना चाहता हूँ क्योंकि नया मना १९४८ जहाँ तक दफा १५ का मवाल है, यह धारा १५ के अन्तर्गत में भी नहीं है कि जिसकी रूप से यह विषय राज्य मंत्री का जो।

भारत दण्ड संहिता का परिच्छेद ४२५ ने इस प्रकार है—

"Whoever, with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public...."

यह शब्द सोचने के योग्य है।

"Whoever with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property.."

इसमें जनता शब्द के नीचे रेखा है और मेरा विश्वास है जैनाजी अभी सेठ गोविन्ददाम ने महात्मा जी के कुछ वाक्यों को उद्धृत किया

जहाँ तक गाय, बैलों और घोड़ों आदि का सवाल है, वह (पब्लिक इंटरेस्ट) भलाई में आ जाते हैं, भले ही वह किसी एक प्रादमी के प

हों, पर जनता को उनको हानि पहुंचने से या मारे जाने से हानि होती है। इसी प्रकार परिच्छेद ४२८ और ४२९ में लिखा है कि यदि कोई ऐसा काम करता है और उससे जनता को हानि पहुंचती है तो वह (मिसचिफ़) सरारत सिद्ध हो जाती है, जैसे कि दो आदमियों के पास एक घोड़ा है, तो यदि एक मनुष्य घोड़े को मार दे तो वह कानून के अनुसार अपराधी माना जाता है।

Section 428 says:—

“Whoever commits mischief by killing poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of ten rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine or with both.”

Section 429 says:—

“whoever commits mischief by killing poisoning, maiming or rendering useless any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine or with both.”

मेरा आदर पूर्वक निवेदन है कि यह कानून जो बना था तो इसका यह कारण था कि जहाँ तक इन पशुओं का प्रश्न है उन को यदि कोई मारेगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा। यह देश का सर्व माधारण कानून है और मैं आदर पूर्वक कहूँगा कि यदि कोई और अलग कानून न भी बने

तो भी यह साधारण कानून उसके अपराध को सिद्ध करने के लिये काफी है। इसके अतिरिक्त यदि आप समवर्ती सूची की प्रविष्टि १ या २ का निरीक्षण करें तो आप पायेंगे कि जहाँ तक दण्ड देने वाले विषयों का प्रश्न है वह दोनों के दोनों ऐसे हैं कि जो समवर्ती सूची में आते हैं:—

(१) “दण्ड विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत दण्ड संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बन्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा शसैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर।”

(२) “दण्ड प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हैं।”

मेरा आदर पूर्वक निवेदन है कि समवर्ती सूची तीसरी में अपराधों सम्बन्धी विधान के जो कि भारतीय दण्ड विधान में वर्णित हैं सारे विषय सम्मिलित हैं केवल उन अपराधों के अतिरिक्त जो कि सूची १ और २ में वर्णित हैं। इसी प्रकार प्रविष्टि १५ में जो पशु नसल का परिरक्षण, संरक्षण तथा उन्नति का वर्णन है वह विधान की धारा ४८ में सम्मिलित है—

“...और गाय, बछड़े, बछड़ियों और दुधार तथा भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध।”

पहले भाग में परिरक्षण और नसल की उन्नति का वर्णन और मेरा आदर पूर्वक यह कहना है कि प्रविष्टि १५ में जो दिया है वह धारा ४८ के पहले भाग में आ गया है। प्रविष्टि १५ में पशु परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति का वर्णन धारा ४८ में सम्मिलित है। जहाँ तक हत्या का सम्बन्ध है वह देश के सर्वसाधारण कानून और क्रिमिनल ला में आता है, उसका कोई सम्बन्ध प्रविष्टि १५ से नहीं है।

मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ और यह भी कहा जा सकता है

कि यदि हत्या को रखा जायेगा तो इससे उनका परिरक्षण होगा परन्तु आदर पूर्वक मेरा निवेदन है कि यह विचार गलत है। मेरा यह विश्वास है कि आप सारी पशु तथा वनस्पति जगत् को उन्नत करते हैं, उनका परिरक्षण और संरक्षण करते हैं तो क्या इस कारण से करते हैं कि आप उसको खा जायें, भक्षण कर जायें ? आप मुर्गी और भेड़ को पालते हैं तो क्या इसलिये कि उसको मार डालेंगे ? हत्या करना अलग वस्तु है और परिरक्षण विन्कुल अलग। बहुत बार वन्तुओं का परिरक्षण इसलिये किया जाता है कि हम उनको मार डालेंगे। उदाहरण के लिये एक मुर्गी खाने में पचासों मुर्गे और मुर्गीयाँ और किसी को उनसे कोई हृतछात का रोग लग जाता है और कई रूपों में उनको मार दिया जाता है तो सारे मुर्गीखाने के हित में उस मुर्ग या मुर्गी को अन्य सबसे अलग कर दिया जाता है और कई बार उन्हें मार भी डाला जाता है। इसलिये हत्या के लिये परिरक्षण हो नकता है यह दोनों विन्कुल भिन्न-भिन्न वस्तुयें हैं। यह दोनों इन प्रकार सम्मिलित नहीं हैं कि जहाँ परिरक्षण का वर्णन हो, वहाँ हत्या आवश्यक ही आयेगी। मेरा आदर पूर्वक निवेदन यह है कि इस दृष्टिकोण से इसमें यह शब्द लिखे हुये नहीं हैं।

प्रविष्टि १५ में केवल पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति, यह शब्द है इसमें हत्या का शब्द नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने तीसरी धारा और रख दी में सादर निवेदन करता हूँ कि इस कानून का कदापि यह अर्थ नहीं कि चार पशुओं को बचा लिया जाये। इसका वास्तव में अर्थ जैसा कि सेठ जी ने बतलाया है कि इस देश में जो भ्रम है वह हट जायें। हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू विश्व भर में शान्ति का डिडिम पीटते हैं और वह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारे विश्व में शान्ति हो। महात्मा गांधी, श्री किदवाई और श्री मुन्शी ने बार बार बतलाया है और सदन में दिये गये उनके भाषणों में यह आया कि इस कार्य का उत्तरदायित्व हर एक सरकार पर है महात्मा जी

और किन्दाई साहब ने कहा कि यह कार्य हमें जानबूझ परिवार का श्रेण
 समझ कर करना चाहिये और जिम्मेदार लोग ही उन पशुओं को बचा
 सकते हैं और उनका परिचर्या कर सकते हैं। जितने ही सरकारी
 अधिकारी ऐसे हैं जो उसमें विश्वास नहीं करते कि अनुपयोगी पशु को
 रखा जाये, मैं समझता हूँ स्वयं मन्त्री महोदय भी उन ही विचारों के
 होंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया मैं उसकी प्रशंसा करता
 हूँ। उन्होंने इतना स्पष्ट वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हम धारा ४८
 के अनुसार कार्य करने के लिये बंधे हुये हैं और यह हमारी विधानिक
 सरकार है। चाहे कोई मन्त्री मानें या न माने अहा तक गो का प्रश्न है
 धारा ४८ अग्निम वस्तु है और गाँवों की रक्षा की आवेगी। योजना
 आयोग ने गोसदन के लिये चार करोड़ रुपया दिया है। उन्होंने कभी यह
 नहीं कहा कि हम इनको बन्द कर देंगे। सरकार उस नीति पर निर्भर है,
 हमारी सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की हुई है,
 अब चाहे उसके कोई मन्त्री महोदय उसमें विश्वास रखें या न रखें
 क्योंकि इस विषय में दो मत हो सकते हैं और जो लोग इस बारे में
 प्रतिकूल मत रखते हैं वह मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने कि वह लोग जो
 इसके अनुकूल मत रखते हैं। यह उचित नहीं होगा कि सदन में इस
 वस्तु को देखा जाये कि १५ प्रविष्टि को लिख देने में हत्या सम्मिलित
 होगई। मैं आदर पूर्वक कहूँगा कि इस प्रकार यह प्रश्न नहीं नुल्लभ
 सकता। मैं यह भी कहूँगा कि एक विधेयक को देखने का वह ठीक उंग
 नहीं है कि आप उसकी दो-तीन पंक्तियों को देखें। आप इनके उद्देश्य
 और तर्क की देखें, उस पूरे विधेयक के सार को देखें तो आप पायेंगे कि
 उसका सार यही है कि पशु मारे जायेंगे तो अपराधी को दण्ड मिलेगा,
 उनके मस्तिष्क में शायद इतना ही हो। सेठ जी चाहते तो बहुत अधिक
 थे, दो घण्टे बोले और ऐसी बातें कहीं जो हम लोगों के ज्ञान में नहीं
 थीं। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन में चाहे जितने तर्क दिये

जायें भिन्न-भिन्न तर्क हो सकते हैं, पर इसका सार है उसकी हत्या, या ज स्टाक से किसी पशु का अर्थ निकाला जाये तो यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां स्टाक का जो शब्द है उसके अर्थ ऐनिमल (पशु) नहीं हैं, नाय नहीं हैं, बैल नहीं हैं। स्टाक ऐसी वस्तु है जिस के कोई भी अर्थ निकल सकते हैं, मनुष्य को भी स्टाक कहते हैं, लकड़ी को भी स्टाक कहते हैं, मुर्गीखाने को भी स्टाक कहते हैं, ग्वाध को भी स्टाक कहते हैं। मैंने दो शब्द-कोष देखे और उन में स्टाक शब्द के पचासों अर्थ हैं। यदि कहीं कोई व्यक्ति कहता है कि स्टाक के स्थान पर कोई शब्द निश्चित कर दो तो मैं मानता, पर यहाँ स्टाक के अर्थ ही मेरी समझ में नहीं आते कि क्या है। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्टाक के अर्थ ऐनिमल नहीं हैं, स्टाक में एक ऐनिमल नहीं है, यदि स्टाक के कोई अर्थ हैं तो वह उन नसल के हैं और उन नसल को बचाने के लिये ऐसा कहा जा सकता है जहां अंग्रेजी में स्टाक का शब्द है, वहां हिन्दी भाषा के विधान की प्रविष्टि १५ में उस का कितना ठीक अनुवाद किया है। देखिये उन्होंने कैसे स्टाक के अर्थ समझे—

‘पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उत्पत्ति तथा पशुओं के रोगों का निवारण’ मैं कहूंगा कि स्टाक के अर्थ यदि नमल के हो तो राज्य की जिम्मेवारी है कि नसल को ठीक रखे। अच्छी नसल के लिये केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। कि किसी पशु को मारा न जाये। परिरक्षण के क्या अर्थ हैं ? कि ठीक में रखा जाये। भेड़ों का परिरक्षण होता तो उस के यह अर्थ होने कि भेड़ को न केवल बचाया जाये बल्कि ठीक भी किया जाये। मुर्गियों के परिरक्षण के अर्थ यह है कि मुर्गियों को उत्तत किया जाये। यदि अंडा छोटा होता है तो उस को ऐसा किया जाये कि वह बड़ा होने लगे। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर स्टाक के अर्थ कदापि ऐनिमल के नहीं लिये जा सकते क्योंकि मेरे पास इस समय दो शब्द कोष हैं। अब समय नहीं, अन्यथा आप को पढ़ कर सुनाता यदि आप वैस्टर या ग्रामफोर्ड शब्द कोषों में जोकि इस समय

मेरे पास है, स्टार्क के प्रर्थ देने को नहीं कर जाते। नामक शब्द का एक ऐसा शब्द प्रयोग में आता गया है जिसे के प्रर्थ है पशु में नहीं आते। हिन्दी में उसके ठीक प्रर्थ लगाये गये। जैसा कि पुरा एक दिन पूर्व कहा कहा था कि हम ने संविधान में हरजाना जो नष्ट हुआ था। परिणाम यह हुआ कि हमें उस जो बदलना पड़ा क्योंकि उस के प्रर्थ ठीक नहीं थे। उसी प्रकार यद्यपि स्टार्क का शब्द पुराना आता। परन्तु के काल से प्रयोग में चलना ने चला आता था परन्तु जो अब स्टार्क के प्रर्थ नसल के किये गये। इसी लिये उस शब्द के प्रर्थ से जान लिये गये। उस का एक भाग जिस का सम्बन्ध राजा से था उस का भाग १८ में राज्य के आधीन रखा गया और दूसरा भाग जो न उस से सम्बन्धित प्रकार के आधीन रखा गया।

श्रीमान् जी, शायद यह कहा जाये कि क्या यह बात उचित होगी या नहीं, पर कानून के अन्दर हम ऐसी कोई वस्तु नहीं देना चाहते। हम किसी के भाषणों को नहीं देस सकते, कोई वस्तु नहीं देस सकते, केवल शब्दों के अतिरिक्त इन शब्दों के जो प्रर्थ निकलें वही हम को देना है। सारी विधान परिषद की मदों को जो उस ने धारा ३१ में बनाया था, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अम्पीकार कर दिया और वह ठीक हो लिया और जो शब्दों के प्रर्थ निकलते थे उन को ले लिया। इसी प्रकार वहाँ पर जो शब्द है "पशु की नसल" के प्रर्थ जिनसे से है, एक पशु से नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि प्रविष्टि १५ में जो स्टार्क शब्द आया है उस के प्रर्थ हत्या से कभी नहीं है। उस के प्रर्थ रखने से होते हैं। हत्या और रखने में बड़ा अन्तर है। दोनों समानार्थक नहीं हैं। इस लिये जहाँ तक संविधान का प्रश्न है हमें पूरा अधिकार है और अब मैं इसी धारणा के अनुसार बोलूंगा क्योंकि हमारे अधिकार तो पूर्ण हैं और हमारे अधिकारों में से यह अधिकार निकाल कर राज्य को दिये गये हैं। इसलिये धारणा यह है कि सदन को पूरे अधिकार हैं और यह सदन इस सम्बन्ध में पूर्णतया योग्य है।

श्रीमान् जी, मैं इस प्रश्न पर जो कुछ लिखना चाहता था वह कह चुका। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं विधेयक के प्रीतिरूप पर और थोड़ा सा निवेदन कर दूँ।

अध्यक्ष महोदय—वह विचार १४२ पर समाप्त हो जायगा।

पं० ठाकुरदास भार्गव—मैं नवन या समय लेना नहीं चाहता।

सेठ गोविन्ददास—सभापति जी, अगर इस हाऊस की यह राय है कि इस के लिये और समय दिया जाय तो क्या आप बड़ा नहीं सकते ?

सभापति महोदय—यह जो हाऊस की बात है।

श्री एन. सी. चैटरजी—(उत्तर) मैं यह हुआब रखता हूँ कि आज हम साढ़े पाँच बजे तक बैठें और इन विवाद को समाप्त कर दें, क्योंकि हम लोगों को कुछ कहना है और फिर बहुतों जनरल महोदय कुछ कहेंगे।

पं० ठाकुरदास भार्गव—सदन को यह पूरा अधिकार है कि वह समय बढ़ाये। मेरा निवेदन है कि आज इस प्रश्न पर वाद विवाद कर लिया जाये, अन्य जो प्रश्न हैं उन पर फिर वाद विवाद हो सकता है। पर शायद सदन ऐसा कर नहीं सक्ता क्योंकि अध्यक्ष महोदय का रुतिग है कि अधिकार रखने के प्रश्न का निर्णय सदन इस समय नहीं करेगा। इस का निर्णय इस समय होगा जब विधेयक फिर उपस्थित किया जायेगा और वह भी तब होगा जब सदन इस के विचार करने को पास कर देगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कि सदन के सन्मुख इस पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित हो। इसलिए मेरे लिये और कोई मार्ग नहीं रह जाता, इसके अतिरिक्त कि मैं आप की आज्ञा से कुछ शब्द अभी कह दूँ।

अध्यक्ष महोदय—मेरा विचार है कि यदि हम एक बार विधेयक की उपयोगिता में प्रवेश कर गये प्रत्येक विधेयक की धाराओं में तो यह समाप्त न होगा और समय थोड़ा है, यदि हम सदन की बैठक का समय

आधा घंटा और भी बढ़ा द तो भी ऐसे सदस्यों की बहुत संख्या है जो अपने नाम पहले ही भेज चुके हैं।

पं० ठाकुरदास भार्गव—मैं सदन और मान्य सदस्यों के मार्ग में बाधा बनना नहीं चाहता वह जो चाहें सो कहें परन्तु कृपा करके मुझे कुछ क्षण बोलने की ओर आज्ञा दे ताकि मैं विवेक के औचित्य पर बोल सकूँ। उसके पश्चात् आप निर्णय करें कि सदन की बैठक साढ़े पाँच बजे तक चलती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय—यदि सदन यह तर्क उपस्थित करता परन्तु उस के लिये यह आवश्यक है।

श्री एन, सी, चैटरजी—इस वैधानिक विषय को समाप्त कर देना काफी नहीं होगा। यदि हम साढ़े पाँच बजे तक बैठें तभी हम इस वैधानिक विषय के साथ न्याय कर सकेंगे।

श्री बी, जी, देशपांडे—दूसरे विषयों पर विचार किया जा चुका है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—मैं पूर्णतया आपके आधीन हूँ यदि मुझे बोलने की आज्ञा दें तो बोलूँगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि वाद में मुझे कुछ बोलने के लिए समय दिया जाए। जब वैधानिक विवाद समाप्त हो जायेगा तो मैं आपसे कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय—यदि विचार सम्बन्धी प्रस्ताव पास होगया तो।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—जहाँ तक विचार सम्बन्धी प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुझे आगे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है ? यदि आप मुझे ५ मिनट और दें.....

अध्यक्ष महोदय—समय थोड़ा है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—मैं औचित्य पर भी ५ मिनट से अधिक समय नहीं लूँगा। श्रीमान् जी, जहाँ तक इसके औचित्य का

प्रस्त है मुझे बड़े खेद के साथ कहना है कि वह प्रश्न बार-बार सदन के सम्मुख आता है और हमारी सरकार ने उन विधेयक पर जितना ध्यान देना था उतना नहीं दिया। जिस समय डा० राजेन्द्रप्रसाद कृषि मन्त्री थे उस समय उन्होंने इस के लिए कुछ धन खर्च इन बनलाया था। इस प्रश्न को सुनभराने के लिए उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की थी जिस ने १९४८-४९ में अपनी रिपोर्ट उतारि। कर ना। उनके मुताबिकों को भारत सरकार और श्री जवरानदास दोहनवाल ने स्वीकार किया। इस के पक्षान यदि सरकार चाहती तो इस विषय पर ठीक प्रकार सुदृष्टा सकती थी। देश में जो अनुयोगी पशु है उनका संभाल सरकार के अनुसार इन पशुओं से अधिक नहीं है। वहाँ प्रस्ताव की गई है कि हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने इस विषय पर पकड़ारी से अवलोक किया और सदन ने माना कि सरकार उन अनुसार काम कर रही है। जहाँ में सरकार की प्रशंसा कर रहा है कि वह हर प्रकार पशु सुधार के लिए धन व्यय कर रही है और हमारे कृषि मन्त्रियों ने सरकार के हर कार्य को न्यायोचित ठहराया है। पर एक बात पर मैं उनमें सहमत नहीं हूँ। मैं उनका ध्यान उस पशु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि प्रायः लोग करते हैं और जिस कारण से इस विषय के पक्ष में नहीं हैं। वह भूय वह है कि वह गणनाते हैं कि इस देश में १० प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक पशु अनुयोगी है। मेरे मानः दोपट्टे हैं। मगर नहीं, अन्यथा मैं कहकर सुनाता, प्रत्येक जगह उनका पद होगा। इस सरकार के मतानुसार देश लाखों से अधिक अनुयोगी पशु इस देश में नहीं हैं। मन्त्र जो पशु है जो दूध आदि नहीं देते या जो बाधों में बाध मेर दूध देते थे, वह आज चार गेर दूध देते हैं। मैं इस विषय में अधिक जाना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है। पर यह अत्यन्त कहना चाहता हूँ कि इन पशुओं से उत्पादन आज पहिले से अधिक बढ़ गया है। १०, १२ वर्ष पूर्व डा० राजेन्द्रप्रसाद हिमालय पक्षों में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि १२ वर्ष के भीतर-भीतर सारे अनुयोगी पशु अपने पाप समाप्त हो जायेंगे।

चाहे उन्हें भारो या न भारो । समस्या यह थी कि इन अनुपयोगी पशुओं का क्या किया जाए । आज भी यह समस्या सुलभ सकती है पर उसका ढंग उनको मारना नहीं है । सबसे अच्छा ढंग यह है कि ऐसे सांडों को बधिया कर दिया जाए ताकि वह ग्रौर पशु उत्पन्न करने के योग्य ही न रह सके । उनके उत्पादन को ठीक करने का केवल यही एक साधन है जिससे कुछ लाभ हो सकता है । जिस प्रकार डा० देशमुख ने चावल के विषय में इतना प्रयत्न करके सारे देश को विनाश से बचाया है और अपने कर्तव्य को पूरा किया है, उसी प्रकार मुझे कोई सन्देह नहीं कि वह इस समस्या को भी सुलभा देगे । यह विषय तो पहले ही ठीक हो गया होता पर हमारी सरकार को गत वर्षों में बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है । बहुत-सी समस्याएँ खड़ी हो गई । पुनर्वास समस्या, खाद्य समस्या आदि से ही इतने दिनों तक आवकाश नहीं मिला, फिर भी आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि चार करोड़ रुपया योजना आयोग ने नसलों के सुधार के लिए दिया । उसमें से २० लाख रुपया खर्च किया किया गया । दो करोड़ रुपया उत्तरे गोसदनों के लिए दिया था इसमें से पांच लाख खर्च किया गया । १०० करोड़ रुपये से अधिक हमारी सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर लगा दिया पर हमारी गायों की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया गया । कई व्यक्तियों को गायों के नाम से ही चिढ़ है । गायों का नाम सुना और नाक भौं सिकोड़ने लगे । मैं गाय की पूजा नहीं करता । जब मैंने इस विषय को संविधान की धारा ४८ में उपस्थित किया था, मैं इस धारा के अस्तित्व में आने के लिए उत्तरदायी हूँ । उस समय मैंने कहा था कि मैं इस विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से उपस्थित करता हूँ और यदि मेरा मत सुना जायेगा तो वेदों से लेकर आज तक इस देश में यह नियम रहा कि गाय मारने योग्य पशु नहीं । मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ उन व्यक्तियों की बात जो कल जाकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते थे कि गोहत्या बन्द होनी चाहिए और आज वही कहते हैं कि बिना गाय को सारे काम नहीं

चलेगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको यह आशा है कि सरकार की नीति हमारे मन के अनुसार होगी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार की नीति मेरे कथनानुसार है। डा० पंजाबराय देवगुन का भी विचार मेरे मन के अनुसार है और वह संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार का कार्य और वक्तव्य भी उनके अनुसार है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, हम सब चाहते हैं कि इस देश का लाभ हो और इस विषय पर एकमत प्राप्त होगा चाहिए। मैं इस समय इस समस्या के आर्थिक कारकों की ओर जानना नहीं चाहता कि कैसे रई करोड़ का आय हमारे गोवंश में हुआ है। सभी इसे जानते हैं और इससे सहमत हैं। यदि देश का एक-दोस्रो निदान हो जायेगा तो इसमें हमारा उत्तादन और भाग्य भगता है और हमारा लाभ हो सकता है। मैं कहूँगा कि आहू आय तिर्ग भी इष्टिकोण से देखें इसका निदान बड़ा सरल है, पर यह हो तब जानना है जब सरकार ध्यान दे। सात वर्षों तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि सेठजी और डा० पंजाबराय देवगुन से कोई अन्तर नहीं है। दोनों मध्यप्रदेश के ही रहने वाले हैं और दोनों ही का मार्ग एक है। सेठजी केवल इतना कहते हैं कि जो किन्मा जा रहा है उसमें केवल कानून की सहायता और दे दी जाये अन्य कार्य तो सरकार भी कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को पूरी शक्ति प्राप्त है इसके करने के लिए और उसे यह कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि भारत में जनतन्त्र के कुछ अर्थ हैं, यदि स्वर्गायि निद्वार्ड के प्रति हमारा कोई भी कर्तव्य है तो भारत के जनतन्त्र की भाव है और प्रति भारत के २६ प्रतिशत लोगों की भाव को सरकार अवस्थाकार करना नहीं चाहती है। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या देखा जहाँ से कि हमारे श्री पन्त जी पधारें हैं कि वहाँ पर एक कमेटी बैठाई गई, उसकी रिपोर्ट है।

सेठ गोविन्ददास—उसमें तीन मुख्यमान भी थे।

त यह देखना होगा कि स्वतन्त्र भारत में गोहत्या बन्द होती है और वह भी अतिशीघ्र ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई गोसन्वर्धन जांच कमेटी का उल्लेख भी किया गया है । डा० सीताराम उसके अध्यक्ष थे । नयाब छतारी, श्री महमद सैयदखां तथा अन्य कई लोग उसके सदस्य थे । उन्होंने ने यह रिपोर्ट एक मत होकर तैयार की है और यह रिपोर्ट क्या है ? उनका मत है—

“इस बात के अतिरिक्त कि राज्य की जनता की भावनाये वड़े उग्ररूप में प्रायः धार्मिक है । देश के अर्थ, स्वास्थ्य तथा परस्पर प्रेम के दृष्टिकोण से भी गौ और गीर्वाण की रक्षा का काम आवश्यक है ।”

आगे उन्होंने लिखा है—

“ध्वर उधर हाने की या प्रश्न को टाटने की नीति नहीं होनी चाहिए और गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ।

मेरी मांग है कि यह सारे राष्ट्र और देश से सन्बन्धित समस्या है, किसी एक राज्य की नहीं । इस संसद को यह साहस से अपनाना चाहिए और जिस प्रकार सीताराम कमेटी ने कहा कि राष्ट्र की जनता के आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य और परस्पर प्रेम के हित में गोहत्या पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दे । यह प्रश्न कोई क्षेत्रीय या ग्रामीण नहीं है । यह अखिल भारतीय समस्या है और इस पर इस संसद को समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते विचार करना चाहिये ।

जहां तक विद्वान् अटार्नी जनरल द्वारा उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, उन द्वारा कही गई हर बात को सर्वोच्च मान मिलना चाहिये । जो कुछ उन्होंने कहा है वह मैंने ध्यान से सुना है । उनका पक्ष क्या है ? उसका कहना है कि हमारे विधान निर्माताओं ने जान बूझ कर तीन सूची बनाई हैं । प्रथम, द्वितीय और तृतीय । आप जानते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया या अमरीका की पद्धति को नहीं अपनाया । जिस प्रकार वहां पर अवशिष्ट विधानशक्तियों का नियम बना है । जो सीधे रूप में

संघ से सम्बन्धित नहीं, यहाँ ऐसा नियम नहीं है। हमने तीन सूची बनाई है। प्रथम सूची सम्पूर्ण संघ और दूसरी राज्य विधान सभाओं के संबंध में और तीसरी सम्बन्धी सूची है। यहाँ हमने कुछ विधायी पद्धति को अपनाया है और भारत की संसद की जो प्रचलित विधान नितियाँ प्रदान की हैं। साथ जानते हैं कि जहाँ संसद के पास २४३ वर्ग। भारत के विधान पर आलोचना करते हुए जो कुछ मैं कहूँ—

“कैनेडियन पद्धति के अनुसार प्रचलित विधान नितियों की राज्य के स्थान पर संघ की गोपनीय के पीछे चलाने में कुछ उन्नति है। जब विधान निर्मात्री सभा की पद्धति पढ़ने पढ़ने के बाद ही तो उनके सदस्य समीक्षा पद्धति में उन्नत होकर आगे जायें। यहाँ यह दिखन बनाया जाइते थे कि प्रचलित नितियाँ संसद की नीति पर राज्यों का अपना विधान सभाओं का पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करें। तत्परन्तु अब विधान निर्मात्री सभा की १४ अप्रैल १९४७ के अधिनियम के अन्तर्गत नया मन्त्रालय में बैठकर हुई तब तब भारत का विधानसभा में चुना जा और अपनी ही सीमाओं में कुछ विदेशी राज्य के निर्माण हो जाने में सुरक्षा का प्रदान अधिक जटिल हो गया। उस कारण ने यह नितियाँ केन्द्र सरकार का निर्माण आवश्यक हो गया और यह सभी सम्भव हो जाता था कि केन्द्र को अधिक से अधिक नितियाँ और उनके साथ प्रचलित नितियाँ प्रदान की जायें।”

इस कारण से हमने कुछ नितियाँ संसद को नहीं हैं और इस प्रकार कुछ राज्यों को। हमारे पास एक सम्बन्धी क्षेत्र भी है जहाँ दोनों काम कर सकते हैं केन्द्र और राज्य। हमने केन्द्र के विधान की पद्धति अपनाई है और समीक्षा की नहीं। हमने बहुत प्रचलित नितियाँ इस संसद को सौंपी हैं इस कारण यह संसद नितोच्च और सर्वोच्च सम्पन्न है।

मैं विद्वान् अग्रणी जनरल के पास इस बात पर सहमत हूँ कि प्रथम सूची अर्थात् संघ की सूची में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इस प्रकार की

विधि के लिये कोई स्थान हो। मैं इस बात पर भी उनसे सहमत हूँ कि तीसरी समवर्ती सूची में भी जिसके साथ इस विषय का सम्बन्ध है कुछ नहीं। प्रश्न केवल यह है क्या वह ठीक है? क्या वह इस बात में ठीक है कि इस विधि को राज्य विधान सभा के अधिकार में बतलाते हैं? मैं उनसे इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये कहूँगा। उन्होंने तीन या चार प्रविष्टियों ६, १४, १५ और २७ का उल्लेख किया है। एक प्रसिद्ध और अनुभवी वकील के लिये इतने अधिक प्रमाण उपस्थित करना ही उसकी निर्वलता का स्पष्ट उदाहरण है। अब प्रविष्टि ६ को देखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और आपथालय। यह कोई भी सो मील की दूरी पर है। यह गोहत्या निरोध का विधेयक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक से कोई सो मील की दूरी पर है। प्रविष्टि १५ "पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालीहोधी प्रशिक्षण और व्यवसाय यह उसके सबसे अधिक समीप है। पर क्या यह वास्तव में उसके क्षेत्र में आती है अब प्रविष्टि १४ देखिये—“कृषि, जिम में अन्तर्गत कृषि शिक्षा और मवेपणा, भरकों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है।”

अपने विद्वान् और मान्य मित्र के प्रति अति आदर भाव रखते हुये मेरा विचार है कि यह उसके क्षेत्र में नहीं आती और न ही प्रविष्टि २७ से सम्बन्ध स्थापित होता है, जो इस प्रकार है—सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

उसके प्रति महान् आदर भाव रखते हुये कि इसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई प्रविष्टि ऐसी है जिस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है वह प्रविष्टि १५, “पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति में अपने मान्य साथियों के विचार के लिये मैं यह कहूँगा कि यह विधेयक पशु उन्नति का विधेयक नहीं है। इसका वास्तविक

उद्देश्य पूर्णतया भिन्न है। मेरे मान्य मित्र पं० ठाकुरदास जी भार्गव आपके सन्मुख "स्टाक" और अन्य वस्तुओं की व्याख्या कर रहे थे। परिरक्षण (प्रिजरवेशन) यदि आप शब्द-कोश में देखें तो इसका अर्थ है नाश से बचाना। आप एक विशेष नसल के पशु की रक्षा करते हैं कभी कभी उस विशेष नसल के पशु के किसी भाग को सदैव के विनाश से बचाने के लिये मारना भी पड़ता है। परन्तु सेठ गोविन्ददास की यह भावना नहीं है। पं० ठाकुरदास भार्गव जब रक्षा के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। मुझे वेद है कि उनकी प्रशंसा नहीं की गई। उस समय उन्होंने अन्न और मुर्गी की रक्षा का भी उल्लेख किया था। अन्न किस लिये सुरक्षित रखते हैं आप मुर्गी को अपने प्रयोग में लाने के लिये सुरक्षित रखते हैं। इसलिये आपको वास्तविक उद्देश्य को देखना होगा। अटार्नी जनरल महोदय उनके प्रति सन्मान प्रदर्शित करते हुये, इस बात के कहने में पूर्णतया सत्य हैं। कि जब दोनों विधान सभाओं में प्रतिस्पर्धा या विवाद का निपट उपस्थित हो तो आपको वास्तविक सार को देखने के नियम को अपनाना पड़ेगा। यह वास्तविक सार का क्या सिद्धान्त है? यह सार देखने का नियम प्रीवी काँसिल द्वारा एक महान् आयरिश मुकदमा में इस प्रकार स्थापित किया है:—

“यह बात भली-भाँति स्थापित हो चुकी है कि आपको विधि के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिये अर्थात् विधि के सार तत्व को, यदि विधान की दृष्टि के अनुसार आपको यह पता लगे कि विधि का सार सीधी शक्ति के अधीन है तब यह अवैधानिक नहीं, यदि अकस्मात् ही इसका असर केवल उन ही विषयों पर पड़ सकता है जो अधिकृत क्षेत्रों से बाहिर है।”

विधि का वास्तविक स्वरूप क्या है? विधि का वास्तविक स्वरूप यह है कि कल से किसी भी गौ या गोवंश का मारना बन्द हो जायगा जैसा कि गोसम्बर्धन जाँच कमेटी ने कहा है। यह परिरक्षण या उन्नति

नहीं यदि आप घारा ४८ को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप में इन शब्दों का उल्लेख है—

“...राज्य विशेषतया तसलों के परिचर और गोधनधन के साधन अपनायेगा.....”

अध्यक्ष महोदय (श्री वर्मन)—शान्त, शान्त इस के लिये निश्चित समय समाप्त हो चुका तो क्या सदन इसे चालू रखना चाहता है ?

कुछ सदस्य—हां, हां ।

अध्यक्ष महोदय—तो किसी को एक विधि की पूर्ति के लिये प्रस्ताव उपस्थित करना होगा ।

श्री भुलन सिन्हा—खड़े हो गये ।

विदेश तथा प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)—मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि आप देर तक बैठने का निर्णय करें परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि आप ५ वजे के बाद बैठने को कोई निर्णय न किया जावे ।

मन्त्री महोदय (श्री सत्यनारायण सिन्हा)—इसके अनुसार समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री एन० सी० चेंटरजी—क्या मैं इसे एक या दो मिनट में समाप्त कर दूं ।

अध्यक्ष महोदय—चार घण्टे का समय जो इसके लिये निश्चित था समाप्त हो चुका है अब समय बढ़ाने का प्रस्ताव आना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—१५ मिनट का समय बढ़ा देना चाहिये । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है । मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

“विधेयक पर विचार करने के लिये जो समय निश्चित किया गया था उसे १५ मिनट और बढ़ा दिया जाये अर्थात् ५ वजे तक कर दिया जाये ।”

श्री भुलन सिन्हा—मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ ।

“इस विधेयक पर अधिक विचार करने के लिये और समय जो एक घण्टा से अधिक न हो और दिया जाये।”

अध्यक्ष महोदय—प्रधान मन्त्री ने पहले ही प्रस्ताव उपस्थित कर दिया है।

प्रश्न यह है:—

“कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये जो समय निश्चित किया गया था उसे १५ मिनट और बढ़ा दिया जाये अर्थात् ५ बजे तक कर दिया जाये।”

प्रस्ताव पास हो गया।

श्री एन. सी. चेंटरजी—मे समाप्त करता हूँ ? यदि आप कृपा करके धारा ४८ को देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें तीन बातें हैं, नस्लों का परिरक्षण और गोहत्या निषेध और बछड़े, बछड़ियों तथा दुधार पशुओं का बध वन्द करना अब यदि आप सप्तम अनुमूर्ची की वैधानिक पद को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ केवल पशुओं की नस्ल का परिरक्षण के शब्दों को प्रयोग किया गया है। परन्तु वहाँ पर “गोहत्या निषेध” के शब्द नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि ज्ञान-वृद्ध कर ही ऐसा लिखा गया है। जब आपको किसी विषय की एक विशेष धारा का पता लग जाये और उसमें एक या दो बातों का उल्लेख हो और तीसरी बात छोड़ दी गई हो तो मेरा विचार है कि इसकी व्याख्या करने का प्रमुख नियम यह है कि वैधानिक मद में यह बातें ज्ञान-वृद्धकर छोड़ दी गई हैं क्योंकि इसको संसद के सर्वोच्च अधिकारों पर छोड़ दिया गया था और यह हमारी परिधि में है। इसलिये मेरा विचार है कि यह धारा २४८ के अनुसार है और संसद को इस सन्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। यह विधेयक संसद के अधिकारों के बाहिर नहीं बल्कि उसके अधिकारों में ही है।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं यह बात प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक के पूर्णतया विरुद्ध है।

एक सदस्य—क्यों ?

श्री जवाहरलाल नेहरू—और मैं इस सदन से कहूंगा कि वह इसे पूर्णतया अस्वीकार करदे। यह मैं तीन सिद्धान्तों के आधार पर कहता हूँ। इनमें से एक यह है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे विधि परामर्शदाता का कहना है कि यह विधेयक संसद् के अधिकार में नहीं है। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उन्होंने इस वैधानिक मत को चुनौती दी है। मैं वैधानिक आवश्यकताओं में जाना नहीं चाहता। इस विषय पर सरकार अपने विधि परामर्शदाता के मत का पालन करे, काफी है।

इसके प्रतिरिक्त विधेयक के औचित्य का प्रश्न है। मेरा विचार है कि इस विधेयक को जो प्रयोजन है वह वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहेगा। यह हम में से बहुत-सों को अच्छा लगेगा। बहुत-सों को केवल भावनावश अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि हम सब देश के पशुधन की रक्षा चाहते हैं। हम सब इस बल की गिरती हुई दशा को देखकर चिन्तित हैं यदि धर्म और भावना आदि का प्रश्न छोड़ दिया जाये तो आर्थिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी इस बल का परिरक्षण और सम्बर्धन आवश्यक है। चिन्ता संख्या की नहीं, संख्या तो है पर उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उसे रोकना है। मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसे साधन अपनाये गये हैं जिन का अच्छा परिणाम निकला है और भी उपयोगी साधन अपनाये जायेंगे। परन्तु इस प्रश्न के सम्बन्ध में दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए अन्यथा हमारे सम्मुख ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी जिनके कारण हम गोरक्षा की अपनी आशाएँ आकांक्षाएँ और इच्छाओं को पूर्ण करने से वंचित होकर उनका बुरा ही करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल इस विधेयक को पास कर देने से ही हम लोग देश के पशुओं की रक्षा नहीं कर सकते। आपको वास्तव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि आज पशु पहिले से अधिक दुर्दशा में

फंसे हुए हैं। विधेयक मृत वस्तु को जीवन नहीं दे सकता। विधेयक किसी रोगी पुरुष या पशु को स्वस्थ नहीं बनाता।

अन्य रचनात्मक साधन अपनाने होंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में रचनात्मक दृष्टिकोण चाहिए ऐसे साधन बन्दई में अपनाये गये हैं। पश्चिमी बंगाल में भी अपनाये जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यह साधन शीघ्र ही अपनाये जायें आप कह सकते हैं कि और भी कार्य किये जायें। अच्छा, कीजिए। परन्तु यह विशेष दृष्टिकोण स्थिति को सुधारता नहीं। यह बात स्पष्ट है कि सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं और बाहिर भी वायद कोई एक आध ही ऐसा हो जिसकी इच्छा देश के पशुधन और विशेषकर दुग्धान् पशुओं की रक्षा के अतिरिक्त कुछ और हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं। परन्तु जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसके प्रयत्न में ऐसे विपरीत कार्य कर जाते हैं जिनके परिणाम बिल्कुल प्रतिकूल होते हैं। बुद्धि और कम अनुभव के भी विपरीत मार्ग हैं। अटार्नी जनरल के मतानुसार यह ऐसा विषय है कि जो राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है। बहुत अच्छा। मेरा परामर्श राज्य सरकारों को भी यही होगा कि वे ऐसे विधेयक उपस्थित या पास न करें।

कुछ सदस्य—शरम, शरम।

एक सदस्य—अपमान।

श्री जवाहरलाल नेहरू—यह माननीय सदस्य का मत है। मैं अपना मत प्रकट कर रहा हूँ।

श्री नन्दलाल शर्मा—आप उन की हत्या करवाना चाहते हैं ?

बहुत से सदस्य—कदापि।

श्री वी, जी, देश पांडे—वह यही कह रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं कह रहा हूँ कि देश के पशुधन के परिरक्षण का यह ढंग नहीं है।

श्री वी, जी, देश पांडे—डंग क्या है ? हुत्पा करना या हुत्पा की आजा देना ।

श्री जवाहरलाल—परन्तु पहला डंग यह है कि अर्थ और कृषि की शिक्षा ली जाये ।

श्री वी, जी, देश पांडे—मैं जानता हूँ । माननीय प्रधान मन्त्री को यह शिक्षा लेनी चाहिए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि पशु अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण हैं और मेरा विचार है कि मानव जीवन गौ से अधिक महत्वपूर्ण है । मैं इससे सहमत नहीं हूँ । मैं प्रधान मन्त्री पद से त्यागपत्र देने को तैयार हूँ परन्तु मैं इस प्रकार भुक्ते के लिए तैयार नहीं.....

श्री वी, जी, देश पांडे—आपको भुक्ता पड़ेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भारत में ऐसा आन्दोलन व्यर्थ, बुद्धि हीनता और हास्यास्पद है ।

श्री वी, जी, देश पांडे—माननीय मन्त्री महोदय को “बुद्धिहीनता” शब्द वापिस लेना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कि सरकार की स्थिति यह है और यह स्थिति बड़ी स्पष्ट है । हम चाहें गिर जायें चाहे खड़े रहे परन्तु ऐसे आन्दोलन के कारण हम भुक्ते नहीं । हम रचनात्मक साधन अपनायेंगे । हम उनको प्रयोग में लायेंगे और इस सम्बन्ध में हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे । क्योंकि पशुधन की रक्षा का यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है । मेरा जन लोगों से परानर्श है जो अर्थ और कृषि नहीं जानते कि वे कोई ऐसा कदम न उठाये जिससे हमारे पशुधन का विनाश हो जाये और जिसके महत्वपूर्ण वैधानिक परिणाम निकलते हैं और यह सम्भव नहीं है.....

श्री एन, सी, चैटरजी—क्या प्रधान मन्त्री महोदय जानते हैं

कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार की है और कहा है कि देश के आर्थिक हित में सम्पूर्णतया गोहत्या बन्द होनी चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं साहस पूर्वक कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करके गलती की है । उनकी ऐसा करने का अधिकार है । परन्तु मैं यहाँ यह कहता हूँ कि मेरे मत के अनुसार वह गलत कदम उठा रहे हैं । क्या माननीय सदस्य को यह पता है कि बम्बई सरकार ने ऐसा कदम उठाने से इनकार कर दिया है ।

श्री एन, सी, चैटरजी—उस समय माननीय श्री गोविन्द-वल्लभ पन्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे और उन्होंने ही वहाँ की सरकार को ऐसा करने का परामर्श दिया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य पं० गोविन्द वल्लभ पन्त के सम्बन्ध में इतना कुछ जानते हैं या नहीं, जितना कि मैं तथा अन्य सदस्य जानते हैं इसका कोई महत्व नहीं । हम राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकती है मेरा मत है कि उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए मेरा मत स्पष्ट है परन्तु यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । वे स्वतन्त्र हैं । परन्तु यहाँ हम राज्य सरकारों के बारे में नहीं बोल रहे बल्कि भारत सरकार और इस संसद की ओर से बोल रहे हैं और मैं कहता हूँ जहाँ तक इस सरकार का सम्बन्ध है हमें कुछ नहीं करना है । हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते ।

सेठ गोविन्द दास—(जागी) सभापति जी, पंडित जवाहरलाल जी और हमारे श्रेष्ठ नेता इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उनके प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है और कांग्रेस जिस के वे नेता हैं, उसी संस्था में मैंने जब से अपना जीवन आरम्भ किया, तब से मैं रहा हूँ । परन्तु जिस प्रकार पंडित जी को अपना मत रखने का अधिकार है, उसी प्रकार वे तो सच्चे प्रजा-तन्त्रवादी हैं, वे हम लोगों को भी अपना मत रखने का अधिकार देंगे...

श्री नन्दलाल शर्मा—नहीं, इसलिए विह्वल हो गया है।

सेठ गोविन्द दास—कम से कम जब मैं ने प्रधान मन्त्री के कह दिया कि यह मेरी कान्फेन्स का मकान है, यह मेरी अन्तरात्मा का सवाल है और मैं इस प्रश्न को सन् १९२३ से आज तक लगातार २६ वर्षों में लाना रहा हूँ, तब उन्होंने श्रीर पंडित जी ने मुझे इस बात का अधिकार दिया कि मैं इस प्रश्न को यहाँ उपस्थित कर सकता हूँ और इस सम्बन्ध में मेरा जो मत है वह भी मैं दे सकता हूँ, इसलिये कोई यह नहीं समझे कि कांग्रेस दल वाली किसी भी अन्तरात्मा को कुचलना चाहते हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू—आप तो पूरा अधिकार हैं।

सेठ गोविन्द दास—अभी आपने स्पष्ट देना दिया कि पंडित जी कितने बड़े प्रजातन्त्रवादी हैं पंडित जी पर इस प्रकार का कोई आरोप करना कि पंडित जी इस देश की राय के खिलाफ जाना चाहते हैं। या वे इस देश की राय के खिलाफ जायेंगे, ग़ुनग़ाना है। पंडित जी इस देश की गवर्न को जितना जानते हैं मेरा यह दावा है कि उत्पन्न इस देश की गवर्न को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता और यह इस देश का नागरिक है कि हम को पंडित जवाहरलाल नेहरू का सट्टा मेरा जग देश को मिला है।

श्री बी. जी. देशपांडे—(वैश्चन) भवाल।

सेठ गोविन्द दास—परन्तु इसी के साथ मैं पंडितजी से आप की मार्फत मर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक गोवध का मामला है, वहाँ तक उनकी जो राय है, उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है उन के विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में जो राय है उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है। और अगर उनके पास इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं कि जो यह समझते हैं कि गाय की उन्नति का यह रास्ता नहीं है, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे ग़लत बात कह रहे हैं। आज वे देखें कि देश की

परिस्थिति क्या है और हम जान को मने अनेक बार स्पष्ट किया है ।
 आज हम देख रहे हैं कि इस देश में जो बहुत बड़े जा रहे हैं व अच्छी व
 अच्छी नस्ल के हैं । बम्बई के एक कान्ग्रेसी को जो मैं पौडवाली से प्रार्थना
 करूँगा कि आपकी मार्फत कि वे स्वयं जाकर देखें कि क्या एरा हाजत
 है, कलकत्ते के कसाईखाने को जाकर देखें कि मजदूर के समारंभाने को
 जाकर देखें और नारा यह बिगान है जहाँ मैं जाऊँ इसके स्थानों पर जो
 भी हुआ है, वह मेरी ताईय करनी है कि जब तक हम इस में सौम्य
 कतई बन्द नहीं हो जाता तबतक हम प्रत्येक अच्छे मनुष्य को भी
 रक्षा नहीं कर सकते । हमारे ऊँ प्रान्तों में...

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त । मगर उस ही मन्त्र है । हम
 इस प्रस्ताव पर मत लेने प्रबन्ध कर रहे हैं ।

...कि क्या देश के दुष्प्राप्त और बाल्य हान मनुष्यों के परिस्थिति के
 इस विषयक पर विचार किया जाये या नहीं ।" जो प्रस्ताव के पक्ष
 में हैं, "हाँ" कहेंगे ।

कुछ सदस्य—हाँ ।

अध्यक्ष महोदय—जो प्रस्ताव के विपक्ष में हैं "नहीं, कहेंगे ।

कुछ सदस्यगण—नहीं ।

अध्यक्ष महोदय—विपक्ष वालों की निम्न शक्ति ।

कुछ सदस्य—पक्ष वालों की विजय रही ।

अध्यक्ष महोदय—"हाँ" वाले दावे की ओर और "ना" वाले
 वायें की ओर हो जायें । शान्त ! शान्त !! क्या अब अच्छा रहेगा कि मैं
 सदस्यों को बड़ा होने के लिये कहूँ ?

श्री बी. जी. देशपांडे—तथा उनके नाम मिले जायेंगे । उस स्थिति
 में हमें कोई आपत्ति नहीं ।

श्री एन. सी. चैटर्जी—आपने मत अनुसार अलग-अलग होने
 की आज्ञा दी है हमारी मांग भी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय—अलग-अलग हो जायेंगे ।

सदन दो भागों में विभक्त हो गया ।

"हाँ"-१३, "ना" ६१ प्रस्ताव अन्वीकार हो गया ।

विधेयक के पक्ष में मत देकर गोहत्या बन्द कराने वाले सदस्यों के नाम—

नं०	नाम सदस्य	प्रान्त	पार्टी
१	श्री के. एस. राववाचारी	आन्ध्र	प्र. सो. पा.
२	„ बबू रामनारायणसिंह	बिहार	जनता पार्टी
३	„ कूलन सिन्हा	बिहार	कांग्रेस
४	„ सेठ गोविन्द दास	मध्यप्रदेश	„
५	„ ठाकुरदाम भागन	पंजाब	„
६	„ पुरुषोत्तमदास टंडन	उत्तरप्रदेश	„
७	„ उदयशंकर हुये	„	„
८	„ मूलचन्द हुये	„	„
९	„ राजाराम शास्त्री	„	प्र. सो. पा.
१०	„ एन. सी. चटर्जी	पं० बंगाल	हिन्दु महासभा
११	„ बी. जी. देस पांडे	मध्य भारत	„
१२	„ नन्दलाल शर्मा	राजस्थान	रामराज्य
१३	„ भगवानन्त शास्त्री	विन्ध्य प्रदेश	प्र. सो. पा.

गोरक्षा विधेयक के विरुद्ध या गोहत्या जारी रखने के पक्ष में मत देने वाले सदस्यों के नाम इनमें ८७ कांग्रेसी हैं जिन्होंने बैलों की जोड़ों के निशान पर मत लिए। पर राज-सत्ता के मद्द तथा स्वार्थ के कारण गोरक्षा विधेयक के विपक्ष में मत दिए।

नं०	नाम सदस्य	पार्टी
	आन्ध्रा	
१	१ श्री एन. रामासेशैया	कांग्रेस
२	२ „ पैडी लक्ष्मैया	„
	आसाम	
१	३ श्रीमती बी. लौगमैन	„
२	४ श्री अमजद अली	प्र. सो. पा.

विहार

१	५ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
२	६ „ डा० राम सुभागमिह	„
३	७ „ राजेश्वर पटेल	„
४	८ „ सत्यनारायण सिन्हा	„
५	९ „ श्रीमती मुपनामिन	„
६	१० „ फणि गोपाल सेन	„
७	११ „ भागवत झा "आजाद"	„
८	१२ „ नागेश्वर प्रसाद सिन्हा	„
९	१३ „ जयपालसिंह	भारखंड

बम्बई

१	१४ श्री गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
२	१५ „ मूलदास भूदरदास वैश्य	„
३	१६ „ श्रीमती मणिवेन बी. पटेल	„
४	१७ „ चन्द्रशंकर भट्ट	„
५	१८ „ शिवराम रांगो राजे	„
६	१९ „ श्रीमती इन्दिरा ए० मावदेव	„
७	२० श्री के० एल, मोरे	„
८	२१ श्री बलवन्त नागेज दातार	„
९	२२ श्री राजाराम गिरिधारलाल दुवे	„
१०	२३ श्री टी, गार, नेमदी	„
११	२४ श्री बी, एच, खड्गेकर	स्वतन्त्र
१२	२५ श्री शंकर दाताराम मोरे	पी, बी पा०

मध्यप्रदेश

१	२६ श्री सरदार अमरसिंह सहगल	कांग्रेस
२	२७ श्रीमती मिनीमाता	„

न० नाम सदस्य		पार्टी
३	२८ श्री वासुदेव श्रीधर किरोलिकर	"
४	२९ श्री एम, जी, उडके	"
५	३० श्रीमती अनमूयाबाई काने	"
६	३१ श्री डा० पंजाबराव एन, देशमुख	"
७	३२ श्री लक्ष्मण श्रावण भटकर	"
८	३३ श्री अशोक महता	प्र. सो, पा,
मद्रास		
१	३४ श्री टी. टी. कृष्णमानाचारी	कांग्रेस
२	३५ " श्री वी. अलमेशन	"
३	३६ " एम. मुत्तुकृष्णन	"
४	३७ " सी. आर. नरसिंहन्	"
५	३८ " एन, वी. रामस्वामी	"
६	३९ " के. पेरियास्वामी गाडर	"
७	४० " एस. सी. बालकृष्णन्	"
८	४१ " एन. एम. लिंगम	"
९	४२ " आर. वेक्टरमण	"
१०	४३ " डा० डी. रामचन्द्र	कामनवील पार्टी
उड़ीसा		
१	४४ श्री टी० संगण्णा	कांग्रेस
पंजाब		
१	४५ श्री चौ० रणवीर सिंह	"
२	४६ " दीवानचन्द शर्मा	कांग्रेस
३	४७ " सरदार तेजासिंह अकरपुरी	"
४	४८ " सरदार सुरजीतसिंह मजीठिया	"
५	४९ " सरदार लालसिंह	अकालि

उत्तर प्रदेश

१	५०	श्री मर्ताश चन्द्र	कांग्रेस
२	५१	„ तुशीराम जर्मा	„
३	५२	„ दाहृतवान खा	„
४	५३	„ दिगम्बर मिह	„
५	५४	„ रघुवीर महाय	„
६	५५	„ लोटन राम	„
७	५६	श्रीमती उमा नेहरू	„
८	५७	श्रीमती शिवराजवती नेहरू	„
९	५८	„ डा० बी. बी. केनकर	„
१०	५९	„ पं० जवाहरलाल नेहरू	„
११	६०	„ जे. एन. विल्सन	„
१२	६१	„ रघुनाथमिह	„
१३	६२	„ विश्वानाथ राय	„
१४	६३	„ हरप्रसादमिह	„

पश्चिम बंगाल

१	६४	श्री डा० मुगोल रंजन चैटर्जी	कांग्रेस
२	६५	„ अनिलकुमार चन्द्रा	„
३	६६	„ सतीशचन्द्र सामन्त	„
४	६७	„ डा० मनोमोहन दास	„
५	६८	„ अरुण चन्द्र गुहा	„
६	६९	„ पूर्णेंद्रु शेखर नास्कर	„

हैदराबाद

१	६६	श्री के, जनार्दन रेड्डी	कांग्रेस
२	७०	„ पी, रामस्वामी	„
३	७१	„ कृष्णाचार्य जोशी	„

नं०	नाम सदस्य	पार्टी
४	७२ श्री डा० एस, ए, एवनिजिर	"
५	७३ " सुरेशचन्द्र	"
६	७४ " शंकर राव तेलकीकर	"
७	७५ " एच, सी, हेडा	"
	जम्मू और काश्मीर	
१	७६ श्री लक्ष्मणसिंह चरक	कांग्रेस
२	७७ " प० शिवनारायण फांतेदार	"
	मध्यभारत	
१	७८ श्री डा० कैलाशनाथ काटजू	कांग्रेस
	मैसूर	
१	७९ श्री एम, बी, कृष्णप्पा	कांग्रेस
२	८० " डोडा थिमईया	"
३	८१ " सी, आर, वासप्पा	"
	राजस्थान	
१	८२ श्री राजबहादुर	कांग्रेस
२	८३ " राधेव्याम रामकुमार मुरारका	"
३	८४ " नेमीचन्द्र कासलीवाल	"
	सौराष्ट्र	
१	८५ श्री खंडूभाई कासनजी देसाई	कांग्रेस
	ट्रावनकोर कोचीन	
१	८६ श्री जार्ज टामस कोट्टकपली	कांग्रेस
२	८७ " ए, एम, थोमस	"
३	८८ " सी, आर, इयुत्ती	"
४	८९ " एन, श्रीकान्तन नायर	रि, सो, पा,

कुर्ग

१ ६० श्री एन. सोमना कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश

१ ६२ श्रीमती राजकुमारी प्रमृत्तशोर "

२ ६३ श्री गोपीराम "

मणिपुर

१ ६४ श्री लेसराम जोगस्वरमिह "

विन्ध्य प्रदेश

१ ६५ श्री शिवदत्त उपाध्याय "

कांग्रेस पार्टी = ५७ अन्य पार्टी = कुल १५

उन सदस्यों की सूची जिनकी उपस्थिति २ अप्रैल १९५५ को लिखी हुई है, पर जिन्होंने गोरक्षा विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मत नहीं दिये । कांग्रेस पार्टी के २४६ उपस्थित सदस्यों में से केवल ६३ ने मत दिये तथा १५३ सचेतक की अवहेलना करके मौन रहे ।

नं० नाम सदस्य पार्टी

आन्ध्र

१ १ श्री बी. बी. गिरि कांग्रेस

२ २ " कोथा रघुरामैया "

३ ३ " राय सम शेपागिरिराव "

४ ४ " टी. एन. विश्वानाय रेड्डी "

५ ५ " एम. बी. गंगावर शिवा "

६ ६ " कांडल सुब्रह्मण्यम् प्र. सो. पा.

७ ७ " नलारेड्डी नायडू "

८ ८ " कनेटी मोहनराव साम्यवादी

९ ९ " कोंडू सुब्बा राव "

१० १० " सनक वुचि कोटैय्या "

११	११ श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय	स्वतन्त्र
१२	१२ " एत. वी. एज. नरसिंहम्	"
१३	१३ " सी. आर. चौधरी	"
१४	१४ " मंगलागिरि नानादास	"

आसाम

१	१५ श्री एन. सी. देव	कांग्रेस
२	१६ " सीतानाथ ब्रह्म चौधरी	"
३	१७ " रोहिणीकुमार चौधरी	"
४	१८ " कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी	"
५	१९ " देवकान्त बरुआ	"
६	२० " जोगेन्द्रनाथ हजारीका	"
७	२१ " चौखामून गोहिन	"

विहार

१	२२ श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा	कांग्रेस
२	२३ श्री रामधानीदास	"
३	२४ " जगजीवनराम	"
४	२५ " महेन्द्रनारायण सिंह	"
५	२६ " डा० सत्यनारायण सिन्हा	"
६	२७ " पं० द्वारकानाथ तिवारी	"
७	२८ " विभूति मिश्र	"
८	२९ " भोला राउत	"
९	३० " डा० सैयद महमूद	"
१०	३१ " अवधेश्वरीप्रसाद सिन्हा	"
११	३२ " अनिरुद्ध सिन्हा	"
१२	३३ " श्यामनन्दन मिश्र	"
१३	३४ " ललितनारायण मिश्र	"

१४	३५	श्री बनारसीप्रसाद निन्हा	कांग्रेस
१५	३६	" नयन तारादाम	"
१६	३७	" विविजय नारायणसिंह	"
१७	३८	" मधुराप्रसाद मिश्र	"
१८	३९	" रामराज जगवाड़े	"
१९	४०	" लाल हननोम	"
२०	४१	" ए. इम्राहीम	"
२१	४२	" डा० हरिमोहन	"
२२	४३	" विज्ञेश्वर मिश्र	प्र. गो. पा.
२३	४४	" पं० गुरेशचन्द्र मिश्र	"
२४	४५	" किराडी सुतहर	"
२५	४६	" वैनजमिन हनदा	स्वतन्त्र
२६	४७	" कान्हागाम देवगन	भारखंड

यम्बई

१	४८	श्री प्रकाश चावला	कांग्रेस
२	४९	" एम. एम. गांधी	"
३	५०	" रुगाजी भावजी परमार	"
४	५१	" शान्तिनाथ गिरवराज पारिल	"
५	५२	" जी. बी. मावर्नकर	"
६	५३	" फूलसिंह जी बां. दाभी	"
७	५४	" कन्हैयालाल नानाभाई देसाई	"
८	५५	" बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल	"
९	५६	" यशश्चन्तराव पारतन्डराव मुक्ते	"
१०	५७	" यू. प्रार. बांगवत	"
११	५८	" हरी विनायक पाटस्कर	"
१२	५९	" नरहर विष्णु गाडगिल	"

१३	६०	श्री चिन्तामण्य द्वार गानाय देशमुख	कांग्रेस
१४	६१	" वेकटराव पिराजीनाथ पन्नाय	"
१५	६२	" जगन्नाथराव कृष्णराव भोनाज	"
१६	६३	" रामण वातण्य भिदारी	"
१७	६४	" डी. पी. करभरकर	"
१८	६५	" जीतीम जाल्वा	"
१९	६६	" नारायण गादोवा कडालकर	"
२०	६७	" एस. बी. पाटिका	"
२१	६८	" इन्दुभाई बी. ग्रामीण	स्वतन्त्र

मध्यप्रदेश

१	६९	श्री भूपेन्द्रनाथ भिना	कांग्रेस
२	७०	" सी. डी. गीतग	"
३	७१	" लुक्चन्द सोधिया	"
४	७२	" पं० जी. एल. तिनारी	"
५	७३	" रामचन्द्रभाई एन. साहू	"
६	७४	" श्रीमन्नारायण अग्रवाल	"
७	७५	" के. जी. देशमुख	"
८	७६	" गोस्वामी राजा सहदेव भारती	"
९	७७	" गोपालराव वाजीराव खेडकर	"
१०	७८	" भगलाल बागड़ी	प्र. सो. पा.

मद्रास

१	७९	श्रीमती एम. चन्द्रशेखर	कांग्रेस
२	८०	श्री टी. एस. अविनाशिलिंगम चेट्टिपार	"
३	८१	" पी. टी. थानू पिल्ले	"
४	८२	" एम. शंकरपांडियन्	"
५	८३	" एस. बालमुब्रह्मण्यम्	"

६	८४	श्री यू. श्रीनिवास मल्लय्या	कांग्रेस
७	८५	" नेतूर पी. दामोदरन्	"
८	८६	" आई. ईयाचरण	"
९	८७	" ए. कृष्ण स्वामी	का. वी. पा.
१०	८८	" वी. ब्रुवाराधसामी	त. टा. पा.
११	८९	" डा० एडवर्डपाल मथुरम	स्वतन्त्र
१२	९०	" एम. डी. राम स्वामी	फावर्ड ब्लोक
१३	९१	" ए. के. गोपालन	साम्यवादी
१४	९२	" के. ए. दामोदर मंजन	प्र. सो. पा.
१५	९३	" के. केलप्पन	"

उड़ीसा

१	९४	श्री निरंजन जेता	कांग्रेस
२	९५	" निरयानन्द कानूनगो	"
३	९६	" लोकनाथ मिश्र	"
४	९७	" पं० निगराज मिश्र	"
५	९८	" रामचन्द्र नाक्ती	"
६	९९	" भागवत माहू	"
७	१००	" कान्हूचर जेता	"
८	१०१	" पी. मुन्ना राव	ग. प.
९	१०२	" गिरधारीलाल भोई	"
१०	१०३	" नटवर पान्डे	"
११	१०४	" सारंगधरदास	प्र. सो. पा.
१२	१०५	" लक्ष्मीवर जेता	गणतन्त्र परिषद्
१३	१०६	" उमाचरण पटनायक	स्वतन्त्र
१४	१०७	" विजयचन्द्र दास	साम्यवादी

पंजाब

१	१०८ श्रीमती सुभद्रा जोशी	कांग्रेस
२	१०९ श्री डा० वीरेन्द्रकुमार सत्यवादी	"
३	११० " घमंडीलाल बन्मल	"
४	१११ " रामदान	"
५	११२ " हेमराज	"

उत्तर प्रदेश

१	११३ श्री महावीर त्यागी	कांग्रेस
२	११४ " भक्त दर्शन	"
३	११५ " सी, डी, पाड्य	"
४	११६ " मुकन्दलाल अग्रवाल	"
५	११७ " मौलाना अबुलकलाम आजाद	"
६	११८ " सुन्दरलाल	"
७	११९ " हीरावल्लभ त्रिपाठी	"
८	१२० " रघुवरदयाल मिश्र	"
९	१२१ " कन्हैयालाल कल्मीकि	"
१०	१२२ " श्रीचन्द सिंगल	"
११	१२३ " तरदेव स्नातक	"
१२	१२४ " चौधरी रघुवीरसिंह	"
१३	१२५ " कृष्णचन्द्र	"
१४	१२६ " होतीलाल अग्रवाल	"
१५	१२७ " वैकटेशनारायण तिवारी	"
१६	१२८ " पं० बालकृष्ण शर्मा	"
१७	१२९ " शिवदयाल उपाध्याय	"
१८	१३० " प्यारेलाल कुरील तालीव	"

१६	१३१	श्री स्वामी रामानन्द झांघी	कांग्रेस
२०	१३२	" कर्तल बी, एच, जेदी	"
२१	१३३	" बुनाकीनान्त वर्मा	"
२२	१३४	" गणेशजीनान्त चांदरी	"
२३	१३५	" फ़िरोज गांधी	"
२४	१३६	" पत्तानाल	"
२५	१३७	" विभवन नारायणसिंह	"
२६	१३८	" दिनेश प्रतापसिंह	"
२७	१३९	" केजवदेव मालवीय	"
२८	१४०	" सोहनलाल धूमिया	"
२९	१४१	" दमरय प्रसाद द्विवेदी	"
३०	१४२	" सरजूप्रसाद मिश्रा	"
३१	१४३	" सीताराम अस्थाना	"
३२	१४४	" विस्वानाथ प्रसाद	"
३३	१४५	" रामजी वर्मा	"
३४	१४६	" श्रीमती कनकेन्दुमनी शाह	स्वतन्त्र
३५	१४७	" श्रीमती यकुन्तला नायर	हि, प,
३६	१४८	" आर, एन, सिंह	प्र, सो, पा,

प० बंगाल

१	१४९	श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा	कांग्रेस
२	१५०	" मुहम्मद खुदावस्स	"
३	१५१	" सुबोध हमदा	"
४	१५२	" डा० मत्स्यवान राय	"
५	१५३	" हीरेन्द्रनाथ चुकजी	साम्यवादी
६	१५४	" साधन चन्द्रगुप्त	"

७	१५५ श्री कमल कुमारी जग	साम्प्रदायी
८	१५६ श्रीपती गणु च.दासी	"
९	१५७ " नुसार च.दासी	"
१०	१५८ " निकुंज मिश्राजी चौधरी	"
११	१५९ " दुर्गाचरण पंतजी	ज. सं.

नैदरावाद्

१	१६० श्री स्वामी गगानेश सीम	कांग्रेस
२	१६१ " मा० दीक्षित उद्गाताह पंतमारी	"
३	१६२ " आर, एम, दीवान	"
४	१६३ " एच, जी, वैद्यगु	"
५	१६४ " सी, माधव रेड्डी	प्र, सो, पा,

जम्मु व काश्मीर

१	१६५ श्री मुहम्मद सईद मसूदी	कांग्रेस
२	१६६ " सफी मुहम्मद अकबर	"
३	१६७ " मुहम्मद सफी चौधरी	"
४	१६८ " गुलाम कादिर	"

मध्य भारत •

१	१६९ श्री अमरसिंह सावजी जायर	कांग्रेस
२	१७० " लीलाधर जोशी	"
३	१७१ " भगुनन्दु मालवीय	"
४	१७२ " राधाचरण शर्मा	"

मैसूर

१	१७३ श्री एन, केशवैयागार	कांग्रेस
२	१७४ " टी, मादिया गौडा	"
३	१७५ " टेकर सुब्रह्मण्यम्	"
४	१७६ " एम, के, शिवनजप्पा	"

- ५ १७७ " के जी बोड्यार "
 पटियाला यूनीयन
- १ १७८ श्री हीरामिह चिन्तारिया कांग्रेस
 २ १७९ " रणजीतसिंह स्वतन्त्र
 राजस्थान
- १ १८० श्री पन्नालाल बालूपान कांग्रेस
 २ १८१ " दीनानाथ राम भंडारी "
 ३ १८२ " बलवन्तसिंह मेहता "
 ४ १८३ " राजचन्द्र सैन रा, रा, प,
 ५ १८४ " गिरिराज शरण मिह स्वतन्त्र
 मौराष्ट्र
- १ १८५ श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता कांग्रेस
 २ १८६ " जेठालाल हरिकृष्ण जोशी "
 ३ १८७ " नरेन्द्र पी, नथवानी "
 ४ १८८ " जयन्तिलाल नरभेराम पारख "
 द्राघनकोर कोचीन
- १ १८९ श्री पी, पी, मैयन कांग्रेस
 २ १९० " के, टी, अच्युतन "
 ३ १९१ " आर, बैलायुधन स्वतन्त्र
 ४ १९२ " बी, पी, नायर "
 ५ १९३ " कुमारी ऐन, मैस्कोरीन "
 ६ १९४ " एन, नैसामती तिरु, त, काँ
- अजमेर
- १ १९५ श्री ज्वालाप्रसाद कांग्रेस
 दिल्ली
- १ १९६ श्री राधारमण कांग्रेस
 २ १९७ " कृष्णननायर "

३	१९८ श्री नवल प्रभाकर	कांग्रेस
४	१९९ श्रीमती सचेता कृपलानी	प्र, सो, पा,
	हिमाचल प्रदेश	
१	२०० श्री ए, आर: सेवल	स्वतन्त्र
	कच्छ	
१	२०१ श्री गुलानशंकर अमृतलाल धोत्रिका	कांग्रेस
	मनीपुर	
१	२०२ श्री रिशंग किशिंग	प्र, सो, पा,
	त्रिपुरी	
१	२०३ श्री दशरथ देव	साम्यवादी
२	२०४ " वीरेन्द्र	"
	विन्ध्य प्रदेश	
१	२०५ श्री रामसहाय तिवारी	कांग्रेस
२	२०६ " सरदार राजभानुसिंह तिवारी	"
३	२०७ " रणदमन सिंह	प्र, सो, पा,
	अण्डमान	
१	२०८ श्री जान रिचडसन	एंग्लो इंडियन
	एंग्लो इंडियन	
१	२०९ श्री फ्रेक एन्थनी	"
२	२१० " ए, ई, टी, बैरो	"
	कांग्रेस	१५३
	साम्यवादी	१३
	स्वतन्त्र	१५
	प्र, सो, पा,	१३
	अन्य	१६
	जोड़	२१०

श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन का श्री नेहरू जी के नाम पत्र

२ दिसम्बर १९४७ ई. दिल्ली

सोमवार ४ अक्टूबर १९४७

प्रिय महोदय,

मेरा अनुमान है कि आपने इस बात की सूचना मिल गयी होगी कि परसों जब 'भारतीय नुतन विचार' दिनेश १९४७" का विचारार्थ स्वीकृत कराने के लिए श्री गोविन्द वल्लभ पंत के अध्यक्ष पर मतदान हुआ तब इन प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के लिये दलित दल के सदस्यों को दल के नाम पर 'नकार' जारी की जाने पर भी मैंने अपना मत इसके पक्ष में दिया था। भाषण करने के सम्बन्ध २ मिनट पहिले मुझे सचिवत की एक प्रति दी गई थी और उस समय मुझे आश्चर्य हुआ था।

१६ जुलाई १९४७ का यह विषयक उद्घोषित किया गया था। विधेयक को विचारार्थ स्वीकृत कराने के प्रस्ताव पर २ अप्रैल, १९४५ को अन्तिम बहुमत होने और मतदान किं. मत में पहिले १९४३ और १९४४ में लोकसभा में मतदान ३ निर्णयों पर इन प्रस्ताव पर बहुमत हुई थी। यदि ऐसा सोचा गया था कि विधेयक कांग्रेस की नीति के अनुकूल नहीं है तो कांग्रेस दल या उनसे नेता समेत उद्घोषित करने था उसके विचारार्थ प्रस्ताव रखने का दावा करने थे। इन कारणों ने कि न केवल प्रस्ताव रखा नहीं गया बल्कि कई बार उस पर बहुमत भी होने की गई मैंने स्वभावतः यह अनुमान किया कि इस प्रश्न पर कांग्रेस दल ने अपना कोई विशिष्ट दृष्टिकोण निश्चित नहीं किया है और विधेयक के प्रस्तावक तथा दल के अन्य सदस्य अपने वैयक्तिक विचारों के अनुसार बोलने और मत देने के लिये स्वतन्त्र हैं।

साधारण नियम यह है कि दल में विचार विमर्श करके किसी विशेष विषय का दल का प्रश्न घोषित कर देने के बाद ही सचिवत

बात यह हुई कि कल दोपहर से पहने सत्यनारायणसिंह ने मुझसे कहा कि यह विधेयक कुछ दिन रखा जाने वाला है और मुझसे पूछा कि इस प्रस्ताव के पूर्व इतिहास को दृष्टि में रखते हुए क्या वह सदस्यों को इसका विरोध करने के लिए सचेतक जारी कर दें। मैं इस बात पर राजी हो गया कि वे ऐसा करें। मुझे खेद है कि ऐसा किया गया तथा इसका भी कि आपके पास सचेतक इतनी देर में पहुंचा।

संक्षेप में इसका पूर्व इतिहास यह है। मेरा अनुमान है कि पिछले दो सालों में हम लोगों ने गोविन्ददास जी से कई बार इस पर बहस की। अटार्नी जनरल ने भी इस विषय पर विचार किया। खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने कुछ काम किये हैं और कुछ जारी है। क्योंकि जैसा मैंने गोविन्ददास जी को आश्वासन दिया था यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने पशुओं की रक्षा करें और अन्य गायों के विषय को अजग का दुधारू गायों की हत्या रोकें। किन्तु हम लोग अनुभव करते थे कि समस्त भारत के लिए ऐसा विधेयक केवल पारित कर देने से कुछ परिणाम नहीं निकलेगा वरन् इससे स्थिति और बिगड़ जायगी। हमें अधिक रचनात्मक दृष्टि अपनानी थी। देश के विभिन्न भागों की परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर समस्त भारत के लिए एक अधिनियम लागू करने से कई तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। राज्य शासनों के लिए ऐसे दृष्टिकोण पर विचार करना अधिक उपयुक्त था। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक भारत व्यापी अधिनियम उत्तर-पूर्वी सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों और जन "जाति" वाले क्षेत्रों को स्वयंसेव लागू होता। वहां हम लोगों के लिए इससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती। आज की स्थिति में ही हमें वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन जन जाति वाले क्षेत्रों में आन्दोलन का एक यह तारा है कि भारत सरकार विधि द्वारा गोवध का प्रतिबन्ध करने जा रही है।

इस तरह हम लोगों को एक स्थिति का सामना करना पड़ा जब यह

विवेक हमारे विवि परामर्शदाताओं की राय में संसद के कार्य क्षेत्र से एकदम बाहर था और इनके गुण-दोष की दृष्टि ने इसे समस्त भारत पर लागू करता बुद्धिमानी नहीं होती। हम लोगों ने यह भी अनुभव किया कि हमारा दृष्टिकोण अन्य न होकर रचनात्मक होना चाहिये। शेष बातों पर राज्य सरकारें जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकती हैं। पिछले साल या उससे पहले भी यह बात गोविन्ददास जी के सामने बार-बार रखी गयी। इस पर कई बार वहाँ भी हुई। गोविन्ददास जी ने तर्कों के नथ्य का अनुभव भी किया लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी भावना और अन्तरात्मा की बात हो गई है और यद्यपि सरकार विवेक का अनुमादन नहीं करती या इसे विधान मण्डल के अधिकार के बाहर समझा जाता है तो भी वह उसे प्रांगचारिक रीति से प्रस्तावित करना चाहते हैं—परिणाम जो कुछ भी हो। वृत्ति यह उनकी अन्तरात्मा का विषय था इसलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत स्पष्ट रीति से सरकार का दृष्टिकोण समझा दिया गया था। इस आन्तरिक मतभेद के कारण इस विवेक को कुछ अवसरों पर गोविन्ददास जी के सहमत ने अस्थगित कर दिया गया था।

बहुत विराम के बाद यह विवेक गूँगाएँ कल आगया और मुख्य सचिव ने मुझे-उसके बारे में सबेरे या दोपहर से पहले पूछा। मैं उनसे इस बात के लिए सहमत हो गया कि हम लोग सदस्यों को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी करा दें और एक सचेतक जारी कर दिया जाय। मैंने उनसे भी यही कहा जो हम लोगों ने पहले कहा था कि गोविन्ददास जी को या अन्य किसी को भी जो इसे अपनी अन्तरात्मा का प्रश्न समझता है अपने विचार प्रकट करने और उसके साथ ही अपने मतदान करने में स्वतन्त्रता होगी।

जो कुछ हुआ उसका संक्षेप में यह वृत्तान्त है। आपको शायद याद हो कि जब गोविन्ददास जी वहाँ के अन्त में बोल रहे थे तो मैंने बीच में दखल दिया था और कहा था कि उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था

उसे अपमान की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी। जिनकी भी माता उस प्रकार की थी उसके लिए यही बात समझी थी। इसलिए नौजवानों ने होते हुए आपको वैसा मतदान करने का जैसा आपने किया था अधिकार था।

आज मैंने अपने दल की सभा में इस विदेशी की चर्चा की थी और स्थिति फिर विस्तारपूर्वक समझाई थी।

इस प्रश्न के तथ्य के बारे में यह सम्मति है कि मेरे विचार आपसे विचार के समान न हों लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आजकल भारत के कुछ स्थानों में जो गोरक्षा हो रही है यद्यपि पशु-उत्पत्ति बहुत कम है जो पहले हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर देना—प्रत्यक्ष ही दुधारू गायों और उनके सतत के सम्बन्ध में। भारत में विदेशी विशेष परिस्थितियों और अपने पशु पाल के दो गोरक्षा के कारण मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ। मैं इसके बारे में राज्य सरकारों और अपने खाद्य और कृषि मन्त्रालय को निजना रहा है और कई काम किए भी गये हैं जिनके कुछ नतीजे निकले हैं। कुछ प्रत्यक्ष लाभ किये जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि केवल इस विषय के पास ही जाने से ही कोई सन्तोषजनक परिणाम न होता बल्कि इसके विपरीत जटिलताएँ पैदा हो जाती और पशुओं की रक्षा भी नहीं होती।

यह सम्भव है कि मैंने अपनी बात अच्छी तरह स्पष्ट नहीं की। जो भी हो मैं यह नहीं समझता कि आपको कांग्रेस दल या लोकसभा से त्यागपत्र देने का कोई अवसर है। यदि आप ऐसा निश्चय करेंगे तो मुझे अवश्य ही खेद होगा।

आपका
जवाहरलाल नेहरू

२४ अप्रैल १९५५ को गोहत्या निरोध दिवस

गोहत्या जारी रखने के लिये २ अप्रैल १९५५ को लोकसभा में श्री नेहरू जी के त्याग-पत्र देने की घमकी के विरोध में २४ अप्रैल १९५५ को देश के कोने-कोने में गोहत्या निरोध दिवस मनाया गया। दिल्ली तथा सैकड़ों स्थानों में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसमिति से पास हुआ:—

प्रस्ताव

“यह विराट जन सभा सरकार से यह माँग करती है कि सम्पूर्ण भारत में गोवध कानून से बन्द कर दिया जाये। यह सभा पं० नेहरू जी की २ अप्रैल १९५५ की धोपणा को जो उन्होंने संसद में गोरक्षा के विषय में की है अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखती है। यह सभा घोषित करती है कि गोरक्षा के प्रश्न पर पं० जवाहरलाल नेहरू जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत की नमस्त जनता (धर्म, जाति और राजकीय दलबन्दी के बावजूद) सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी के पक्ष में है। इसलिये यह सभा माँग करती है कि या तो पं० नेहरू अपनी धोपणा को वापिस ले, या प्रधान मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दे।”

दिल्ली की सार्वजनिक सभा में २४ अप्रैल १९५५ को फ्रंसी के सन्त तथा गोहत्या निरोध समिति के सर्वाधिकारी ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी प्रधान पद से निम्नलिखित भाषण दिया:—

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।

प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

समुपस्थित महानुभावो ।

आज मुझे न तो गोमाता की पवित्रता तथा पावनता पर कुछ कहना है, न उसके महत्व को ही बताना है। आज की सभा का विषय तो है संसद में हमारे प्रधान मन्त्री की वह अनुचित अनुत्तरदायित्व पूर्ण वक्तृता जो उन्होंने गोरक्षा के सम्बन्ध में दी है। भारतीयों राज्यों का

सब से प्रधान व्यक्ति हिन्दुओं की भावनाओं पर इस बुरी तरह प्रहार करे यह भारत के लिए, हिन्दू जाति के लिए और हम सभा करने वालों के लिए लज्जा की बात है। प्रधान मन्त्री के गौ के सम्बन्ध में कुछ भी विचार रहे हो वे चाहे उसे साधारण पशु ही मानते रहे हों, किन्तु सब से अपनी मान्यता को मनवाने का आग्रह करना, इसी प्रश्न पर चुनाव लड़ने को उद्यत हो जाना, त्याग पत्र देने की धमकी देना तथा "सचेतक" निकाल कर जनता के प्रतिनिधियों को गोहत्या के समर्थन करने को विवश करना यह सब से बड़ा अन्याय तथा देशद्रोह है ऐसी वक्तृता देकर नेहरू जी ने प्रजातन्त्र की हत्या ही नहीं की है एक स्वेच्छाचारी शासक पने का परिचय दिया। जब अपने निजी मान्यता को बलपूर्वक प्रजा के ऊपर लाद देना ही प्रजातन्त्र का परिचायक है, तो मैं पूछता हूँ औरंगजेब ने फिर क्या बुरा किया? औरंगजेब हृदय से मठ मन्दिरों और मूर्तियों की पूजा राष्ट्र के लिए घातक समझता था, उस ने १०० प्रतिशत हिन्दुओं की भावना की अवहेलना करके मठ मन्दिरों को तुड़वा दिया फिर उस में और नेहरू में अन्तर ही क्या रहा? आज नेहरू जी भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ६० प्रतिशत भारतीयों की भावना की हत्या कर रहे हैं, उस दिन मुवावजे के सम्बन्ध में अपनी सम्पत्ति प्रकट करते हुए नेहरू जी ने कहा था, यद्यपि "मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरुद्ध हूँ, किन्तु दूसरे बहुत लोग इस के विरुद्ध नहीं हैं। मैं उन की भावना का आदर करता हूँ और इसीलिए मुवावजा देने के पक्ष में हूँ"। जब वे धन जैसी छोटी बात में तो लोगों की भावना का आदर करते हैं और गौ जो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, उस विषय में हमारी भावनाओं पर प्रबल प्रहार करके हमें धमकी देकर डराते धमकाते हैं यह कहाँ का न्याय है, यह कैसी प्रजातन्त्रीय पद्धति है?

इस के पश्चात् श्री टंडन जी ने जो पत्र लिखा उस का नेहरूजी ने जो उत्तर दिया वे तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो ही चुके हैं, वह

दोनों पत्र मेरे सम्मुख उपस्थित हैं उन दोनों के पढ़ने से निम्न बातें सिद्ध होती हैं :—

- (१) सेठ गोविन्ददास जी ने विधेयक अपने दल की अनुमति से प्रस्तुत किया था ।
- (२) सभी लोग गोवध बन्दी चाहते थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया ।
- (३) केवल नेहरूजी ही व्यक्तिगत रूप से गोहत्या बन्दी के विरोधी हैं, जब भी प्रसंग आया उन्होंने ने सरकारों पर, सदस्यों पर, व्यक्तिगत प्रभाव डाल कर इस प्रश्न को टलवाया ।
- (४) जब उन्हें वैधानिक रूप में विरोध करने का किमी की ओर से आश्रय मिला तब उन्होंने ने अनुचित अवैधानिक ढंग से सचेतक जारी करके लोगों को विवश किया और ६५ ऐसे सदस्य भी निकल आए जिन्होंने जनमत की उपेक्षा करके अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध, केवल टिकट के लाभ से गोहत्या का समर्थन किया ।
- (५) श्री टंडनजी, प० ठाकुरदामजी भार्गव, सेठ गोविन्ददासजी जैसे कुछ कॉंग्रेसी सदस्यों ने माहूम तो किया उन्होंने ने 'सचेतक' होते हुए भी उस के विरुद्ध मत दिया, किन्तु दल के मोह को वे भी न छोड़ सके । यदि टंडन जी थोड़ा माहूम करते और सदस्यता से त्याग पत्र देकर पुनः स्वतन्त्र रीति से चुनाव को खड़े हो जाते तो नेहरू जी को तथा मसार को पता चलता कि गोरक्षा के सम्बन्ध में जनता का क्या विचार है और नेहरू जी बार बार इसी प्रश्न पर चुनाव लड़ने और त्याग पत्र देने की धमकी देते हैं वह सर्वथा व्यर्थ है । यों कहने पर तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की नीति की उसके आचार व्यवहार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते रहते थे, किन्तु यथार्थ में वे उस का साथ न देते तो निश्चित

मत है नही भारत का कुद न होना । अतः हमने यह विषय हुआ कांग्रेस में रह कर कोई गोहत्या नहीं करना सकता । जनता को ऐसे लोगों से जिनकी भी प्रचार की आना न करनी चाहिए ।

- (६) जब तक नेहरू जी का वश चलेगा तब तक वे न केन्द्री में, न राज्यों में गोवध बन्दी का कानून न बनाने देंगे, अतः अब साधारण ग्राम्योत्थनों से काम न चलेगा । हमें इनके लिए प्रान्त प्रान्तीय बनाना पड़ेगा, प्राणियों की बर्बादी लगाने पड़ेगी । अब यह कुछ माया थी, नेहरू जी के इस दृष्टिकोण ने काम न चल रहा था । अब भी जनता सोचती रही और इस दिशा में प्रयत्न प्रयत्न न करने तां की तो रुकती ही रहेगी । साथ ही यह कुछ अन्धों, गुन्नापाठ उपासना की सभी मान्यता नष्ट हो जायेगा ।

अब हमें क्या करना चाहिए ?

- (१) अब हमें गांव-गांव और घर-घर इन बातों का प्रचार करना चाहिए कि नेहरू जी सर्वथा गोवध बन्दी के पक्ष में हैं वे गोहत्या चालू रखने को त्यागपत्र देने की भी तयार हैं, जनता को इन से सावधान हो जाना चाहिए ।
- (२) संसद में जिन लोगों ने गोहत्या के पक्ष में मत दिए हैं उनके प्रान्तवार नाम प्रकाशित करने चाहिये और उनकी बात गोहत्या के घोषित करना चाहिए, उन के यहां प्रदर्शन करना है, सामाजिक बहिष्कार तथा और भी ऐसे उपाय करने चाहिये जिन से सब को विदित हो जाय इन्होंने जनता की भावना का अपमान किया है ।
- (३) अब साधारण उपायों से काम न चलेगा, हमें सामुहिक संगठित रूप से प्रत्येक प्रान्त में दूसरे प्रबल उपाय चढ़ाने चाहिये । यह तो निश्चय है, यह गोहत्या की समर्थक सरकार की भी भयभीत होकर कुछ करेगी नहीं, किन्तु कुछ लोगों के त्याग के पश्चात् देश में जो वायुमण्डल बनेगा, क्रान्ति होगी उसमें यह सरकार भयभीत होकर

गोहत्या बन्द करेगी अतः हमें सम्पूर्ण देश में प्रबल क्रान्ति का वायुमण्डल तैयार करना चाहिये ।

- (४) बहुत से लोगों का मत है हम चुनाव में इन्हें हरा देगे, किन्तु जिनके हाथ में राज्य सत्ता है, जो स्वैच्छाचारी हैं, जो उचित अनुचित सभी उपायों को कार्य में लाने में नहीं हिचकते । गुना ऐसा भी जाता है कि चुनाव के दो वर्ष पूर्व से ही वनिकों से कई करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिये हैं, उन्हें एक ही उद्देश्य से बनी कई पृथक-पृथक संस्थायें चुनाव में नहीं हरा सकती । यदि चुनाव में हारना ही हो, तो सब मिल कर एकमात्र नेहरू जी को हरा कर यह सिद्ध कर दो कि गोहत्या के सम्बन्ध में जनता उनके विचारों से सहमत नहीं । अतः गोमाता की ही रक्षा के लिये प्रबल आन्दोलन करना चाहिये ।

सारांश यह है कि हमें सम्पूर्ण शक्ति लगा कर गोबध बन्द कराना है । गौ हमागी भावनाओं का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी परम्परा का केन्द्र बिन्दु है । गौरक्षा करना यदि साम्प्रदायिक है, तो हम समस्त हिन्दू धोर साम्प्रदायिक बनने को तैयार हैं, यदि गोहत्या बन्द कराने से हम भुखो मर जायेंगे, तो हम उनके लिए भी तैयार हैं । हम साष्टक देना चाहते हैं कि यह हमारा धार्मिक प्रश्न है । राज्य भले ही धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक हो, हम धर्महीन स्वैच्छा से नहीं हेंगे । हम बड़े से बड़ा बलिदान देकर ऊँचे से ऊँचा मूल्य चुका कर गौरक्षा करेंगे । श्री नेहरू जी और उनके पीछे जाँ अमृत्य और निस्सार युक्तियाँ इस के पक्ष में देते हैं उनका हम समय गमय पर प्रबल खडन कर चुके हैं वे दूसरे धर्म वालों की भावना का आदर करते हैं किन्तु हमारी भावनाओं पर प्रहार करते हैं, अतः हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए, इस सरकार से अब कोई आशा नहीं करनी चाहिए । आप सभी भाई सामूहिक रूप से संगठित होकर गोमाता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएँ, यही मेरी आप सबके चरणों में विनय है । भगवान गोपाल हमें शक्ति दें । जिससे गोमाता की सेवा के लिए कुछ कर सकें । वस इतना ही मेरा विनय है ।

गोसम्बर्धन के लिए भी गोहत्या निषेध कानून अनिवार्य

लेखक—लाला हरदेवसहाय

आज के कांग्रेसी क्या कहते हैं ?

प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी सज्जन अब भी गोहत्या बन्द करने का आन्दोलन होता है तब कानून द्वारा गोहत्या निषेध का विरोध करते हुए गोसम्बर्धन, गोपालन द्वारा गोवंश की उन्नति से ही गोवध की समस्या का हल करने की बात कहते हैं। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने ३ मार्च १९५१ को हिसार की पञ्च-अवसानी में भाषण करते हुए गोहत्या निषेध का समर्थन किया, पर १९५४ की गोपाष्टमी के सन्देश में राष्ट्रपति जी ने भी गोसम्बर्धन गोपालन की ही बात कही। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित गोसेवा संघ ने सम्पूर्ण गोवधबन्दी की नीति को स्वीकार किया। पर फिर भी गोसेवा संघ की अध्यक्ष श्रीमती जानकी देवी जी वजाज कुछ दिनों से श्री नेहरू जी के पक्ष का समर्थन तथा गोहत्या निषेध कानून का विरोध करते हुए कहती है, यदि कानून द्वारा गोहत्या बन्द हो गई तो गायों की और भी बुरी दशा होगी, अतः लोग गोहत्या निषेध के लिए आन्दोलन न करके गोसम्बर्धन गोपालन करे, गोसदन खोलें। श्रीमती मीरा बहन भी ऐसी ही बातें कहती हैं।

उपरोक्त सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि गोहत्या निषेध आन्दोलन को ठेस पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोग भी गोसम्बर्धन के नाम से जनता से भ्रम फैला रहे हैं इस भ्रम को दूर करने के लिए वास्तविक स्थिति जनता के सम्मुख रखना अत्यन्त आवश्यक है।

गोसम्बर्धन के लिए भी गोहत्या निषेध अनिवार्य

जिस प्रकार छिद्र के पात्र में पानी डालने से समय और परिश्रम बेकार जाता है उसी प्रकार जब तक गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द न होगी, तब तक गोसम्बर्धन गोपालन से गोवंश की स्थाई उन्नति न होगी।

संसार के प्रगतिशील कहलाने वाले अमेरिका, इंग्लैंड, रूस इत्यादि देशों में समस्याओं के निर्णय का आधार विधेयों की सम्मति तथा देश का संविधान है। भारत सरकार की गोरखा तथा उन्नति कमेटी १९४७-४८ ने निम्नलिखित सम्मति दी—

भारत में किसी अवस्था में भी गोहत्या वांछित नहीं है। यह कानून के द्वारा बन्द हो। भारत की समृद्धि बहुत कुछ उसके गोधन पर निर्भर है और राष्ट्र की आत्मा को तब ही सुन्नोप होगा जब गोवंश की हत्या सम्पूर्णतया बन्द कर दी जावेगी।

केन्द्रीय सरकार की इस समिति में सरकारी विधेयक तथा कांग्रेस विचार धारा के लोग, जिनमें में भी एक था। आज कांग्रेसी सज्जन, जनसंघ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद् इत्यादि जिन्हें साम्प्रदायिक संस्था कहते हैं उनका एक भी सदस्य नहीं था। देश की सब से बड़ी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने ८ अप्रैल १९५३ को डाक्टर सर सीताराम जी की अध्यक्षता में गोसम्बर्धन जाच कमेटी बनाई। इस कमेटी में श्री अहमद सैयदखान नवाब छत्तारी (जो अंग्रेजी राज्य के समय इस प्रान्त के गवर्नर थे) अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो० मोहम्मद हबीब, श्री अस्तर हसन सदस्य लोकसभा, ये तीन मुसलमान, श्री एन. जे. मुकर्जी एक ईसाई शेप कांग्रेसी या समाजवादी कुल २१ सदस्य थे। इस समिति ने ७ अप्रैल १९५४ को गोहत्या सम्पूर्णतया कानून द्वारा बन्द करने तथा गोहत्याओं को कड़ा दंड देने की सिफारिश की।

भारतीय संविधान की धारा ४८ में—

“गायों, बछड़ों, बछड़ियों, हल गाड़ी चलाने वाले तथा अन्य सब दुधार पशुओं की हत्या बन्द करना राज्य की नीति निर्धारित की गई।”

श्री नेहरू जी की प्रधानता में बनी पंचवर्षीय योजना कमेटी की सुपरेखा जुलाई १९५१ में प्रकाशित हुई। उसमें अनुपयोगी, कहे जाने वाले

पशुओं को कत्ल न करके गोसदनों में रखने की वास्तव निम्नलिखित सुझाव दिया—

“गोवंश की साधारण हत्या से इस समस्या (यानी अनुपयोगी गोवंश की समस्या) पर कोई अच्छा प्रभाव न पड़ा। अनुपयोगी पशुओं की एक साथ हत्या करना भी अमल में नहीं आ सकता। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिये, एक उपाय है उन स्थानों में जहाँ आज चारा काम में नहीं आता वहाँ वृद्ध और अपंग पशुओं को रखने के लिए गोसदन खोलना।”

केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश की विशेषज्ञ समितियों और भारतीय विधान की धारा ४८ में गोसम्बर्धन कार्यों के साथ-साथ कानून द्वारा गो-हत्या बन्द करने की सिफारिश की। श्री नेहरू जी की प्रधानता में बनी पंचवर्षीय योजना कमेटी ने भी गोवंश को कत्ल न करके उन्हें गोसदनों में रखने का सुझाव दिया। इन सब तथ्यों से केवल गोसम्बर्धन नहीं गोहत्या निषेध भी आवश्यक और अनिवार्य है।

उपयोगी पशुओं की हत्या

आज देश में कसाई वृद्ध और अपंग ही नहीं, पशु डाक्टर को रिश्वत देकर या घरों और जंगलों में या चोरी से सर्वप्रथम अच्छे पशुओं को ही कत्ल करने की कोशिश करता है। क्योंकि कसाई को अच्छे बछड़ा, बछड़ी तथा नौजवान गाय-बैल के कत्ल से शत-प्रतिशत तथा अपंग वृद्ध पशु के वध से १५-२० प्रतिशत ही लाभ पहुँचता है। अतः कसाई सर्व प्रथम उपयोगी नौजवान गोवंश को ही कत्ल करता है। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू, सन्त विनोबा भावे तथा सब ईमानदार पशु विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं कि देश में उपयोगी पशुओं की विशेषतया नौजवान दुधार गायों की हत्या होती है। श्री नेहरू जी के विचारों के समर्थक श्रीमती मीरां बहन ने

तो यह भी स्वीकार किया है कि कसाई जहाँ तक हो सके अच्छे पशु का ही कतल करता है। उपयोगी पशुओं का वध वन्द करने की कोशिश गत ११ वर्ष से हो रही है। बंगाल, बम्बई, हैदराबाद में उपयोगी पशु-वध निषेध कानून भी बने हैं। पर यह कानून एक भी उपयोगी पशु को कतल से नहीं बचा सके। इस कानून का लाभ पशुधन तथा राष्ट्र को नहीं बल्कि पशु विभाग या पुलिस को पहुँचा है जिन्हें कसाई ने रिश्वत देकर या चोरी से अच्छे पशु कतल किये। पशु विभाग के लोग उपयोगी पशु को अनुपयोगी लिखने के लिये लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं और इसी कारण जब भी सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी का प्रश्न उठता है पशु-विभाग के प्रायः अधिकारी सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करते हुये केवल मात्र उपयोगी पशुओं का वध वन्द करने का ही समर्थन करते हैं। यह सिद्ध है कि जब तक गोहत्या सम्पूर्णतया वन्द नहीं होगी प्रायः करके उपयोगी गोवंश का वध ही होगा। जब उपयोगी गोधन का कतल जारी रहे अच्छी नसल के बछड़े, बछड़ी तो जवान गाय कतल होती रहें तो गोसम्बर्धन और गोपालन के द्वारा जो भी अच्छी नसल के पशु तैयार होंगे वह पशुधन की उन्नति में लाभदायक न होकर कसाई तथा सरकारी पशु-विभाग के रोजगार को ही बढ़ावेंगे। गोसम्बर्धन का लाभ राष्ट्र को नहीं आज कसाई या पशुविभाग को ही पहुँच रहा है भविष्य में भी पहुँचेगा। मछली, मुर्गी, सूअर की तरह गोवंश की उन्नति शीघ्रता से नहीं होती। गाय की नसल तैयार करने में कम से कम दस साल लगते हैं। अतः गोधन की स्थाई उन्नति आवश्यक है और इस स्थाई उन्नति के लिये भी गोहत्या सम्पूर्णतया वन्द करनी आवश्यक है।

गोसम्बर्धन आदि से गोहत्या वन्द नहीं हो सकती।

डैनमार्क, हालैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि जिन देशों में वर्षों से गोसम्बर्धन गोपालन का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है सरकार और जनता ने करोड़ों रुपया पशु उन्नति के कार्यों पर खर्च किया। वहाँ गोवंश की

उन्नति भी हुई है पर गोहत्या भारत से भी अधिक होती है क्योंकि उन देशों से वैज गेती क काम नहीं आने अतः कतल ही होने है । गाय भी जब कम दूध देती है तब कतल कर दी जाती है । अतः यह सिद्ध है कि गोसम्बर्धन गोपालन से गोहत्या बन्द नहीं हो सकती । कुछ लोग गाय का दूध, घी तथा ग्रहिंसक चमड़े का व्यवहार करने से ही गोहत्या निरोध की समस्या का हल ढतलाते हैं । इसका उपयोग करना चाहिए पर यूरोप अमरीका आदि में सब लोग गाय के दूध घी का ही व्यवहार करते हैं पर गोहत्या बन्द नहीं । है तो यह असम्भव पर यदि देश के सब लोग भी ग्रहिंसक चमड़े का व्यवहार करने लगे तो भी गोहत्या बन्द नहीं हो सकती । देश से अस्सी लाख से अधिक कतल किये गाय बछड़ों के चमड़ों का निर्यात हो रहा है उसके लिए तो गोहत्या होगी ही । यह दलाल केवल मात्र गोहत्या निरोध आन्दोलन को ठेस पहुंचाने के लिए ही दी जाती है । गाय के दूध घी प्रौर ग्रहिंसक चमड़े का व्यवहार करने से गोहत्या बन्द नहीं हो सकती । राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल जी तथा अन्य मन्त्री महोदय गोसम्बर्धन गोपालन की बात करते हैं पर वह इंग्लैंड के बादशाह, अमरीका के प्रेसीडेंट तथा अन्य प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के बड़े लोगों की तरह गोपालन से स्वाभाविक दिलचस्पी नहीं रखते हैं । अतः जनता से भी गोपालन के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं होगा ।

भारत सरकार गोवश की उन्नति के लिए दो पैसा प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च करती है । पर संसार के अन्य देश कम से कम एक रुपया प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च करते हैं । इंग्लैंड की सरकार ने १९३२ से १९३६ तक ४० करोड़ या पाँच रुपया प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च किये । अधिक खाद्य उत्पादन योजना पर हमारी सरकार ने ६५ करोड़ रुपया खर्च किया । पर खाद्यपदार्थों के उत्पादन के मुख्य साधन गोवश की उन्नति के लिए एक पाई भी नहीं दी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में २० अरब रुपया खर्च करने का निश्चय किया । जो पशुधन देश को २०

कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने से गोवध की दानन दुर्ग होती थी
 केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश की सरकारी समितियाँ तथा मनु विशेष
 और गांधी जी का गोभेषा संघ सम्पूर्ण गोहत्या विधेय का मुद्रा लभ
 देता । यदि सरकार बुद्धिमानों से काम ले तो जैसा कि श्री नेहरू जी
 अध्यक्षता में बनी पंचवर्षीय योजना समिति ने स्वीकार किया है कि गोवध
 की हत्या न कर के देश के उन भागों में जहाँ प्रायः घरों में गोवध
 चारा व्यर्थ जाता है, गोसदन खोले जायें । सरकारी नियोजनों के अनुसार
 गोसदन में रखा जाने वाली एक गाय पर अधिक से अधिक ११ रुपये
 वार्षिक खर्च होंगे । प्रतिवृत्त सरकारी नियोजन श्री नेहरू के अनुमानानुसार
 एक वर्ष भर में जो गोबर गोधून देनी है उस आद का मूल्य २३ करोड़
 है । अतः प्रथम तथा वृद्ध गाय भी लाभदायक है । यदि सरकार
 सरकारी नियोजनों की सम्मति के अनुसार ईमानदारी से आख्या करे तो
 कानूनन गोहत्या बन्द करने से न ही गोवध की दुर्दशा होगी और न ही
 सरकार पर अनुचित बोझ पड़ेगा । श्री नेहरू जी पणु विशेषज्ञ नरों ।
 संगार के अन्य प्रगतिशील देशों की तरह उन्हें सरकारी पणु विशेषज्ञों
 की समिति को मानते हुए गोहत्या बन्द करनी चाहिए । श्री नेहरू जी
 तथा उनके समर्थकों के विचार अनुसार यदि प्रथम और वृद्ध गायन का
 रखना राष्ट्र के लिए हानिकारक है तो श्री नेहरू जी तथा अन्य कांग्रेसी
 नेता जो बार-बार जनता को महात्मा गांधी जी के उपदेशों पर चलने के
 लिए कहते हैं उन्हें महात्मा गांधी जी के १७ जुलाई १९२७ के 'नव-
 जीवन' पत्र में लिखे आदेश के अनुसार एक एक प्रथम तथा वृद्ध गोवध
 के रखने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए । महात्मा गांधी जी लिखते हैं—
 “बाजार में विकने आने वाली तमाम गायें ज्यादा से ज्यादा
 कीमत दे कर राज्य खरीद ले । बूढ़े लूले लंगड़े और रोगी ढोरों की
 रक्षा राज्य को करनी चाहिये ।”
 यह सिद्ध है कि कानूनन गोहत्या बन्द करने से न ही गायों की दुरी
 अवस्था होगी और न सरकार पर अनुचित बोझ पड़ेगा । गांधी जी के

आदेशानुसार तो एक-एक वृद्ध तथा अशक्त गाय बैल के रखने की जिम्मेवारी सरकार पर ही है ।

क्या गोहत्या के जिम्मेवार हिन्दू हैं ?

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, रक्षा मन्त्री डा० कैलाशनाथ जी काटजू तथा प्रायः कांग्रेसी नेता कहते हैं हिन्दू गाय कत्ताई के हाथ वेचते हैं अतः हिन्दू ही गोहत्या के जिम्मेवार हैं । गोहत्या निषेध कानून के लिए आन्दोलन न करके हिन्दुओं को ही गाय न बेचने के लिए समझाना चाहिए । हिन्दू कमाव्यों के हाथ गाय न बेचें ता गोहत्या स्वयं बन्द हो जायेगी । कानून की आवश्यकता नहीं । यह ठीक है कि हिन्दुओं को कत्ताई के हाथ गाय नहीं बेचनी चाहिए । किन्तु ही हिन्दु आज भी नहीं बेचते । पर गोहत्या निषेध के लिए प्राचीन काल में जब घर-घर में गायें थीं चारे के लिए पर्याप्त गायन थे तब भी कानून और दंड ने ही गोहत्या बन्द करने का नियम गा अथर्व वेद में लिखा है—

यदि नो गां हंसि अथर्वं यदि पूनपम्
तं त्वा सीमेन विभ्यामो यथा नो असा अवीरहा ।

(अथर्ववेद ? । १६ । ४)

अर्थात् यदि तू हमारी गाय, घोड़े, तथा पुरुष का वध करेगा तो हम तुम्हें सीमे की गोली से बंध देंगे । जिनसे तू हमारे वीरों का वध न कर सके जैसा कि पं० मुन्दरलाल जी ने 'भारत में अंग्रेजी राज्य' पुस्तक के पृष्ठ १८८७ पर लिखा है—बाबर ने बहादुरशाह तक तीन सौ वर्ष के मुगल राज्य में गोहत्यारों की हाथ काट देने या गोली से मार देने का दण्ड दिया जाता था । हिन्दू राजाओं ने तो गोहत्या रोकने के लिए कारावास दंड देने का नियम बनाया ही । अंग्रेजी राज्य ने भी उपयोगी पशुओं का वध रोकने के लिए तीन वर्ष तक कैद करने की आज्ञा दी । आज कांग्रेस राज्य के समय मध्य प्रदेश, भोपाल, अजमेर में भी कानून बनाए गए तथा उत्तर प्रदेश व बिहार में कानून उपस्थित हैं । अतः यह

सिद्ध है कि वैदिक काल से आज तक गोहत्या कानून से ही बन्द हुई। भविष्य में भी कानून से ही बन्द होगी। गोहत्या निषेध का प्रश्न हिन्दू तथा मुसलमान का नहीं सारे राष्ट्र के लाभ का सवाल है। कितने ही मुसलमान बादशाहों ने भी गोहत्यारों को कड़ा दंड देने का नियम बनाया। पर आज के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं अपने राज्य में मुसलमान तथा अंग्रेजों से भी अधिक गोहत्या होने पर भी गोबध बन्द करने को तैयार नहीं। अतः सब हिन्दुओं को गोहत्या का जिम्मेवार बनाना ठीक नहीं। यदि गोहत्या निषेध का कानून बन जाए तो वृद्ध तथा अपंग गाय को कोई खरीदेगा ही नहीं, हिन्दू या मुसलमान के बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न न होगा। जब कोई बुराई या दोष समाज में आ जाता है वह कानून से ही बन्द होता है। इसीलिए भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दंड निश्चित है। आज तक सामाजिक सुधार महात्माओं, आप्तपुरुषों के उपदेश तथा प्रचार से ही हुए हैं कानून नहीं बने। आज की सरकार हिन्दू समाज की बुनियाद को उखाड़ने, व्यभिचार तथा गृह-कलह बढ़ाने वाले हिन्दू विवाह विधेयक तो बना रही है पर गोहत्या निषेध कानून बनाने के लिये तैयार नहीं। यह कहना कि जिस प्रकार कानून होने पर भी चोरी डाके पड़ते, कत्ल होते हैं कानून बनने पर भी गोहत्या बन्द न होगी यह ठीक नहीं। जिन राज्यों में कानून है, जहाँ की सरकार ईमानदारी से कानून पर अमल करती है वहाँ गोहत्या नहीं होती।

महात्मा गाँधी जी का सहारा

कुछ लोग यह कह कर कि गाँधी जी कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने के विरोधी थे अतः गोहत्या निषेध के लिए कानून न बने। गाँधी जी या कोई भी व्यक्ति कितने ही कार्य-स्थिति तथा प्रभाव के अनुसार करते रहे हैं-करेंगे। एक समय महात्मा गाँधी अंग्रेजी राज्य के सहायक थे, कुछ वर्ष बाद परिस्थिति से बाध्य होकर विरुद्ध हो गये। गाँधीजी

कहते थे पाकिस्तान मेरी नज़ाबत पर ही बनेगा पर जब वाक्य हुए पाकिस्तान स्वीकार किया। यह ठीक है कि जब जब गान्धीजी परिस्थितियों से मजबूर हुए या उन पर नाट्यवादीक सुनलमान नेताओं का प्रभाव पड़ा गोरक्षा के विषय में ऐसा बार्ने गढ़ हो जो उनके उहने वक्तव्यों के विरुद्ध थीं। महात्मा गान्धी जी की उपस्थिति में उनकी सम्मति में १२ फरवरी १९४६ को गोपुरा ने यह प्रभाव मान हुआ।

“हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अर्थ लावन की दृष्टि से नाथ, बैल या बछड़े का बध होना सर्वथा अनिष्ट है। इसलिये आज की विषम परिस्थिति में गोवंश का जो अतिथेक पूर्ण बध हो रहा है उस का ख्याल करके मन्त्रेक्षण आवश्यक लगभगता है कि बछड़े, बछड़ियों और उपयोगी गायें और बैलों का बध कानूनन तुरन्त रोक दिया जाये”।

गान्धी जी ने १७ जुलाई १९२७ के 'नवजीवन' पत्र में लिखा है कि “तमाम बूढ़े, बूने, लंग, और लोहा लोरी की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिए।” सिद्ध है कि गान्धीजी नव गांधन को कलन में बचाने का लक्ष सम्मुख रखते हुए उपयोगी पशुओं को कानूनन तथा बृद्ध अर्पण को सरकारी लक्ष पर रखने के पक्ष में थे कलन के पक्ष में नहीं।

गान्धी जी ने ६ सितम्बर १९२१ को लिखा, ‘निष्ठाकृत की लडाई को मैंने अपनाया है क्योंकि मैं देन रहा हूँ कि निष्ठाकृत की रक्षा द्वारा गाय को पूरी रक्षा होगी।’

२० अप्रैल १९२४ को लिखा “गोरक्षा के साथ हिन्दू मुसलमान की एकता का निकट सम्बन्ध है।”

२५ जनवरी १९२५ को लिखा, “मे मुसलमानों के लिए जहाँ तक हो सके दुख महन करने को तैयार हूँ। उनका कारण स्वराज्य मिलन की छोटी बात तो थी ही साथ ही गांधी का बचाने की बड़ी बात भी उस में थी।”

“हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के साथ रह कर गोवध करना हिन्दुओं का

खून करने के बराबर है। क्योंकि कुरान कहता है पापीयों का खून करने वाले को ज़रूर नहीं है।”

गांधी जी की उपरोक्त सब बातों का एक ही अर्थिजात है कि गांधी जी चाहते थे मुसलमान स्वयं गोहत्या करना छोड़ दें। यह भिन्न है कि गांधी जी के कोशिश करने पर भी मुसलमानों ने गोहत्या नहीं छोड़ी। महात्मा जी उन्हें न समझा सके। जैसा कि जी नाना कांग्रेसकर जी ने ‘बापू की भाँजियाँ’ पुस्तक के पृष्ठ ७२ पर लिखा है मद्रास कांग्रेस के समय १९२६ में जब हिन्दू मुस्लिम सम्मेलन का प्रश्न गांधी जी के दम्पुस आया तब मुसलमानों ने गोहत्या करने का अधिकार स्वीकार करना चाहा तो महात्मा गांधी जी ने यह कह कर कि मैं तो स्वराज्य के लिए भी गोरक्षा का प्रावर्ष नहीं छोड़ सकता, मुसलमानों ने सम्मेलन करने से इनकार कर दिया। इस ने प्रगट है कि गांधी जी गोहत्या करना मुसलमानों का अधिकार नहीं मानते थे।

महात्मा जी ने गोसेवा के कार्य को प्रगटि देने के लिए ‘नवजीवन’ पत्र के भूतपूर्व सम्पादक तथा गांधीवादी विद्वान् श्री आनन्द स्वामी जी को वर्धा बुला कर गोसेवा संघ के मन्त्री पद का भार सौंप दिया। गोसेवा संघ की विचार धारा पुस्तक के पृष्ठ १६ पर लिखा है, “जब सारी व्यवस्था में कुद्व महीने बीत गये, इतने में ही सन् १९४२ का दगस्त आन्दोलन आया। स्वामी आनन्द महसुन करने लगे कि हमारा वर्धों का नसल सुधार का काम यह विदेशी सरकार गायों को कतल करके भिन्दों में वर्वादि कर देती है, इसलिये सर्वप्रथम इसको हटाना ही गोसेवा है। इस विचार से वे आन्दोलन में भाग लेने के लिए बम्बई वापिस चले गये।” आज अंग्रेजी राज्य की अपेक्षा अधिक तथा अच्छी उपयोगी दुधार गायों की भी हत्या होती है। इस अवस्था में सरकार को हटाने का प्रश्न तो नहीं पर जब तक गोहत्या बन्द न हो श्री आनन्द स्वामी जी के विचारानुसार गोसेवा या रचनात्मक कार्य से विशेष लाभ नहीं। सक्रिय आन्दोलन से लाभ पहुँचेगा।

आज महात्मा गांधीजी नहीं पर आज की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री सत्य गिरीदा जी ने बिहार तथा मेठ गोविन्ददास जी के विधेयता का समर्थन करके कानून द्वारा गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करने की सम्मति दी है। महात्मा गांधी जी के बनाये गयेवां संघ ने भी कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने की नीति स्वीकार की है। यह ठीक है कि गोहत्या बन्द करने के बाद सारी शक्ति गोपालन गोसम्बर्द्धन तथा गायों का उत्पादन बढ़ाने आदि पर लगाई जावे। पर जो सज्जन कानून द्वारा गोहत्या बन्द न करके केवल मात्र गोसम्बर्द्धन गोपालन या केवल गायों के दुग्ध या आर्हिमक धमड़े के प्लूतों के प्रचार ने ही गोहत्या बन्द होने की बात कहते हैं वह ठीक नहीं। यह सब काम होने चाहियें, आवश्यक है। पर जब तक कानून द्वारा गोहत्या बन्द न होगी न गोपालन होगा न ही गोसम्बर्द्धन। दूध आदि के उत्पादन बढ़ाने का तो कहाँ डिकाना।

अधिक गोवंश तथा कन चारा

प्रायः कांग्रेसी नेता तथा सरकारी कर्म तथा पशु विभाग के सरकारी लोग, सरकारी विभागों की सम्मति प्राप्त होने पर भी गोवंश को नव्या आवश्यकता से अधिक तथा चारा कम बनना कर गोहत्या जारी रखने की अवैधानिक तथा असाधिकाय चेष्टा कर रहे हैं। कहा जाता है कि गाय धेवी गौ मनुष्य, दोनों नाथ-माय नहीं ब्रज सकते। उनकी यह बलीले भी तथ्यों तथा श्रुतियों के अनुसार ठीक नहीं।

क्या गोवंश आवश्यकता से अधिक है ?

अमरीका, कॅनेडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी इत्यादि संसार के प्रगतिशील गृहस्थाने वाले देशों में जिनके गोवंश की संख्या का भारत की पशु संख्या से मुकाबला किया जाता है, वहां खेती मशीनों या घोड़ों से होती है। पर भारत की खेती का आधार ही गोवध पर है। बैलों से हल

जैसा कि महात्मा गांधी जी ने मध्य प्रदेश को खाताऊ नसल को दुधार एवं उत्पादक बनाया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बजरंग बहादुर सिंह ने काजी हाऊस से प्राठ ग्राम में खरीदी प्रदुत्पादक तथा बंगाल के मुरशिदाबाद जिले के बलरामा इलाके के किसान ने अनुत्पादक बंगला गायों को नसल सुमार से उत्पादक या मानदायक बना दिया, उसी प्रकार सब अनुत्पादक कहलाने वाली गायें उत्पादक बनाई जा सकती हैं तथा प्राज भी सरकारी ईमानदार विभागों के मतानुसार तो लूलो-लंगड़ी गाय भी अनुत्पादक नहीं। ऊर्षि-महालय श्री गोमन्तन काँसिल के मतानुसार एक अनुयोगी पशु को गोमन्तन से रखने में नानरैकरिंग या एक बार छप्पर तार प्रादि लगाने का खर्च ५० रुपये तथा पुनः प्रति वर्ष १० रुपये खर्च होंगे। यदि एक वृद्ध गाय गोमन्तन अधिक से अधिक पाँच साल भी जीवित रहे तो १५ रुपये वापिस मिलेंगे। रुपि रासायनिक विशेषज्ञ डा० तैडर के मतानुसार एक मान वाषिक १२२ मन गोबर तथा ४० मन मूत्र देती है, इसका कुल्य वाषिक २६ रुपये होता है।

खादी प्रतिष्ठान के श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त तथा अन्य विशेषज्ञों ने गोबर गोमूत्र से खाद के गुण स्थायी रखते हुये भी रोझनी करने, नह्नी चलाने, पानी निकालने आदि के लिये गैस उत्पादन करने का यन्त्र तैयार किया है। यदि गोबर गोमूत्र का ठीक उपयोग किया जाय तो वृद्ध और अपग गाय वैल भी अनुत्पादक नहीं उत्पादक ही हैं। यदि प्राज गोवंश से पुरा लाभ नहीं उठाया जाता तो यह गाय का नहीं हमारा तथा हमारे विशेषज्ञों की अकर्मण्यता तथा अयोग्यता का दोष है।

चारे दाने की कमी का प्रश्न

यह ठीक है कि अव्यवस्था के कारण देश ही नहीं, प्रान्त के एक भाग में चारा अधिक होने से चारा खराब हो रहा है और दूसरे भाग में चारे की कमी से पशु भूखे रहते हैं। पर यदि सारे देश के चारे के उत्पादन का अनुमान किया जाये तो कमी नहीं। भारत सरकार की

पशु खाद्य सलाहकार कमेटी ने १९५०-५१ को पशु संख्या तथा १९५२-५३ के उत्पादन के अंकों को सम्मुख रखते हुए चारे देने की आवश्यकता, वर्तमान उत्पादन (प्राप्ति) इत्यादि के विषय में ८० करोड़ मन दूध उत्पादन के लक्ष्य को सम्मुख रख दाने-खली के खर्च का हिसाब लगाया था। पर वहाँ दूध के वर्तमान उत्पादन १८ करोड़ मन के हिसाब से दाना-खली का खर्च लगाया है। कमेटी ने मांस उत्पादन और मुर्गी पालन के लिए जो अन्न की आवश्यकता बनवाई थी वह भी इन अंकों में सम्मिलित नहीं की गई क्योंकि हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह मांस के लिए अन्न पशु नहीं रखे जाते और न ही भविष्य में आवश्यकता है। अंक इस प्रकार हैं। हिसाब लागू दोनों में है।

	आवश्यकता	प्राप्य	कमी	अधिक
कड़वी तथा मूत्रा चारा	१३८०	१३००	८०	०
हरा चारा खली से	२८६०	१११०	१७५०	०
हरा चारा जंगल में चरने से	२७६०	५२७०	००	२५१०
कुल जोड़ लाख टन	७०००	७६८०	२१६०	२५१०
दाना खली विनीला	२८६	१३८	१४८	

इस हिसाब से चारे की कमी नहीं २५० लाख टन अधिक है। दाना खली में अनुमान ५२ प्रतिशत कमी है। यह कमी १९५२-५३ के उत्पादन के हिसाब से है। १९५२-५३ की प्रवेष्टा १९५३-५४ में अन्न का उत्पादन ७० लाख टन तथा तेल के बीजों का उत्पादन १० लाख टन अधिक हुआ है। गुवार जो पशु के लिये अच्छा चारा-दाना है, कम से कम ५० लाख टन पैदा होता है। इस अन्न गुवार तथा तेल के बीजों से १७ प्रतिशत दाना खली प्राप्त होते हैं। अतः दाने-खली में अनुमान ३५ प्रतिशत कमी रह जाती है। इस कमेटी ने बैलों के लिये जो दाने का हिसाब लगाया है वह आज की आवश्यकता से अधिक है। छोटे बछड़े दाना नहीं खाते, दूध ही पीते हैं। प्रायः बछड़ों को दाना नहीं